20 जनवरी, 2023 * वर्ष 32, पृष्ठ संख्या 60, अंक-1

राजस्थान सुजस

मंथन का मंत्र : सशक्त लोकतंत्र
राजस्थान विधानसभा बनी साक्षी

माही महोत्सव, बांसवाड़ा

7 से 9 जनवरी के बीच बांसवाड़ा में परंपरागत माही महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव का आगाज कुशल बाग मैदान से शोभायात्रा से हुआ। लोक सांस्कृतिक दलों ने विभिन्न मनमोहक लोक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से लोकानुरंजन किया। घोड़े, ऊंट, बैलगाड़ी पर सवार होकर विभिन्न समाज के लोगों के साथ मथुरा से आए राधा-कृष्ण के कलाकारों ने भजनों से माहौल को आनंदमय बना दिया। महोत्सव में बांसवाड़ा के प्रसिद्ध जगमेरु हिल पर पैराग्लाइडिंग की गई। प्रकृति की वादियों के बीच आला बरोड़ा गांव के माही बैकवाटर एरिया में बर्ड फेयर भी हुआ। कुशल बाग मैदान में वागड़ को जानें, मटका दौड़, कुर्सी दौड़, मेहंदी, सतोलिया, रूमाल झपट्टा, साफा बांधना जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। मशहूर पुराधाम अरथूना देवालय समूह परिसर में शास्त्रीय संगीत और नृत्य निशा का आयोजन हुआ। सांस्कृतिक संध्या पर मशहूर सैलेब्रिटी ने अपनी परफोर्मेन्स दी। महाराणा प्रताप सेतु पर नौकायन व माही पूजन का कार्यक्रम हुआ।

आलेख व छाया: कल्पना डिंडोर, सहायक निदेशक, जनसम्पर्क

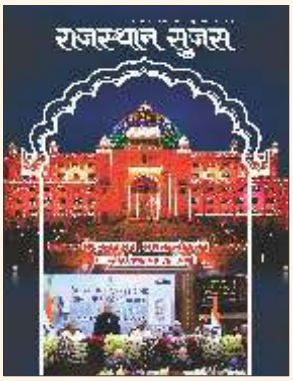

प्रधान सम्पादक
पुरुषोत्तम शर्मा

सम्पादक
अलका सक्सेना

सह-सम्पादक
डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा

उप-सम्पादक
सम्पत राम चान्दोलिया
आशाराम खटीक

सहायक सम्पादक
महेश पारीक

राजस्थान सुजस में प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचार लेखकों के अपने एवं आंकड़े परिवर्तनशील हैं। आवश्यक नहीं कि शासन उनसे सहमत हो। सुजस में प्रकाशित सामग्री का विभाग किसी भी रूप में उपयोग कर सकेगा।

ग्राफिक डिजाइनिंग
कृष्णा प्रिंटर्स

सम्पर्क
सम्पादक
राजस्थान सुजस (मासिक)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
सचिवालय, जयपुर-302005
मो. नं. 98292-71189
94136-24352
e-mail :
editorsujas@gmail.com
publication.dipr@rajasthan.gov.in
Website :
www.dipr.rajasthan.gov.in

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान का मासिक

वर्ष : 32 अंक : 1 | जनवरी, 2023

इस अंक में

लोक जीवन	02
सम्पादकीय	04
खेती से बढ़ी आमद, अन्नदाता खुशहाल	35
सुजस ऐप	36
सफलता की कहानी	38
हत्सशिल्प उत्सव	42
एमएसएमई नीति	44
राजस्थान हस्तशिल्प नीति	46
निवेश के लिए एमओयू	48
RAJIV GANDHI SCHOLARSHIP	49
जनजाति क्षेत्र विकास	50
जन सूचना पोर्टल	52
केसरी सिंह बारहठ पेनोरमा	54
देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना	56
पालनहार योजना	57
राजस्थान जन आधार योजना	58
धरोहर	59
तब और अब	60

राज्य सरकार के 4 वर्ष

05

18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी

21

बातचीत

28

फोटो फीचर

30-31

राजस्थान सुजस के आगामी अंक के लिए मौलिक, अप्रकाशित सामग्री भिजवायें। कृपया अपने आलेख एवं फोटोग्राफ सम्पादक को e-mail : editorsujas@gmail.com पर अथवा डाक से भेजें।

पीठासीन अधिकारी सम्मेलन

14

राज्य सरकार का चिंतन शिविर

24

अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव

32

नया वर्ष, नया उल्लास

नया साल हम सबके लिए नई उमंग, नया उत्साह और नए संकल्प लेकर आया है। साथ ही, बसंत ऋतु का शुभागमन हो चुका है। आशाओं की नव कोपलें प्रस्फुटित हो रही हैं और चहुंओर खुशियों के पुष्प पल्लवित हो रहे हैं। यह खुशनुमा मौसम हमें जीवन को नई दिशा देने के लिए प्रेरित करने वाला है।

नया साल और नया बसंत राजस्थान के लिए कई सौगातें लेकर आया है। हमारा प्रदेश हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, जो हम सबके लिए गौरव का विषय है। समन्वित प्रयासों से हमारे प्रदेश ने 11.04 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर हासिल कर समग्र और समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया है।

नए साल के पहले माह में राजस्थान विधानसभा में 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, 67 वर्ष बाद पाली के रोहट में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट-गाइड जम्बूरी तथा राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मू के कर-कमलों से राजभवन में देश के पहले संविधान उद्यान का लोकार्पण जैसे आयोजन गौरवान्वित करने वाले हैं।

राज्य विधानसभा में बजट सत्र प्रारम्भ हो चुका है। आगामी माह में प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने तथा युवा कल्याण पर केंद्रित राज्य बजट प्रस्तुत होगा। मैं आशान्वित हूं कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों और सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रदेश प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर होगा।

नए वर्ष में राजस्थान सुजस का पहला अंक आपके हाथों में प्रस्तुत करते हुए हार्दिक प्रसन्नता है। आप सबको नववर्ष एवं उल्लास भरे बसंत की ढेरों शुभकामनाएं।

(पुरुषोत्तम शर्मा)
प्रधान सम्पादक

राज्य सरकार ने लिए एक से बढ़कर एक जनकल्याणकारी फैसले

राज्य सरकार के चार वर्ष की विकास प्रदर्शनी

राज्य सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जवाहर कला केंद्र में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की ओर से पांच दिवसीय राज्यस्तरीय विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 18 दिसंबर से दौसा जिले के सिकन्दरा में भी दो दिवसीय विकास प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इसके अलावा इस अवसर पर जिला स्तर पर भी अलग-अलग प्रदर्शनियां आयोजित कर आमजन को राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतिगत फैसलों की जानकारी उपलब्ध करवाई गई। प्रदर्शनी में चार वर्ष में विभिन्न विभागों द्वारा अर्जित उपलब्धियों को भी प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी में विद्यार्थियों, महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं सहित विभिन्न लोककल्याणकारी योजनाओं को लेकर भारी उत्साह नजर आया।

जन सेवा, सबका सम्मान, आगे बढ़ता राजस्थान

जवाहर कला केंद्र में 5 दिवसीय राज्यस्तरीय विकास प्रदर्शनी

राज्य सरकार के चार वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 से 21 दिसंबर तक जवाहर कला केंद्र, जयपुर में ''जनसेवा, सबका सम्मान, आगे बढ़ता राजस्थान'' राज्यस्तरीय विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में राज्य सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग सहित विभिन्न विभागों द्वारा 25 स्टॉल लगाकर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विभागीय कार्य प्रणाली तथा नवाचारों की जानकारी दी गई। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के समन्वय से लगाई गई इस प्रदर्शनी में कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, सहकारिता विभाग, आरसीडीएफ (डेयरी), गौपालन विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, श्रम एवं नियोजन, सार्वजनिक निर्माण, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, आयोजना, राजस्थान आवासन मंडल, नगरीय विकास विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण, स्वायत्त शासन, नगर निगम जयपुर-हेरिटेज, नगर निगम जयपुर-ग्रेटर, सूचना एवं जनसंपर्क, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उद्योग, ऊर्जा, गृह, वन, पर्यटन सहित अन्य विभागों द्वारा चार साल में लिए गए फैसलों, विकास

अरुण जोशी
अतिरिक्त निदेशक, जनसंपर्क

कार्यों, योजनाओं एवं उपलब्धियों का आकर्षक ढंग से प्रदर्शन किया गया। पांच दिवसीय प्रदर्शनी में हजारों की संख्या में आगंतुकों ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉल्स का अवलोकन कर राज्य सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम, महत्त्वपूर्ण निर्णय एवं उपलब्धियां, जन-घोषणा पत्र क्रियान्विति रिपोर्ट एवं सफलता की कहानियां आदि साहित्य नि:शुल्क प्राप्त किए।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 17 दिसंबर को जवाहर कला केंद्र में आयोजित राज्यस्तरीय विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने 25 विभागों की स्टॉल्स पर जाकर विभागों द्वारा करवाए गए विकास कार्यों, उपलब्धियों एवं नवाचारों का अवलोकन किया। श्री गहलोत ने सभी विभागीय अधिकारियों को योजनाओं के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाकर अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री परसादी लाल मीणा, आपदा प्रबंधन मंत्री श्री गोविंद राम मेघवाल, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत, अल्पसंख्यक मामलात मंत्री श्री शाले मोहम्मद, सूचना एवं जनसंपर्क राज्य मंत्री श्री अशोक चांदना, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग, पूर्व शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री सलाहकार श्री संयम लोढ़ा, मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा, पुलिस महानिदेशक श्री उमेश मिश्रा सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने 'सेवा ही कर्म, सेवा ही धर्म' का संदेश देती विकास प्रदर्शनी में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में विभिन्न क्षेत्रों में करवाए गए विकास कार्यों एवं योजनाओं के फोटो, स्कैच, मॉडल्स एवं प्रकाशन सहित अन्य सामग्री को देखा। श्री गहलोत ने कृषि विभाग की स्टॉल पर ऋण माफी के लाभार्थी किसानों से संवाद किया। साथ ही प्रगतिशील किसानों से मुलाकात कर उनके नवाचारों को सराहा। प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री ने सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के सुजस ऐप, सुजस बुलेटिन, सुजस ई-बुलेटिन एवं सुजस पॉडकास्ट 'आवाज' का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी स्थल पर बने सुजस स्टूडियो से प्रदेशवासियों के नाम सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर वीडियो संदेश भी रिकॉर्ड किया। उन्होंने परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की स्टॉल पर दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों की जान बचाने के लिए दिए जाने वाले प्रशिक्षण का लाइव डेमो देखा। उन्होंने प्रदर्शनी में लगाये गए मोबाइल स्टूडियो में 7-डी सिनेमा का भी अवलोकन किया। प्रदर्शनी के दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष स्कूली छात्राओं ने राज्य सरकार की ओर से उनको सिखाए आत्मरक्षा के गुण का प्रदर्शन किया।

चुनावी घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज बनाकर वादों को किया पूरा

राज्यस्तरीय विकास प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर अपने

उद्बोधन में श्री गहलोत ने कहा कि हमने चुनावी घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज बनाकर वादों को पूरा किया है। हमने जनता की भावनाओं के अनुरूप जन-घोषणा पत्र बनाया, जिसे आधार बनाकर नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन का कार्य किया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा के लिए लगभग 1 करोड़ लोगों को पेंशन दी जा रही है। आईटी का इस्तेमाल करते हुए प्रदेश में एक जवाबदेही और पारदर्शी सुशासन स्थापित करने का कार्य राज्य सरकार ने किया है। भ्रष्ट कार्मिकों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इंदिरा रसोई योजना में आमजन को 8 रुपये में सम्मान के साथ पौष्टिक भोजन परोसा जा रहा है। प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं के माहवारी स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए 800 करोड़ रुपये की 'उड़ान योजना' के माध्यम से नि:शुल्क सेनेटरी नैपकिन का वितरण किया जा रहा है। सरकार की योजनाओं से आज 46 लाख घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों का बिजली बिल शून्य आ रहा है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों को राहत दी जा रही है।

चिरंजीवी योजना से मिल रहा नि:शुल्क उपचार

मुख्यमंत्री के अनुसार राज्य सरकार की प्रत्येक योजना के केन्द्र में गरीब एवं वंचित लोग हैं। आमजन को महंगे उपचार से मुक्ति दिलाने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की है। इसमें 10 लाख रुपये तक का नि:शुल्क उपचार मिल रहा है। किडनी, हार्ट, लीवर

ट्रांसप्लांट जैसे महंगे इलाज में 10 लाख रुपये की सीमा समाप्त कर सारा खर्च राज्य सरकार वहन कर रही है। साथ ही, 5 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा आईपीडी, ओपीडी में सभी प्रकार के उपचार नि:शुल्क कर दिए गए हैं। प्रदेश में आमजन की सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन जैसी महंगी जांचें नि:शुल्क की जा रही हैं। इन ऐतिहासिक निर्णयों से राजस्थान स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मॉडल स्टेट बनकर उभरा है।

मानवीय दृष्टिकोण से लागू की ओपीएस

राज्य सरकार ने प्रदेश में मानवीय दृष्टि से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू किया। राज्य का वित्तीय प्रबंधन बेहतरीन रहा है, जिससे प्रदेश में सभी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। केंद्र सरकार भी ओपीएस लागू करे ताकि कार्मिकों में भविष्य के प्रति सुरक्षा की भावना आए। हमारी सोच सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की है।

ईआरसीपी महत्त्वपूर्ण परियोजना

राज्य के 13 जिलों में आमजन और किसानों के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इस योजना से राजस्थान के एक बड़े क्षेत्र में पेयजल व सिंचाई जल की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। अनावश्यक देरी से परियोजना की लागत बढ़ेगी व प्रदेशवासी परियोजना के लाभ से वंचित होंगे। गत बजट में राज्य सरकार द्वारा ईआरसीपी के लिए 9,600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा न मिलने तक राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से इसे आगे बढ़ायेगी।

राजस्थान में हुआ शानदार कोरोना प्रबंधन

कोरोनाकाल में बेहतरीन चिकित्सा प्रबंधन के जरिए राजस्थान पूरे देश में अग्रणी रहा। कोरोना महामारी के सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए 'भीलवाड़ा मॉडल' की पूरी दुनिया में सराहना हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने राजस्थान की तारीफ की। प्रदेश के हर चिकित्सालय में ऑक्सीजन, आवश्यक दवाइयों और बेड्स की अतिरिक्त व्यवस्था की गई। इसी का परिणाम रहा है कि अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान में मृत्युदर काफी कम रही। 500 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंस की गईं, जिनमें ग्राम पंचायत स्तर तक के सदस्य जुड़े। दवाइयों एवं चिकित्सा उपकरणों के प्रबंधन, लॉकडाउन के दौरान रोजगार खोने वाले मजदूर वर्ग, ठेले-रेहड़ी वालों का सर्वे किया गया। इस दौरान लाखों लोगों के खातों में आर्थिक सहयोग राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई।

सूचना और जनसम्पर्क विभाग

प्रदर्शनी में सूचना और जनसम्पर्क विभाग की स्टॉल पर लोगों में राज्य सरकार की लोककल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों की जानकारी प्राप्त करने के प्रति जिज्ञासा एवं दिलचस्पी देखने को मिली। स्टॉल पर आगंतुकों को राज्य सरकार के स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम, महत्त्वपूर्ण निर्णय एवं उपलब्धियां, जन घोषणा पत्र क्रियान्विति रिपोर्ट एवं सफलता की कहानियां आदि साहित्य नि:शुल्क उपलब्ध करवाया गया। विजिटर्स यहां सुजस वीडियो बुलेटिन स्टूडियो के माध्यम से लाइव एकरिंग के रोमांच से भी रूबरू हुए। यहां क्विज एवं पजल गेम्स के माध्यम से रोचक तरीके से सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान

की गई। 'आओ खेलें खेल, सब मिल हो जाएं एक' पजल गेम बच्चों और युवाओं में खासा लोकप्रिय रहा। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर आधारित इस जिग्सा पजल गेम को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा भी सराहा गया। विद्यार्थियों एवं युवाओं में सरकारी योजनाओं पर आधारित क्विज कॉम्पटिशन को लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आया। प्रदर्शनी में हर वर्ग और हर उम्र के लोगों की भागीदारी देखने को मिली। 18 दिसंबर को स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ ही राजीविका से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर राज्य सरकार की योजनाओं एवं विकास कार्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। राजीविका से जुड़ी महिलाओं के समूह ने सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की स्टॉल पर उपलब्ध साहित्य प्राप्त किया और वहां मौजूद विभाग की टीम से संवाद कर राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया। ये ग्रामीण महिलाएं सुजस वीडियो बुलेटिन निर्माण की प्रक्रिया को जानकर रोमांचित हुईं।

आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग

प्रदर्शनी में आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग की स्टॉल पर विगत चार वर्ष में विभाग की ओर से शुरू की गई महत्त्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी प्रदर्शित की गई। प्रदर्शनी में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जन आधार, पहचान, बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर, सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) राजीव गांधी युवा मित्र और यंग इंटर्न प्रोग्राम सहित अन्य योजनाओं की जानकारी दी गई। जन आधार सरकार की ऐसी महत्त्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक डिजिटल तरीके से सुगमतापूर्वक पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश में अब तक करीब 1 करोड़ 94 लाख परिवारों का जन आधार नामांकन किया जा चुका है। इस योजना से करीब 7 करोड़ 54 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अब तक लगभग 51 हजार 728 करोड़ से अधिक की नकद राशि इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की गई है। साथ ही 70 लोक कल्याणकारी योजनाओं एवं 33 सेवाओं का लाभ जन आधार के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है। राज्य सरकार ने बिजनेस रजिस्ट्रेशन मोबाइल ऐप भी शुरू किया है। इसके माध्यम से राज्य में संचालित आर्थिक गतिविधियों एवं इकाइयों को विशिष्ट पहचान संख्या जारी की जा रही है। अब तक करीब 13 लाख बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किए जा चुके हैं। इसी प्रकार 'पहचान' पोर्टल एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन का कार्य सरलता से हो रहा है। अब यह कार्य पूरी तरह ऑनलाइन किया जा रहा है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की स्टॉल पर विभाग की योजनाओं और विकास कार्यों के साथ महात्मा गांधी नरेगा योजना के संबंध में फिल्म, मॉडल और स्टेण्डीज के माध्यम से जानकारी प्रदान की गई। महात्मा गांधी नरेगा योजना किस तरह गांव में रोजगार उपलब्ध करवाकर ग्रामीण जन का आर्थिक सम्बलन कर रही है और स्थायी परिसम्पतियों के निर्माण से गांव में सकारात्मक परिवर्तन ला रही है, इसे दर्शाते हुए एक मॉडल प्रदर्शित किया गया। विभाग द्वारा तैयार मॉडल में ग्राम पंचायत में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत होने वाले विकास

कार्यों को दर्शाया गया। इसमें बताया गया कि योजना के तहत नवीन ग्राम पंचायत, खेल मैदान, आंगनबाड़ी केंद्र, श्मशान घाट, चारागाह विकास, ग्रेवल सड़क, सीसी सड़क, पुलिया निर्माण, खाद्य गोदाम, मॉडल तालाब आदि कई प्रकार के ग्राम की मूलभूत आवश्यकता से संबंधित विकास कार्यों को पूर्ण कर ग्राम विकास की नई दिशा तय की जा रही है।

प्रदेश में मनरेगा में पिछले 4 वर्ष में 13 लाख 58 हजार कार्य पूर्ण किए गए, जिन पर 31 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि खर्च हुई है। राजस्थान में मनरेगा पिछले तीन वित्तीय वर्ष से लगातार मानव दिवस सृजन एवं 100 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों के मामले में देशभर में अव्वल है। पंचशाला के नवाचारों के रूप में प्रदेश में 52 हजार 534 से अधिक पशुशाला, 13 हजार 600 से अधिक पोषणशाला, 1,570 से अधिक पौधशाला, 350 से अधिक कार्यशाला एवं 35 निर्माणशाला का निर्माण मनरेगा के अन्तर्गत किया गया। प्रदर्शनी में अमृत सरोवर, खेल मैदान विकास, नर्सरी निर्माण, मॉडल तालाब एवं संपर्क सड़क के कार्यों का चित्रात्मक प्रदर्शन किया गया। साथ ही जलग्रहण क्षेत्र विकास मॉडल, पंचायती राज के कार्य और राजीविका के महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों एवं उपलब्धियों का प्रदर्शन भी इस स्टॉल पर किया गया।

सहकारिता विभाग

जवाहर कला केंद्र में राज्यस्तरीय विकास प्रदर्शनी में सहकारिता विभाग की स्टॉल पर सहकारिता विभाग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी विस्तृत रूप से उपलब्ध करवाई गई। साथ ही विभिन्न सहकारी संघों द्वारा अपने उत्पादों को भी प्रदर्शित किया गया है। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (कॉनफेड) द्वारा स्टॉल पर शुद्ध रूप से तैयार किए गए उपहार ब्राण्ड के मसालों और अर्गेनिक उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। यहां राजफेड एवं तिलम संघ द्वारा भी अपने उत्पाद प्रदर्शित किए गए। वहीं ग्राम सेवा सहकारी समिति स्तर पर स्थापित कस्टम हायरिंग सेंटर्स की जानकारी भी स्टॉल का खास आकर्षक रहा। स्टॉल पर राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड द्वारा

अपनी ऋण योजनाओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई गई। प्रदर्शनी में आगंतुकों को विभाग की योजनाओं एवं उपलब्धियों से संबंधित साहित्य नि:शुल्क उपलब्ध करवाया गया।

महिला एवं बाल विकास विभाग

प्रदर्शनी में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्टॉल पर उड़ान योजना के तहत किशोरियों एवं महिलाओं को प्रतिमाह नि:शुल्क वितरित किए जा रहे 12 सैनेटरी नैपकिन के बारे जानकारी दी गई। उल्लेखनीय है कि बजट घोषणा 2020-21 की पालना में शुरू की गई इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना राज्य के टीएसपी क्षेत्र के पांच जिलों में सफलता प्राप्त करने के बाद मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा वर्ष 2022-23 में इस योजना का विस्तार करते हुए इसे राज्य के सभी जिलों में लागू करने की बजट घोषणा की गई। जिसे 1 अप्रैल 2022 से संपूर्ण प्रदेश में लागू किया गया। इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इससे जुड़ी तमाम जानकारियां विभाग की स्टॉल पर दी गई। इसके साथ ही समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय की ओर से पोषाहार कार्यक्रम के तहत बच्चों को दिए जाने वाले पोषाहार और बच्चों के ईसीसीई शिक्षा कार्यक्रम की जानकारी भी स्टॉल पर दी गई।

प्रदर्शनी में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्टॉल पर महिलाओं के लिए आई एम शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, आई एम शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना, इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना, महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना, वन स्टॉप सेंटर/सखी केन्द्र, जागृति बैक टू वर्क योजना, मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम- जॉब वर्क योजना, इंदिरा महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान, राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 से जुड़ी बारीकियां विभाग की टीम ने आगंतुकों को समझाई।

कृषि विभाग

कृषि विभाग की स्टॉल पर प्रदर्शित ड्रोन लोगों में जिज्ञासा का खास केंद्र बना। यहां विभागीय टीम ने लोगों को ड्रोन द्वारा कीटनाशक

के छिड़काव और जमीन की मैपिंग के तरीकों के बारे में जानकारी दी। प्रदर्शनी में कृषि विभाग की स्टॉल पर विभिन्न जिलों से प्रगतिशील किसानों द्वारा लाए गए उत्पाद भी प्रदर्शित किए गए। इनमें कोटा से श्री नरेन्द्र द्वारा लाए गए सरसों व अजवाइन का शहद, श्रीगंगानगर के किसान श्री ओमप्रकाश के अंजीर के उत्पाद, जोबनेर के कृषक श्री गंगाराम सेपट की जैविक सब्जियां और स्ट्रॉबेरी, जालौर से किसान श्री बेना राम द्वारा तैयार ऑर्गेनिक अनार और सीकर से श्री राजकुमार की उपज मशरूम व अन्य खाद्य पदार्थों में आगंतुकों ने खास रुचि दिखाई।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग

राज्यस्तरीय विकास प्रदर्शनी में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की स्टॉल पर भारी संख्या में आए आगंतुकों ने मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, मिशन निर्यातक बनो, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना सहित विभिन्न योजनाओं और नवाचारों की जानकारी ली। आगुंतकों ने राजस्थान हैंडलूम कॉर्पोरेशन, खादी विभाग द्वारा प्रदर्शित उत्पादों को सराहा। प्रदर्शनी में युवा उद्यमियों ने भी बड़ी तादात में शिरकत की। कई युवाओं ने मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में खासी दिलचस्पी दिखाई। लघु उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे ब्याज अनुदान की जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि लघु उद्योगों के लिए 25 लाख रुपये तक के ऋण पर 8 प्रतिशत, 5 करोड़ तक 6 प्रतिशत और 10 करोड़ तक के ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। पिछले 4 वर्षों में विभाग द्वारा 146 करोड़ रुपये का ब्याज अनुदान देते हुए 4 हजार 763 करोड़ का ऋण वितरित किया जा चुका है। युवा उद्यमियों ने मिशन निर्यातक बनो योजना के प्रति भी रुचि दिखाई। युवाओं के सवाल कैसे निर्यातक बन सकते हैं? कैसे बिजनेस शुरू कर सकते हैं? कैसे इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कार्ड (ईआईसी) बना सकते हैं? निर्यात के लिए कितनी राशि की जरूरत है? क्या निर्यात करने के लिए उत्पादन करना जरूरी है या बिना उत्पादन भी निर्यात किया जा सकता है? जैसे कई तरह के सवाल पूछे गए। प्रदर्शनी के दौरान संबंधित योजनाओं से जुड़े नोडल अधिकारियों ने उनकी जिज्ञासा को शांत किया और उनका मार्गदर्शन भी किया।

युवाओं ने हाल में लॉन्च मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के बारे में जानकारी ली। इस योजना के तहत 18 से 45 वर्ष के युवाओं को 15 लाख रुपये तक के लघु वाणिज्यिक वाहन खरीदने पर राज्य सरकार द्वारा 60 हजार रुपये या वाहन की ऑन रोड कीमत का 10 प्रतिशत (जो भी कम हो) अनुदान दिया जा रहा है। प्रदेश के 3,300 युवाओं को स्वरोजगार योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। अब तक 1,200 से अधिक आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं।

प्रदर्शनी में डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, रीको एमनेस्टी योजना, रीको द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने संबंधी योजना, वन स्टॉप शॉप, राजस्थान एक्सपोर्ट काउंसिल के गठन, राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम-2019, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारियां विभागीय अधिकारियों और कार्मिकों द्वारा आमजन को दी गई।

शिक्षा विभाग

शिक्षा विभाग की स्टॉल पर विद्यार्थियों के हितों से जुड़ी विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। युवा विद्यार्थियों ने विविध छात्रवृत्ति योजनाओं व स्कूटी योजना में विशेष रुचि व उत्सुकता दिखाई। इन विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना,

विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) सम्बल योजना, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडेमिक एक्सीलेंस योजना सहित छात्राओं हेतु देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना तथा कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के बारे में जानकारी ली। आगंतुक छात्र-छात्राओं को इन छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत लाभ मिलने की पात्रता एवं छात्रवृत्ति

राशि के बारे में बताया गया। इसके साथ ही कॉलेज में प्रवेश लेने वाली छात्राओं के लिए कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना एवं देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना के अन्तर्गत पात्रता व प्रोत्साहन राशि के बारे में बताया गया। आगन्तुकों ने नि:शुल्क यूनिफॉर्म कपड़ों, बाल गोपाल योजना के मिल्क पाउडर के सैम्पलों की गुणवत्ता के बारे में चर्चा की। इसके साथ ही स्टॉल पर प्रदर्शित प्रारम्भिक कक्षाओं के रंग-बिरंगे फर्नीचर की प्रशंसा भी की।

गौपालन विभाग

गौपालन विभाग की स्टॉल पर प्रदर्शित गोबर से बने दैनिक जीवन के उपयोग के उत्पाद खासतौर पर आगंतुकों के बीच आकर्षण के केन्द्र बने। गौशालाओं में पारम्परिक उत्पाद जैसे घी, गौमूत्र, हवन सामग्री, एवं सौंदर्य प्रसाधन तैयार करने का कार्य लम्बे समय से किया जा रहा है, लेकिन अब गोबर के उपयोग से कागज, सजावटी डिब्बे, दीपक, धूप बत्ती, डायरी, पैकेजिंग पेपर, विशेष त्योहारों पर राखी, लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। यहां तक कि गोबर का उपयोग कर होली के रंग भी बनाए जा रहे हैं। राज्य में विभिन्न संस्थाओं द्वारा आकर्षक पैकेजिंग के साथ गुणवत्तायुक्त उत्पाद देश-विदेशों में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिससे गोबर से बने उत्पाद एक नए उद्योग के रूप में विश्व पटल पर अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं। लोगों में इसलिये भी इनका क्रेज है क्योंकि गोबर से बने उत्पाद न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं, बल्कि गौशालाओं में कचरा प्रबंधन में भी अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। साथ ही ऐसे उत्पाद बनाने वाली राज्य की गौशालाएं अतिरिक्त आय के साथ रोजगार के अवसर भी विकसित कर रही हैं।

प्रदर्शनी में मौजूद गोबर से उत्पाद बना रहे श्री भीमराज शर्मा ने गोबर से बने कागजी उत्पादों की जानकारी देते हुए बताया कि सभी उत्पाद हस्तनिर्मित होते हैं तथा गोबर, कटन एवं गौमूत्र को मिलाकर तैयार किये जाते हैं। उन्होंने बताया कि वे वर्तमान में 75 से अधिक विभिन्न प्रकार के उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं। गोबर निर्मित उत्पादों को देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी पहचान मिल रही है। साथ ही ये उत्पाद पारिस्थितिकी संतुलन में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं।

ये भी रहे आकर्षण का केन्द्र

इसके अलावा प्रदर्शनी में चिकित्सा विभाग की स्टॉल में प्रदर्शित एसएमएस अस्पताल के प्रस्तावित आईपीडी टावर का मॉडल, आवासन मंडल की स्टॉल पर प्रदर्शित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का मॉडल,

चिरंजीवी सेल्फी, परिवहन विभाग का ड्राईविंग सिम्युलेटर, सौर ऊर्जा से संचालित सीवरेज क्लीनिंग रोबोट आकर्षण का केंद्र रहे।

कलाकारों ने बिखेरे सांस्कृतिक रंग

प्रदर्शनी में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में लोक कलाकारों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये। श्री गोपाल सिंह खींची और उनके साथी कलाकारों ने मांड गायकी से समां बांधा। उन्होंने पधारो महारे देश और नीम्बूडा-नीम्बूडा जैसे गीतों की प्रस्तुति से श्रोताओं को मन्त्रमुग्ध कर दिया। भवाई लोक कला संस्थान और संगीत से जुड़े कई ख्यातिनाम कलाकारों ने राजस्थान की लोक कला, संस्कृति और लोक नृत्य से दर्शकों को रूबरू करवाया। कार्यक्रम में पंद्रह वर्षीय बाल कलाकार श्री सूर्यवर्धन द्वारा प्रस्तुत प्रसिद्ध भवाई नृत्य सभी के आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम में संस्थान के कलाकारों द्वारा तेरहताली नृत्य की प्रस्तुति दी गई। नृत्यांगनाओं ने ''म्हारी घूमर'' गीत पर घूमर नृत्य कर खूब वाह-वाही लूटी तो वही दूसरी ओर श्री राहुल वालिया ने

''रुणिचे रा धणी'' जैसे लोकगीतों की प्रस्तुतियां देकर खूब तालियां बटोरी।

समापन समारोह में सबरंग संस्थान के सचिव श्री राजेंद्र राव के निर्देशन में पंडित जयनारायण परमार के द्वारा पेश ''पणिहारी जियलो'' गीत पर सिर पर चरी रख कर किए भवई नृत्य और ''म्हारी घूमर छे नखराळी ऐ मां'' गीत पर किए गए घूमर नृत्य पर दर्शक झूम उठे। कार्यक्रम में आयोजित सुरीली संध्या में मूंगा राम एंड पार्टी से जुड़े कलाकारों ने मंच पर अपने सांस्कृतिक रंग बिखेरे। एक ओर जहां प्रसिद्ध गायक कलाकार सरदार राणा ने अपनी धुनों से दर्शकों को चहकाया तो वहीं दूसरी ओर श्री मूंगा राम एवं अन्य नृत्यांगनाओं की मनमोहिनी प्रस्तुति से सामने बैठा हर एक दर्शक खुद को झूमने से रोक नही पाया। प्रदर्शनी की समापन संध्या में सूफी गायक रहमान हरफनमौला एंड पार्टी ने सूफियाना संगीत की सरिता बहाई। ''जिक्र ए इलाही'' जैसे सूफियाना कलमों से शुरू हुई इस खूबसूरत शाम में ''भर दो झोली'', ''दमा-दम मस्त कलंदर'' और ''छाप तिलक'' जैसे गीतों ने समा बांधा।

शख्सियतों ने दी महत्त्वपूर्ण जानकारियां

प्रदर्शनी में हर रोज खास शख्सियतों ने भी महत्त्वपूर्ण जानकारियां आगंतुकों को प्रदान कीं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने पुलिस विभाग द्वारा शुरू की गई सुरक्षा सखी योजना सहित किये जा रहे अन्य नवाचारों से दर्शकों को अवगत करवाया।

20 दिसंबर को हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय की कुलपति ने युवाओं को पत्रकारिता की दुनिया से अवगत करवाया। वहीं पी. के. मस्त नाम से मशहूर श्री प्रवीण कुमार ने शेरो-शायरी और हंसी-ठिठोली के रोचक अंदाज में स्कूली बच्चों को यातायात नियमों एवं सड़क सुरक्षा के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। युवा सिंगर-कंपोजर श्री आयुष भनोट ने संगीत की बारीकियों से अवगत करवाया।

समापन समारोह में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के सचिव ने प्रदेश की खेल नीति और उसकी उपलब्धियों के साथ-साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल प्राप्त खिलाड़ियों को राज्य सरकार द्वारा आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के तहत दी जा रही सरकारी नौकरियों की जानकारी आगंतुकों से साझा की। हाउसिंग बोर्ड द्वारा विकसित सिटी पार्क में सिंगापुर की झलक देखने को मिली।

सिकन्दरा में दो दिवसीय विकास प्रदर्शनी

स्थानीय एवं अन्य राज्यों के लोगों ने ली योजनाओं की जानकारी

राज्य सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने पर दौसा जिले के सिकन्दरा में 18 दिसम्बर से दो दिवसीय विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस विकास प्रदर्शनी में विभिन्न राज्यों से आए व स्थानीय लोगों ने राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस दो दिवसीय प्रदर्शनी में देश के पहले शांति एवं अहिंसा विभाग के गठन, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के आयोजन, पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को फिर से लागू करने, आई.टी. नवाचारों, इन्वेस्ट राजस्थान समिट, श्रेष्ठ कोरोना प्रबंधन, कोई भूखा न सोये अभियान, निरोगी राजस्थान अभियान, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, राजस्थान सिलिकोसिस नीति, स्टार्टअप्स जैसे विषयों और फ्लैगशिप योजनाओं को आकर्षक रूप से प्रदर्शित किया गया।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत और सांसद श्री राहुल गांधी ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया और श्री गांधी ने राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और लाभार्थियों से मिलकर उनको मिल रहे लाभ के बारे में जानकारी ली। श्री गहलोत एवं श्री गांधी प्रदर्शनी के दौरान मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों से मिले। लाभार्थी अंतिमा शर्मा ने बताया कि योजना से उनको लंग कैंसर का महंगा उपचार नि:शुल्क मिल रहा है। वहीं साढ़े तीन वर्षीय लाभार्थी देवांश सैनी के परिजन ने बताया कि योजना से देवांश का नि:शुल्क कॉकलियर इम्प्लांट हो पाया है। लाभार्थी मोहन लाल मीणा ने कहा कि योजना के तहत उनका जयपुर में हार्ट का ऑपरेशन तथा किडनी ट्रांसप्लांट नि:शुल्क हुआ है। लाभार्थियों ने कहा कि चिरंजीवी योजना पूरे देश में लागू होनी चाहिए जिससे गंभीर बीमारी से ग्रसित आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके।

श्री गांधी ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के विद्यार्थियों से अंग्रेजी में संवाद करते हुए उनके सपनों के बारे में पूछा। श्री गहलोत और श्री गांधी ने प्रदर्शनी में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, राजीविका और उड़ान योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। लाभार्थी महिलाओं ने बताया कि उन्हें इन योजनाओं से रोजगार मिलने से आर्थिक संबल मिला है। वहीं नि:शुल्क सेनेटरी नैपकिन मिलने से उनका स्वास्थ्य प्रबंधन बेहतर हुआ है। इस अवसर पर ऋण माफी के लाभार्थी किसानों से भी मुख्यमंत्री और सांसद ने संवाद किया। लाभार्थी किसानों ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा उनका लाखों का ऋण माफ किया गया है, जिससे उन्हें राहत मिली है।

प्रदर्शनी में शामिल हुए राजीव गांधी सेन्टर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी (आर-केट) के विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री और सांसद को बताया कि संस्थान में उन्हें रोबोटिक्स, रिसर्च आदि क्षेत्रों में उच्चस्तरीय शिक्षण प्राप्त हो रहा है, जो पहले राजस्थान में उपलब्ध नहीं था। प्रदर्शनी में श्री राहुल गांधी ने राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने से हुए लाभों के बारे में जानकारी ली।

सांसद श्री गांधी ने राज्य में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, निर्भया स्क्वॉयड, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, जन आधार योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान/ हथलेवा योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडेमिक एक्सीलेंस, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना आदि के बारे में भी जानकारी ली।

83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन

मंथन से निकला अमृत : लोकतंत्र को देगा ऊर्जा

राजस्थान विधानसभा के मुख्य हॉल में आयोजित 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में विभिन्न सत्रों में लोकतंत्र, संसद व विधानमंडलों को प्रभावी बनाने के लिए सार्थक चर्चा हुई।

राज्यसभा, लोकसभा और देश के विभिन्न राज्यों के विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों व सचिवों का सम्मेलन 10 से 13 जनवरी तक राजस्थान विधानसभा में आयोजित किया गया। 11 और 12 जनवरी को 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन (AIPOC) आयोजित हुआ और इसके साथ ही 10 जनवरी को विधानसभाओं के सचिवों का 59वां सम्मेलन भी आयोजित किया गया।

इस सम्मेलन में मौजूदा पीठासीन अधिकारियों के अलावा पूर्व विधानसभा अध्यक्षों, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों, संसद के दोनों सदनों के महासचिव और विधानमंडलों के प्रमुख सचिव और सचिव और पूर्व विधानसभा सचिवों ने भी शिरकत की।

सम्मेलन का उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनकड़ और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने किया। सम्मेलन के समापन सत्र के मुख्य अतिथि राज्यपाल श्री कलराज मिश्र थे। समारोह में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, राज्यसभा के उप सभापति श्री हरिवंश, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी और राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता श्री गुलाब चंद कटारिया ने उद्बोधन दिया।

डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा
उपनिदेशक, जनसम्पर्क

लोकतांत्रिक परंपरा को समृद्ध बनाने में जनप्रतिनिधियों की भूमिका महत्त्वपूर्ण – उपराष्ट्रपति

11 जनवरी को पीठासीन अधिकारियों के 83वें सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनकड़ के अनुसार देश की गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपरा को समृद्ध बनाने में जनप्रतिनिधियों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। उन्हें जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने तथा लोकतंत्र की गरिमा बनाये रखने के लिए अपने आचरण में अधिक

अनुशासन और शालीनता लाने की आवश्यकता है। श्री धनकड़ ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद और संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर के वक्तव्यों का उल्लेख किया। संविधान सभा ने जो रास्ता दिखाया है, हमें उसका अनुकरण करना चाहिए। श्री धनकड़ ने संवाद और परिचर्चा को प्रजातंत्र का महत्त्वपूर्ण अंग बताया। वर्तमान समय में भारत ने हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है और विश्व कल्याण और सामूहिक तरक्की में हम वैश्विक भागीदार बनकर उभरे हैं। आज भारत निवेश के लिए सबसे पसंदीदा स्थान बन गया है। कोविड-19 जैसी विकट परिस्थिति में हमने आत्मनिर्भरता का परिचय दिया। श्री धनकड़ ने सम्मेलन में आए पीठासीन अधिकारियों का आह्वान किया। जनप्रतिनिधियों को नियमों की जानकारी देकर तथा उन्हें समझाकर समाज के विकास में उनकी भूमिका बढ़ाएं।

संसद और विधानसभाएं लोकतंत्र के मंदिर, जनहित के मुद्दों पर संवेदनशील होकर विचार करें जनप्रतिनिधि – राज्यपाल

12 जनवरी को समापन सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने संसद और विधानसभाओं को लोकतंत्र का मंदिर बताया। जनप्रतिनिधि यहां राजनीति से ऊपर उठकर जनहित के मुद्दों पर

संवेदनशील होकर विचार करें। यहां जो भी बहसें या बिजनेस हो, वह आमजन के सतत विकास के लिए हो। संसदीय लोकतंत्र में पीठासीन अधिकारियों की महती भूमिका होती है और वह विधानमंडल सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकारों का एक तरह से अभिभावक भी होता है। लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए पीठासीन अधिकारी अपनी प्रभावी भूमिका निभाएं। सदन का अध्यक्ष सदन के कामकाज से संबंधित नियमों का अंतिम व्याख्याकार होता है।

सदस्य जनता से जुड़े मुद्दों पर पूरी तैयारी के साथ सदन में प्रभावी चर्चा करें। विधायक सदन में महत्त्वपूर्ण विषयों पर होने वाली बहसों के दौरान अधिकाधिक उपस्थित रहें। उन्होंने प्राइवेट मेम्बर बिल को भी अधिकाधिक बढ़ावा दिए जाने पर बल दिया। सदनों में संसदीय कार्यवाही से संबंधित प्रमुख निर्णयों से जुड़ी शोध सामग्री प्रदान करने की त्वरित व्यवस्था विकसित होनी चाहिए।

श्री मिश्र के अनुसार राज्यपाल कोई व्यक्ति नहीं है, वह संवैधानिक संस्था है और जब संवैधानिक आधार पर यह संतुष्टि हो जाती है कि अध्यादेश औचित्यपूर्ण है तभी उसे स्वीकृति प्रदान की जाती है। राज्य सरकार की अनुशंसा पर विधानसभा का सत्र आहूत करने की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है।

संविधान निर्माताओं की मंशा के अनुरूप कानून बनाएं और इस प्रक्रिया में जन भागीदारी बढ़ाएं – लोकसभा अध्यक्ष

लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला के अनुसार दुनिया भारत को देख रही है। देश में होने वाले आगामी जी-20 सम्मेलन में हमें हमारे लोकतंत्र के बदलाव को दुनिया के सामने रखने का मौका मिलेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरें और उनके अभावों के समाधान का रास्ता निकालें। संविधान निर्माताओं की मंशा के अनुरूप कानून बनाएं और इस प्रक्रिया में जन भागीदारी बढ़ाएं। विधानमंडलों में चर्चा का स्तर ऊंचा होना चाहिए। कानून बनाने की प्रक्रिया में संवाद, उच्च कोटि की चर्चा और समीक्षा के लिए अधिक समय देने की जरूरत है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व बढ़ गया है। देश की जनता विधायी कार्यवाही देखती है। उनके मन पर अच्छा प्रभाव पड़े तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास बढ़े यह हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आने वाले समय में देश के सभी विधानमंडलों की कार्यवाही एक ही मंच पर देखी जा सकेगी। इसके लिए डिजिटल संसद का मंच 2023 में जनता को समर्पित करने की उम्मीद है। पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन एक ऐसा मंच है जिसमें संवाद होता है और अनुभव साझा होते हैं ताकि बदलते परिप्रेक्ष्य में विधानमंडलों की भूमिका अधिक कारगर हो सके। 75 साल की लोकतांत्रिक यात्रा में विधानमंडल प्रभावी हुए हैं, मगर हमें मंथन करना है कि लोकतांत्रिक भारत की अवधारणा, विचारधारा और कार्यशैली से हम लोगों के जीवन में कैसे बदलाव ला सकते हैं।

जी-20 में भारत की अध्यक्षता हम सभी का सौभाग्य है। सभी विधायी संस्थाओं को अपने यहां बेहतर कानून बनाने का कार्य करना चाहिए। विधायी संस्थाओं में नियमों, प्रक्रियाओं की समीक्षा की जाए।

उन्होंने लोकसभा द्वारा स्वस्थ संसदीय परम्पराओं के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रयास किया जाएगा कि देशभर में विधायी संस्थाओं में आचरण, नियम-प्रक्रियाओं, परंपराओं में एकरूपता हो। उन्होंने संसदीय समितियों में दल से ऊपर उठकर लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए प्रयास किए जाने का आह्वान किया। विधानसभाएं अपने-अपने राज्यों में आमजन की सतत भागीदारी सुनिश्चित करें। कैसे लोकतांत्रिक संस्थाएं आदर्श बनें, कैसे दुनियाभर की विधायी संस्थाएं हमारे लोकतंत्र से प्रेरणा लें-इसके लिए भी सभी मिलकर कार्य करें।

विधानमंडलों की कार्यवाही बिना रुकावट चलाने के लिए हमें आत्मचिंतन कर रास्ता तलाशना पड़ेगा – उपसभापति, राज्यसभा

राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश के अनुसार विधायिका की उत्पादकता प्रभावी करने, देश के युवाओं को राजनीति से जोड़ने तथा विधानमंडलों की कार्यवाही बिना रुकावट चलाने के लिए हमें आत्मचिंतन कर रास्ता तलाशना पड़ेगा। संसद ने हाल में अनेक अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त किया है जो कि बदलते समय की आवश्यकता है। डिजिटल क्षेत्र में देश काफी आगे बढ़ा है। यह सम्मेलन विधायी प्रक्रिया को मजबूत कर लोगों के स्थायी कल्याण में बेहतर भूमिका निभाएगा।

राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने विधायी संस्थाओं की साख बढ़ाने के लिए कार्य करने पर जोर देते हुए महात्मा गांधी के आत्मानुशासन को विशेष रूप से याद किया। उनके अनुसार विधायी संस्थाओं द्वारा कानून बनाना ही निदान नहीं है। प्रगति और विकास सतत साधना है, इसलिए सदन में गंभीर चर्चा और बहस का माहौल बने। उन्होंने विधायकों को पर्याप्त होम वर्क कर आने, प्रश्नों को तर्क सहित प्रस्तुत करने और मर्यादा के आचरण के साथ आत्मानुशासन अपनाने का आह्वान किया।

संसदीय प्रणाली को सुदृढ़ करने में पीठासीन अधिकारियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका – मुख्यमंत्री

पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के अनुसार राजस्थान में देश के पीठासीन अधिकारियों की सारगर्भित चर्चा में लिए गए फैसले दूरगामी परिणाम लाएंगे। देश के सर्वांगीण विकास में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका साबित होगी। हमें लोकतंत्र को और मजबूत करने का संकल्प लेकर भारतीय संविधान की रक्षा करनी होगी। संसदीय प्रणाली को सुदृढ़ करने में पीठासीन अधिकारियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

विधानसभा और विधानपरिषदों की कार्यवाही को और अधिक प्रभावी बनाने की जिम्मेदारी सभी सदस्यों पर निर्भर करती है। सदन में पक्ष एवं विपक्ष अपना महत्त्व रखते हैं। इनके बीच संतुलन बनाने के साथ-साथ सदन की कार्यवाही नियमों के तहत चलाई जाए, यह पीठासीन अधिकारियों के लिए चुनौतीपूर्ण है। इस चुनौती को स्वीकार कर दायित्वों का निर्वहन करने से सदन की गरिमा बनी रहेगी। देश अमृत महोत्सव मना रहा है। हम सभी ने लोकतंत्र को मजबूत बनाने का कार्य किया है, इसी से ही न्यायपालिका स्वतंत्र है। सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में राजस्थान विधानसभा में कई नवाचार हुए हैं, जिससे विधानसभा की कार्यवाही पारदर्शिता के साथ आमजन तक पहुंच सकी है। वर्ष 1952

के बाद की कार्यवाही को ऑनलाइन करना, बालसभा का आयोजन और परिसर में विश्वस्तरीय संग्रहालय की शुरुआत करना बड़ी पहल है।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के अनुसार प्रदेश में नागरिकों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई है। पूरे देश की जनता के लिए स्वास्थ्य का अधिकार लागू कर इस तरह की योजना लाई जानी चाहिए। उन्होंने हर व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से देशभर में सामाजिक सुरक्षा कानून लाने का सुझाव भी दिया। प्रदेश में राज्य सरकार ने सोच-विचार कर मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के

स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू की है। कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए देश में एवं अन्य राज्यों में भी पुरानी पेंशन योजना लागू की जानी चाहिए।

विधानमंडलों को वित्तीय स्वायत्तता मिलेगी तो वे बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे – विधानसभा अध्यक्ष

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी के अनुसार लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका रूपी तीनों स्तंभों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। जनता की अपेक्षाओं के मुताबिक नीतियों का निर्माण विधायिका करती है, इसलिए इसकी जवाबदेही ज्यादा है। मौजूदा समय की प्रासंगिकता को देखते हुए नीति और कानून में बदलाव की जरूरत है, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा तथा जनता के प्रति हमारी जवाबदेही बढ़ेगी। विधानमंडलों को वित्तीय स्वायत्तता मिलेगी तो वे बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही डिजिटल माध्यम से जनता तक पहुंचाकर सदन की कार्यप्रणाली को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाया है। राजस्थान में आयोजित पीठासीन अधिकारियों का यह सम्मेलन नये सिरे से देश का निर्माण करने में मुख्य भूमिका निभाएगा और लोकतंत्र को मजबूत करने में आदर्श प्रस्तुत करेगा।

राजस्थान का संसदीय परम्पराओं का गौरवशाली इतिहास रहा है। उन्होंने अपने सम्बोधन में विधायिका के प्रभावी संचालन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने सम्मेलन में देशभर से आए पीठासीन अधिकारियों का आभार भी व्यक्त किया।

विचार मंथन से निकला नवनीत लोकतांत्रिक प्रणाली को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा – नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाब चंद कटारिया ने सम्मेलन में आए अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया और विश्वास जताया कि सम्मेलन में विचार मंथन से निकला नवनीत आने वाली पीढ़ियों को लोकतांत्रिक प्रणाली को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। उन्होंने विधायी समितियों के कार्य को और बेहतर बनाए जाने पर बल दिया।

9 संकल्प हुए पारित

राजस्थान विधानसभा में आयोजित दो दिवसीय अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 83वें सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई :

1. लोकतंत्र की जननी के रूप में जी-20 में भारत का नेतृत्व
2. संसद और विधानमंडलों को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और उपयोगी बनाने की आवश्यकता
3. डिजिटल संसद के साथ राज्य विधानमंडलों को जोड़ना और
4. संविधान के आदर्शों के अनुरूप विधायिका और न्यायपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने की आवश्यकता

सम्मेलन में देश के 27 विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों ने इन विषयों पर गहन विचार-विमर्श के बाद आम सहमति से 9 संकल्प पारित किए। समापन सत्र के बाद लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी ने संयुक्त प्रेसवार्ता में इस सम्मेलन में पारित किए गए नौ संकल्पों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

संकल्प 1. भारत की जी-20 अध्यक्षता : पहला संकल्प भारत में आयोजित होने वाले जी-20 राष्ट्रों के समूह और संसद-20 की अध्यक्षता ग्रहण करने पर भारत को लोकतंत्र की जननी के रूप में प्रस्तुत करने के बारे में पारित किया गया। इसके साथ ही समता, समावेशिता, बंधुत्व, शांति और संवहनीय जीवन शैली के लिए वैश्विक नेतृत्व को पूर्ण समर्थन देने का संकल्प लिया गया।

संकल्प 2. शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत में आस्था : शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत में आस्था से जुड़ा एक अन्य संकल्प पारित किया गया जिसमें राष्ट्र के विधायी निकायों के माध्यम से कानून बनाने में भारत की जनता की प्रधानता में अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त किया गया।

शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए राज्य के सभी अंगों को हमारे संविधान में निर्दिष्ट संवैधानिक सीमाओं का सम्मान करने का आह्वान किया गया।

संकल्प 3. आदर्श समरूप नियम प्रक्रियाएं : नव स्वतंत्र राष्ट्र के समक्ष ज्वलंत विषयों के समाधान के संदर्भ में संविधान सभा के सदस्यों के अनुकरणीय आचरण को ध्यान में रखते हुए सहयोग, सामंजस्य एवं विभिन्न विचारधाराओं के समन्वय की भावना के अनुरूप यह संकल्प लिया गया कि विधायी निकायों के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों की व्यापक रूप से समीक्षा की जाएगी। इस बात पर सहमति बनी कि सदस्यों की अधिक भागीदारी तथा विधानमंडलों की सभाओं के सार्थक कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करते हुए आदर्श समरूप नियम प्रक्रियाएं बनाई जाएं और अमर्यादित तथा असंसदीय आचरण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु नियम प्रक्रियाओं में सदस्यों के लिए आचार संहिता को शामिल किया जाए।

संकल्प 4. विधानमंडलों की सभाओं में व्यवधान : विधायी निकायों में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सदस्यों द्वारा सरकार से प्रश्न पूछे जाने के समयसिद्ध साधन स्वीकार करते हुए सभी राजनीतिक दलों से आह्वान किया गया कि वे आम सहमति से यह निर्णय लें कि विधानमंडलों की सभाओं में व्यवधान उत्पन्न न किया जाए।

संकल्प 5. समितियों और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा : विधानमंडल के संचालकों के रूप में समितियों की भूमिका को पहचानते हुए समिति प्रणाली को सशक्त करने और कार्यपालिका के कार्य की समीक्षा की सीमा और दायरे को बढ़ाने के लिए भारत में सभी विधायी निकायों से सार्थक कदम उठाने का आह्वान किया गया।

संकल्प 6. राज्य विधानमंडलों के कार्य प्रबंधन में वित्तीय स्वायत्तता : संघ और राज्य विधानमंडलों के कार्य प्रबंधन में वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए अध्यक्ष लोक सभा को संबंधित राज्य सरकारों से विस्तृत विचार-विमर्श हेतु अधिकृत किया गया।

संकल्प 7. राष्ट्रीय डिजिटल ग्रिड : सम्मेलन में यह संकल्प लिया गया कि भारत में सभी विधायी निकाय अधिक दक्षता, पारदर्शिता और परस्पर संपर्क की दृष्टि से विधायी निकायों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल ग्रिड में भाग लेने हेतु सभी कदम उठाएंगे।

संकल्प 8. उत्कृष्ट विधायिका पुरस्कार : सदस्यों की प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण भागीदारी को बढ़ावा देने और विधायिका के कार्यकरण की कार्योत्पादकता बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों को मान्यता देने के उद्देश्य से इस संकल्प को दोहराया गया कि एक निष्पक्ष प्रणाली के माध्यम से चुने गए विधायी निकायों हेतु वार्षिक आधार पर एक उत्कृष्ट विधायिका पुरस्कार की शुरुआत की जाये।

संकल्प 9. समाज के सभी वर्गों को संवैधानिक प्रावधानों तथा विधायी नियमों और प्रक्रियाओं की शिक्षा : नौवां संकल्प समाज के सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं और युवाओं को संवैधानिक प्रावधानों तथा विधायी नियमों और प्रक्रियाओं की जानकारी देने के सभी संभव प्रयास करने से जुड़ा है।

विधायी निकायों के सचिवों के 59वें सम्मेलन में विधायी संस्थाओं की सर्वोत्तम परिपाटियों का हुआ आदान-प्रदान

विधायी संस्थाओं की सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान-प्रदान और देश भर में विधायी प्रणाली के सुदृढीकरण के लिए विधानमंडलों के सचिवों का 59वां सम्मेलन 10 जनवरी को जयपुर में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई :

- राज्य विधानमंडलों में समिति प्रणाली को मजबूत करके कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करना
- डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से भारत के विधायी निकायों को जोड़ना और
- विधानमंडलों की पहुंच का विस्तार करके भारत के विधायी निकायों को लोगों के करीब लाना।

इस सम्मेलन में राज्य सभा के महासचिव श्री प्रमोद चन्द्र मोदी, लोकसभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, राजस्थान विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री महावीर प्रसाद शर्मा और 27 विधानमंडलों के प्रमुख सचिवों और सचिवों ने शिरकत की। सम्मेलन के अध्यक्ष महासचिव, लोकसभा श्री उत्पल कुमार सिंह ने लोकसभा में कार्यप्रणाली को सुगम और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अपनाए गए नवाचारों के बारे में बताया। महासचिव, राज्यसभा श्री पी.सी. मोदी ने इस सम्मेलन की 70 साल की यात्रा का उल्लेख किया। भारत लोकतंत्र की एक ऐसी मिसाल माना जाता है जिसने विश्व की आबादी के छठे हिस्से में लोकतंत्र को कायम रखने के साथ ही उसे चिरायु बनाए रखने के मार्ग में कई चुनौतियों का सामना किया है।

सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में राजस्थान विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री महावीर प्रसाद शर्मा ने विश्वास जताया कि कि इस सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श से संवैधानिक, प्रशासनिक और विधायी मामलों में विधानमंडलों की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। सम्मेलन में सचिवों ने बैठक की महत्ता पर चर्चा की। विधायी संस्थाओं ने देश की सफल लोकतांत्रिक यात्रा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विधायी निकायों के सम्मेलन ने संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों के पीठासीन अधिकारियों को संसदीय प्रक्रियाओं पर संवाद करने, कार्य अनुभव साझा करने और विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने के लिए एक प्रभावकारी मंच प्रदान किया है।

राजस्थान में चौथी बार हुआ यह सम्मेलन

राजस्थान को अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन (AIPOC) का आयोजित करने का मौका 11 वर्ष बाद मिला है। इससे पहले जयपुर में एआईपीओसी का आयोजन 1957, 1978 और 2011 में किया गया था। इस तरह इस साल इसका आयोजन जयपुर में चौथी बार हुआ है।

अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की शुरुआत 1921 में हुई। वर्षों से यह सम्मेलन लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए नए अनुभवों और विचारों को साझा करने के लिए एक प्रभावी मंच सिद्ध हुआ है। एआईपीओसी भारत के विधानमंडलों का सर्वोच्च निकाय है और इसका शताब्दी वर्ष समारोह 2021 में शिमला,

हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था।

राजस्थानी संस्कृति से हुआ अतिथियों का स्वागत

राजस्थान विधानसभा भवन पर इस दौरान लाइटिंग की गई। देश भर से आने वाले अतिथियों का तिलक लगाकर व चूनरी का साफा पहनाकर राजस्थानी संस्कृति से स्वागत किया गया। 13 जनवरी को देश के विभिन्न भागों से आए अतिथिगण को जयपुर शहर और उसके आस-पास के विभिन्न पर्यटन स्थलों का अवलोकन करवाया गया। सम्मेलन में आए अतिथियों ने राजस्थान की मेहमान नवाजी की सराहना करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी का आभार जताया।

दो पुस्तकों का हुआ विमोचन

सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित राष्ट्रपतियों के अभिभाषणों के नये संकलन का विमोचन किया गया। इसके साथ राष्ट्रमंडल संसदीय संघ राजस्थान शाखा द्वारा आयोजित छह सम्मेलनों में दिए गए उद्बोधनों के संकलन ''नए आयाम'' का भी विमोचन किया गया।

पुस्तक प्रदर्शनी

इस सम्मेलन के दौरान विधानसभा परिसर में संसद पुस्तकालय एवं राजस्थान विधानसभा पुस्तकालय के संयुक्त तत्वावधान में एक पुस्तक प्रदर्शनी लगाई गई। इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनकड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी और नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाब चंद कटारिया ने किया। सभी अतिथिगण ने पुस्तकों का अवलोकन किया।

मुख्यमंत्री के सपने को धरती पर उतार भारत के अलग-अलग कोने की कला और संस्कृति को समेटा गया

राष्ट्रीय स्काउट-गाइड जम्बूरी में दिखी मिनी भारत की झलक

प्रदेश को 67 साल बाद भारत स्काउट एवं गाइड संगठन की राष्ट्रीय जम्बूरी के आयोजन का गौरव प्राप्त हुआ। देश के विभिन्न प्रांतों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की कला एवं संस्कृति के वाहक के रूप में लगभग 34 हजार 500 से अधिक स्काउट, गाइड, रोवर्स और रेंजर्स के साथ-साथ बांग्लादेश, सऊदी अरब, घाना, श्रीलंका, मलेशिया, नेपाल, केन्या आदि देशों के 400 स्काउट इस सात दिवसीय वृहद आयोजन के साक्षी बने।

राजस्थान के पाली जिले के निम्बली गांव एवं इससे लगती करीब 2 हजार बीघा जमीन पर 6 माह तक प्रशासन और भारत स्काउट एवं गाइड संगठन के अथक प्रयासों से एक अस्थायी गांव विकसित किया गया। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 4 जनवरी को जम्बूरी का उद्घाटन किया। इन 35 हजार स्काउट-गाइड के रहने के लिए 220 हेक्टेयर क्षेत्र में 3,520 टेंट बनाए गए। जम्बूरी के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के साथ-साथ राज्यपाल श्री कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। यह राजस्थान की धरा पर आयोजित दूसरी जम्बूरी है। इससे पहले वर्ष 1956 में प्रदेश में पहली बार गुलाबी नगरी जयपुर में राष्ट्रीय जम्बूरी आयोजित हुई थी।

राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन 70 साल से किया जा रहा है। वर्ष 1953 में पहली बार हैदराबाद में जम्बूरी का आयोजन किया गया था। इसके बाद धीरे-धीरे इस आयोजन में भाग लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई। जम्बूरी का उद्देश्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को एकजुट करना और राज्यों की सांस्कृतिक विविधता से परिचित

आशुतोष अवाना, पल्लव जोशी, सोनू शर्मा
सहायक जनसंपर्क अधिकारी

कराना था। भारत स्काउट-गाइड ने अपने संगठन के अंतर्गत देश में 52 राज्य बना रखे हैं। इनमें देश के सभी राज्य एवं संघ शासित प्रदेश भी शामिल हैं।

25 करोड़ का बजट प्रावधान

भारत स्काउट-गाइड संघ से हरी झंडी मिलने के साथ ही सरकार द्वारा जंबूरी आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई थीं। स्थान चयन को लेकर स्टेट चीफ कमिश्नर श्री निरंजन आर्य के निर्देशन में टीमों ने विभिन्न स्थलों की टोह ली और आखिरकार पाली जिले की रोहट पंचायत समिति के निम्बली ब्राह्मणान गांव में रीको की जगह का चयन किया गया। तत्पश्चात सरकार द्वारा राज्य बजट 2022-23 में

राष्ट्रीय स्काउट-गाइड जंबूरी पाली में आयोजित करने की घोषणा करते हुए 25 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान भी किया गया।

झांकियों से प्रदर्शित हुई राज्यों की कला-संस्कृति

विभिन्न राज्यों से आए स्काउट एवं गाइड दलों ने अपने राज्यों की गंगा-जमुनी तहजीब, समृद्ध कला, संस्कृति एवं इतिहास को दर्शाती झांकियां प्रदर्शित कीं। इन झांकियों में राज्यों के पहनावे, लोक नृत्यों आदि का परिचय कराया गया। प्रदेश के अलग-अलग जिलों से आए स्काउट-गाइड दलों ने मरुधरा के गौरवशाली इतिहास, समृद्ध सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय विरासतों का आकर्षक प्रदर्शन किया। राजस्थानी बैंड के साथ रंगीलो राजस्थान थीम पर सजे कोटा के विश्व प्रसिद्ध दशहरा मेले, रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट, कैला देवी मेला (करौली), डिग्गी कल्याण मंदिर (टोंक) सहित भरतपुर-धौलपुर की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। वहीं झारखंड का आदिवासी नृत्य, बिहार का छठ पूजन दृश्य लोगों ने खूब पसन्द किया। ओडिशा, नगालैंड, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आदि की झांकियां भी आकर्षक रहीं।

रंगोली के जरिए भरे विविधता में एकता के रंग

आजादी के अमृत महोत्सव का रंग गुजरात से आये स्काउट दल ने जहां अपनी रंगोली में बिखेरा, वहीं कर्नाटक के दल ने वहां की कला-संस्कृति को सुंदर रंगों से जमीन पर उकेरा। इसी तरह जम्मू-कश्मीर से आयी वंदना ने महिला सशक्तीकरण का संदेश रंगोली में दर्शाकर राजस्थान सरकार का धन्यवाद किया। हरियाणा से आपसी सौहार्द एवं भाईचारे के रंग लेकर आये स्काउट्स में खासा उत्साह नजर आया। रंगोली में राष्ट्रीय एकता, आजादी का अमृत महोत्सव, स्वच्छ भारत-सुंदर भारत आदि के रंग बिखेरे गए।

सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने किया रोमांचित

भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के हवाई करतबों को देखकर वहां मौजूद अतिथिगण एवं प्रतिभागी रोमांचित हो गए। सभी ने इन करतबों का तालियों के साथ उत्साहवर्धन किया। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम की उड़ान को देखने वालों का रोमांच भी सातवें आसमान पर था। रोहट के आसमान में वायुसेना के जांबाज लड़ाकों ने

आसमान में देश-विदेश के हजारों लोगों के सामने भारतीय वायु सेना की शूरवीरता की इबारत लिखी।

गौरतलब है कि जम्बूरी का इतिहास साउथ अफ्रीका से जुड़ा है। इसके अनुसार यहां के मैफकिंग नाम के एक कस्बे में सन् 1899-1,900 के बीच 1,500 गोर और 8,000 स्थानीय लोग रहते थे। डच (बोअर) की करीब 9000 लोगों की सेना ने मैफकिंग पर कब्जा करने के लिए उसे चारों तरफ से घेर लिया। इस दौर में बेडन पावेल (जिन्होंने स्काउट की स्थापना की) मैफकिंग में ही पोस्टेड थे। डच सैनिकों से युद्ध लड़ने के लिए उनके पास 1 हजार सैनिक और सिर्फ 8 बंदूकें थीं, इसके बाद भी पावेल ने 218 दिन तक डच लोगों को अपने कस्बे में नहीं घुसने दिया। इसका सबसे बड़ा कारण मैफकिंग में 9 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों की सेना तैयार करना था। छोटे बच्चों को फर्स्ट एड और दूसरे कामों में और बड़े लोगों को युद्ध लड़ने के लिए लगाया गया। इसी घटना के बाद बेडन पावेल ने 'एड्स टू स्काउटिंग' नामक पुस्तक लिखी। इसके बाद पावेल ने 1907 में पर्ल हार्बर के निकट ब्राउन सी द्वीप में 29 जुलाई से 9 अगस्त तक 20 लड़कों के साथ प्रथम स्काउट शिविर आयोजित किया जिसके आधार पर ही भारत में जम्बूरी का आयोजन होता है।

पहली बार सी स्काउट्स ने जंबूरी में लिया भाग

पहली बार 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जंबूरी में सी स्काउट्स ने भी भाग लिया और सुसज्जित गणवेश के साथ आणक, बैंड और संगीत की धुनों के साथ सी स्काउट्स ने परेड में हिस्सा लिया।

सी स्काउट्स एंड गाइड्स,दक्षिण भारत स्काउट्स एंड गाइड्स से मान्यता प्राप्त एक स्वयं सेवी संस्था है। महाराष्ट्र के पुणे से शुरू हुई सी गाइड्स की वर्तमान में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में इकाइयां संचालित हैं। पहली बार सी स्काउट्स ने राजस्थान में 18वीं राष्ट्रीय जंबूरी में भाग लिया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने वक्तव्य में स्काउट्स की प्रतिभा को सराहा।

सी स्काउट्स एक अत्याधुनिक स्काउंटिंग है जो मुख्यत: वाटर एक्टिविटी जैसे तैराकी, लाइफ सेविंग, बोट पुलिंग, कयाकिंग, कैनिंग, स्क्यूलिंग सेलिंग आदि ट्रेनिंग पर काम करती है। सी स्काउटिंग के सी मैन्स को फायर फाइटिंग, टेलीकम्युनिकेशन, हैम रेडियो, आपदा प्रबंधन जैसी मुख्य कार्यों में महारथ हासिल है। वर्तमान में सी स्काउट्स भारतीय सेना और मर्चेंट नेवी में ऑफिसर पदों पर नियुक्त हो रहे हैं।

जम्बूरी में राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी

18वीं राष्ट्रीय जंबूरी में राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी को लेकर छात्र–छात्राओं, आगंतुकों व स्काउट–गाइड में जबरदस्त उत्साह रहा। प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में स्कूल–कॉलेज के छात्र–छात्राओं व ग्रामीण जनों ने विभिन्न विभागों की स्टॉल्स का अवलोकन कर सरकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों के बारे में बारीकी से जानकारियां प्राप्त कीम। वहीं प्रदर्शनी में महात्मा गांधी की चरखे पर सूत कातते हुई

प्रतिकृति ने आगंतुकों का मन मोह लिया व आगंतुकों द्वारा उत्साहपूर्वक खूब सेल्फी ली गई । इस कारण आगंतुकों द्वारा प्रदर्शनी में इसे सेल्फी प्वॉइंट का नाम दिया गया ।

प्रदर्शनी में आयोजित किए जा रहे क्विज कॉम्पिटिशन और पजल गेम्स को लेकर युवाओं और स्टूडेंट्स ने विशेष रुचि दिखाई। साथ ही सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा क्विज विजेताओं को सर्टिफिकेट प्रदान किये गये।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा तैयार सरकार की प्रोग्रेस रिपोर्ट व योजनाओं से संबंधित साहित्य के प्रति लोगों ने विशेष रुचि दिखायी और रिकॉर्ड स्थापित करते हुए करीब पचास हजार से ज्यादा आगंतुकों ने सरकार की प्रोग्रेस रिपोर्ट, 'राजस्थान सुजस' पत्रिका और जनकल्याणकारी योजनाओं के किट प्राप्त किये । विभाग द्वारा स्थापित सुजस स्टूडियो भी आगंतुकों के आकर्षण का केंद्र बना।

आमजन को मिली विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी

विकास प्रदर्शनी में विभिन्न राज्यों से आए व स्थानीय लोगों सहित सभी आगंतुकों ने राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस प्रदर्शनी में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक्स के आयोजन, पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को फिर से लागू करने, आई.टी. नवाचारों, इन्वेस्ट राजस्थान समिट, श्रेष्ठ कोरोना प्रबंधन, कोई भूखा न सोए अभियान, निरोगी राजस्थान अभियान, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, राजस्थान सिलिकोसिस नीति, स्टार्टअप्स जैसे विषयों और फ्लैगशिप योजनाओं को आकर्षक रूप से प्रदर्शित किया गया ।

राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी में आए आगंतुकों ने राज्य में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, निर्भया स्क्वायड, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, जन आधार योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडेमिक एक्सीलेंस, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना आदि के बारे में भी जानकारी ली।

राजस्थान सरकार का दो दिवसीय चिंतन शिविर

उपलब्धियों के साथ चुनौतियों पर हुई चर्चा

चंद्रशेखर पारीक
सहायक जनसंपर्क अधिकारी

राज्य सरकार के कामकाज, उपलब्धियों और चुनौतियों को लेकर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में दो दिवसीय चिंतन शिविर 17 जनवरी, 2023 को हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशिक्षण संस्थान में संपन्न हुआ। शिविर में 21 घंटे तक सरकार के 28 विभागों ने अपने कामकाज का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। शिविर में राज्य की कानून-व्यवस्था, सुशासन, सामाजिक सुरक्षा, खेल, शिक्षा, युवा, महिला एवं मजदूरों से जुड़ी फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

'राइट टू सोशल सिक्योरिटी' एक्ट के लिए प्रस्ताव पारित

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के अनुसार देश में एक समान सामाजिक सुरक्षा देने के लिए केन्द्र सरकार को 'राइट टू सोशल सिक्योरिटी' एक्ट लागू करना चाहिए। इसके लिए चिंतन शिविर में मंत्रिपरिषद् सदस्यों ने एकमत प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा।

अद्यतन सेवा नियमों की 51 पुस्तिकाओं का विमोचन

चिंतन शिविर के अंतिम सत्र में मुख्यमंत्री द्वारा अद्यतन सेवा नियमों की 51 पुस्तिकाओं का विमोचन किया गया। सेवा नियमों को अद्यतन करने से राजकीय कर्मचारियों की भर्ती प्रकिया एवं पदोन्नति विवाद रहित एवं समय पर हो सकेगी।

विभागों ने दिया कामकाज का लेखा-जोखा

मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा के अनुसार चिंतन शिविर में 21 घंटे तक 28 विभागों की बजट, जन घोषणाओं, अभियानों और आगामी कार्य योजनाओं पर गहन विचार-विमर्श किया गया। इससे प्रदेशवासियों को बेहतर और समयबद्ध सेवाएं देने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में एक माह बाद फिर से बैठक आयोजित की जाएगी।

गृह विभाग : 66 में से 57 बजट घोषणाएं पूर्ण

चिंतन शिविर में गृह विभाग के प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि 66 में से 57 बजट घोषणाओं की क्रियान्विति पूर्ण कर ली गई है तथा शेष प्रगतिरत हैं। साथ ही, 22 जन घोषणाओं में से 21 पूरी कर ली गई हैं। 841 पुलिस थानों में स्वागत कक्ष का निर्माण कर लिया गया है। सभी जिलों में साइबर पुलिस थाने स्वीकृत किए गए हैं तथा साइबर क्राइम इन्वेस्टीगेशन यूनिट की स्थापना की गई है। अपराधों की रोकथाम के लिए एसओजी की 6 नई फील्ड यूनिट तथा एक एंटी नार्कोटिक्स यूनिट की स्थापना की गई है।

खेल एवं युवा मामलात विभाग : प्रत्येक ब्लॉक में बन रहे स्टेडियम

खेल एवं युवा मामलात विभाग के प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि अन्तरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने पर इनामी राशि बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये तक कर दी गई है। प्रदेश में अन्तरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करने के लिए विभिन्न खेलों के 500 कोच लगाए जाएंगे। प्रदेश के 229 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति दी गई

है। खिलाड़ियों को उच्चस्तरीय प्रशिक्षण देने के लिए जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में परफोर्मेंस ट्रेनिंग एण्ड रिहेबिलिटेशन सेंटर की स्थापना की गई है। पैरा-ओलम्पिक खेलों के पदक विजेताओं को भी 25 बीघा कृषि भूमि आवंटित करने का प्रावधान किया गया है। 42 करोड़ रुपये की लागत से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का सफल आयोजन किया गया, जिसमें 30 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में एक नई खेल संस्कृति विकसित हुई है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग : मजदूर परिवारों को 1,815 करोड़ की सहायता

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की 74 बजट घोषणाओं में से 49 घोषणाएं पूरी की जा चुकी हैं तथा 25 प्रगतिरत हैं। सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना संचालित की जा रही है। कोरोना महामारी के समय 33 लाख असहाय, निराश्रित एवं मजदूर परिवारों को कुल 1,815 करोड़ रुपये की सहायता दी गई। विभाग द्वारा विभिन्न वर्गों के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये का अनुसूचित जाति कोष, 100-100 करोड़ रुपये के अन्य पिछड़ा वर्ग विकास कोष, ईडब्ल्यूएस कोष, नवजीवन कोष, 50 करोड़ रुपये का डीएनटी कोष, 20 करोड़ रुपये का वाल्मीकि कोष तथा 10 करोड़ रुपये के ट्रांसजेंडर उत्थान कोष का गठन किया गया है। सिलिकोसिस रोगियों के कल्याण व आर्थिक सहायता के लिए सिलिकोसिस नीति जारी की गई है।

महिला एवं बाल विकास विभाग : बेहतरीन क्रियान्वयन के लिए मिले पुरस्कार

महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि उड़ान योजना में 1.51 करोड़ महिलाओं-किशोरियों को सेनेटरी नैपकिन वितरित किए जा रहे हैं। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना से अब तक लगभग 50 हजार से अधिक महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। महिलाओं एवं बालिकाओं के समग्र कल्याण के लिए राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 जारी की गई है। विभाग के उत्कृष्ट कार्यों के चलते प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा के अंतर्गत कोविड काल में ऑनलाइन शिक्षा में 2021 में स्कॉच सिल्वर अवॉर्ड तथा इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत पेपरलेस योजना के क्रियान्वयन के लिए 2022 में स्कॉच सिल्वर अवॉर्ड हासिल किया है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग : राशन वितरण में आई पारदर्शिता

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों के जरिए पारदर्शिता से राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा, नए नाम भी सूची में जोड़े गए हैं।

शासन सचिवालय में आरम्भ किये गए ई-फाइलिंग सिस्टम के तहत फाइल की ऑनलाइन अप्रूवल देते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत और मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा

कार्मिक विभाग: सरकारी नौकरियां देने में राजस्थान अग्रणी

कार्मिक विभाग के प्रस्तुतीकरण में बताया कि राज्य में अब तक 1 लाख 41 हजार 738 पदों पर नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी हैं तथा 30 हजार 944 पदों के परीक्षा परिणाम जारी हो चुके हैं। वहीं, 1919 पदों के लिए साक्षात्कार किए जाने हैं तथा 9,955 पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित की जा चुकी हैं। 71 हजार 24 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए जा चुके हैं तथा 12 हजार 977 पदों के लिए जल्द विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इसके अलावा, 53 हजार 174 पदों के लिए अभ्यर्थना भेजने की प्रक्रिया जारी है। अब तक कुल 3 लाख 23 हजार 630 पदों पर नियुक्तियां देने का कार्य किया जा रहा है।

जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग: पांच जन घोषणाओं में से चार पूर्ण

जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग प्रस्तुतीकरण में बताया कि 33 बजट घोषणाओं में से 22 पूर्ण कर ली गई हैं, वहीं 11 प्रगतिरत हैं। पांच जन घोषणाओं में से 4 पूर्ण कर ली गई हैं। विभाग द्वारा 50 सौर ऊर्जा आधारित सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं। प्रदेश में 8 नए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों का संचालन शुरू हो चुका है। अनुसूचित जनजातियों के समावेशी विकास हेतु 100 करोड़ रुपये के विकास कोष का गठन किया है। ट्राइफेड भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में विभाग को वन-धन योजना भविष्य हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम तथा सर्वाधिक मूल्य वर्धित उत्पादन श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग : 2 वर्ष में 6.45 करोड़ औषधीय पौधे वितरित

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि कुल 30 बजट घोषणाओं में से 19 पूरी कर ली गई हैं तथा 11 प्रगतिरत हैं। जन घोषणाओं की क्रियान्विति पूर्ण कर ली गई हैं। गत वर्षों में विभाग द्वारा 1 लाख 9 हजार 817 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण किया गया। घर-घर औषधि योजना के तहत गत 2 वर्षों में 6.45 करोड़ औषधीय पौधों का वितरण किया गया। राज्य में इमारती लकड़ी, बांस एवं लघु वन उपज के उत्पादन में वृद्धि हेतु राजस्थान राज्य वन विकास निगम का गठन किया गया। प्रत्येक जिले में एक-एक लव-कुश वाटिका स्थापित की जा रही है। जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर एवं अजमेर में बॉटनिकल गार्डन स्थापित किए जा रहे हैं। ई-वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी तैयार की गई है। जयपुर में ई-वेस्ट री-साइकिलिंग पार्क के लिए भूमि आवंटित की जा चुकी है।

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग : 75 में से 64 बजट घोषणाएं पूर्ण

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि 75 बजट घोषणाओं में से 64 पूरी कर ली गई हैं तथा 11 प्रगतिरत हैं। प्रदेश में नवीन 'इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति' लागू कर दी गई है। प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए राजस्थान रोडवेज में नि:शुल्क यात्रा का प्रावधान किया गया है। ई-व्हीकल एसजीएसटी का पुनर्भरण/बैठने की क्षमता अनुसार एकमुश्त अनुदान, दिव्यांगों हेतु अडोप्टेड वाहनों के क्रय पर वाहन कर में 100 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है। दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया गया है। ग्रामीण परिवहन सेवा का विस्तार करते हुए दूरदराज के गांवों और ढाणियों को बस सेवा से जोड़ा जा रहा है।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग : 98 प्रतिशत परिवेदनाओं का समयबद्ध निस्तारण

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के प्रस्तुतीकरण में बताया कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-181 संपर्क पोर्टल से एकीकृत कर संचालित की जा रही है। संपर्क पोर्टल से 98 प्रतिशत परिवेदनाओं का समयबद्ध निस्तारण किया जा रहा है।

सुशासन के लिए संकल्पबद्ध राज्य सरकार : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के अनुसार प्रदेश में हर वर्ग का सर्वांगीण विकास हमारी प्राथमिकता है। राज्य सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा एवं उद्योग सहित हर क्षेत्र के उत्थान के लिए महत्त्वपूर्ण निर्णय ले रही है। गत चार बजट घोषणाओं में जो वायदे किए, उन्हें संकल्पबद्ध होकर पूरा किया गया है। वहीं, आगामी बजट में आमजन से प्राप्त सुझावों को भी शामिल किया जाएगा।

- कानून व्यवस्था बनाए रखने में राजस्थान पूरे देश में अग्रणी राज्य है। अनिवार्य एफआईआर पंजीकरण नीति से प्रकरणों की संख्या में जरूर वृद्धि हुई है, लेकिन अन्य राज्यों के मुकाबले पीड़ितों को त्वरित न्याय मिल रहा है। पहले पीड़ित परिवार विभिन्न कारणों से पुलिस थानों तक नहीं पहुंच पाते थे। अब वे प्रकरण दर्ज करा रहे हैं और अपराधियों को सजा मिल रही है।
- राजस्थान में एफआईआर के अनिवार्य पंजीकरण की नीति के बावजूद वर्ष 2021 में 2019 की तुलना में करीब 5 प्रतिशत अपराध कम दर्ज हुए हैं।

निरोगी राजस्थान की संकल्पना में आयुर्वेद की महत्ती भूमिका है। प्रदेश में आयुष नीति जारी करना भी अभिनव पहल है। आयुर्वेद विभाग के प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि इस वर्ष 66 करोड़ रुपये की नि:शुल्क औषधियां वितरित की जा चुकी हैं।

- अनिवार्य पंजीकरण नीति का ही परिणाम है कि वर्ष 2017-18 में 33 प्रतिशत एफआईआर कोर्ट के माध्यम से इस्तगासे द्वारा दर्ज होती थीं, परन्तु अब ये सिर्फ 13 प्रतिशत रह गई हैं।
- वर्ष 2017-18 में बलात्कार के मामलों में अनुसंधान समय 274 दिन था, जो अब केवल 68 दिन रह गया है। पॉक्सो के मामलों में अनुसंधान का औसत समय वर्ष 2018 में 232 दिन था, जो अब 66 दिन रह गया है।
- एससी-एसटी एक्ट के करीब 51 प्रतिशत मामले अदालत के माध्यम से सीआरपीसी 156(3) से दर्ज होते थे। अब यह महज 10 प्रतिशत रह गया है।
- राज्य में शराब के ठेकों को रात 8 बजे बन्द करवाने की जवाबदेही क्षेत्र के थानाधिकारी की करने के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में बार आदि का संचालन भी अर्धरात्रि के बाद नहीं होगा।
- भ्रष्टाचार रोकने में भी राजस्थान सबसे आगे है। राज्य सरकार की गंभीरता इसी से साफ होती है कि देश में एसीबी की सबसे अधिक कार्रवाई राजस्थान में हो रही है। पेपर लीक के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। दोषी अभ्यर्थियों को आजीवन ब्लैकलिस्ट किया गया, लिप्त संस्थाओं और व्यक्तियों की सम्पत्ति कुर्क करने का प्रावधान किया गया है।
- महिलाओं एवं बालिकाओं के स्वास्थ्य व स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए नि:शुल्क सैनेटरी नैपकिन वितरण एवं जागरूकता हेतु उड़ान योजना लागू की गई है। आगे भी नवीन योजनाएं लागू की जाएंगी।
- आदिवासियों को सामुदायिक पट्टे वितरित करने में आ रही बाधा दूर की जाए। प्रक्रिया को सरल कर लंबित आवेदनों की फिर से जांच कराकर उन्हें राहत प्रदान करें।
- जीवन रक्षक योजना का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार करें, ताकि सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाकर जान बचाने वालों को प्रोत्साहन मिले। सड़क सुरक्षा के लिए जागरुकता अभियान चलाए जाए।
- सिलिकोसिस बीमारी के मरीजों को तुरंत सहायता पहुंचाने के साथ ही इसके कारणों पर प्रभावी रोकथाम के लिए सख्त निर्णय लिए जाकर खान मालिकों पर कार्रवाई की जाए। सिलिकोसिस नीति में जारी प्रोटोकॉल का पालन कराएं, ताकि मरीजों और उनके परिवारजनों को राहत मिल सके।
- निरोगी राजस्थान की संकल्पना में आयुर्वेद की महत्ती भूमिका है। प्रदेश में आयुष नीति जारी करना भी अभिनव पहल है। आयुर्वेद विभाग के प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि इस वर्ष 66 करोड़ रुपये की नि:शुल्क औषधियां वितरित की जा चुकी हैं।

संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह सुशासन के लिए प्रतिबद्ध राज्य स्तरीय जन अभाव अभियोग निराकरण समिति

"मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की आकांक्षाओं के अनुरूप राज्य सरकार सदैव प्रदेशवासियों को संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन एवं जन हितैषी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य स्तरीय जन अभाव अभियोग निराकरण समिति द्वारा सरकारी सेवाओं की गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी, जवाबदेह और त्वरित डिलीवरी को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।"

जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष श्री पुखराज पाराशर से जनसम्पर्क अधिकारी सपना शाह की बातचीत के अंश...

राज्य स्तरीय जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के प्रमुख कार्य क्या हैं?

राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति विभागों के जन अभियोगों के बकाया प्रकरणों की स्थिति का आंकलन, इसके कारणों का विश्लेषण एवं जन अभियोग का समयबद्ध सीमा में त्वरित निस्तारण की कार्यवाही करती है। समिति द्वारा प्रशासन के सभी स्तरों यथा पंचायत, ब्लॉक, उपखण्ड, जिला एवं विभाग के स्तर पर जन अभियोगों के निराकरण हेतु प्रारूप (Model) विकसित करना एवं दिशा निर्देश जारी करना, अभिशंसित प्रारूप के अनुरूप क्रियान्विति के स्तर की निगरानी करना एवं क्रियान्विति सुनिश्चित करने का कार्य किया जाता है।

समिति जिला, उपखण्ड, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति जन अभियोग शिविरों की मॉनिटरिंग एवं समीक्षा, जन प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर उनसे फीडबैक लेना एवं आवश्यकतानुसार जन अभाव अभियोग निराकरण की प्रक्रिया में परिवर्तित करने के अलावा मुख्यमंत्री सचिवालय के जन अभियोगों के पर्यवेक्षण का कार्य भी करती है।

आमजन अपने परिवाद किस प्रकार दर्ज करवा सकते हैं?

आमजन अपना परिवाद, शिकायत या परिवेदना राजस्थान संपर्क पोर्टल, 181 पर कॉल करके, ई-मित्र के माध्यम से, मोबाइल ऐप एवं स्वयं उपस्थित होकर दर्ज करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आमजन अपनी शिकायत writetocm@rajasthan.gov.in के माध्यम से सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते हैं। मुख्यमंत्री निवास पर भी नियमित रूप से अधिकारीगण जनसुनवाई करते हैं। संबंधित विभाग के अधिकारियों और कार्मिकों द्वारा एक निश्चित प्रक्रिया के तहत विभिन्न स्तरों (L1-L4) के माध्यम से परिवादों का समाधान किया जाता है। प्रत्येक जिले में पदस्थापित सहायक निदेशक, लोक सेवाएं संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवादों की मॉनिटरिंग तथा समीक्षा का कार्य संपादित करते हैं। ग्राम पंचायत स्तर तथा उपखण्ड स्तरीय जन सुनवाई में सहयोग समन्वय करना तथा जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन कराना इनका प्रमुख दायित्व है।

परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए त्रिस्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम किस प्रकार आयोजित किया जा रहा है?

राज्य सरकार द्वारा माह मई, 2022 से त्रिस्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माह के प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत, द्वितीय गुरुवार को उपखण्ड व तृतीय गुरुवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। जनसुनवाई शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहकर समस्याओं का समाधान यथासंभव मौके पर ही करने का प्रयास कर रहे हैं। जिससे आमजन को अपनी समस्याओं के लिए जिलों एवं राजधानी में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं हो। त्रिस्तरीय जनसुनवाई में आमजन से प्राप्त शिकायतों, परिवादों का समय पर गुणवत्तापूर्ण व संतुष्टि स्तर पर समाधान किया जा रहा है तथा आमजन को तत्काल राहत मिल रही है।

त्रिस्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था के अन्तर्गत कितने प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया है?

त्रिस्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था में 31 दिसम्बर, 2022 तक ग्राम पंचायत स्तर पर 1 लाख 39 हजार 508 परिवाद दर्ज किए गए जिनमें से 99.38 प्रतिशत यानी 1 लाख 38 हजार 643 परिवादों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जा चुका है। उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई एवं समाधान व्यवस्था के अन्तर्गत समस्त जिलों से 30 हजार 387 प्रकरण/परिवेदनाएं दर्ज की गई, जिसमें से 98.34 प्रतिशत यानी 29 हजार 884 प्रकरण/परिवेदनाओं का निस्तारण किया जा चुका है। इसी

प्रकार जिला स्तरीय जनसुनवाई व्यवस्था के अन्तर्गत 15 हजार 615 परिवाद दर्ज किए गए। इन दर्ज परिवादों में से 94.67 प्रतिशत यानी 14 हजार 783 परिवादों को निस्तारित किया जा चुका है।

परिवादी की संतुष्टि के लिए समिति द्वारा क्या प्रयास किये जाते हैं ?

समिति सभी शिकायतों/ प्रकरणों/ परिवादों के समयबद्ध निस्तारण के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे द्वारा सभी माध्यमों से प्राप्त प्रकरणों की उचित मॉनिटरिंग व पर्यवेक्षण किया जाता है। परिवादी समिति कार्यालय या ई-मेल आईडी chairman.rpg@rajasthan.gov.in पर ई-मेल के माध्यम से एवं डाक से भी अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त परिवेदनाएं नियमानुसार कार्यवाही हेतु संबंधित विभागों को प्रेषित की जाती है एवं सूचना प्रार्थी, परिवादी, शिकायतकर्ता को भी दी जाती है। यदि किसी परिवेदना पर संबंधित विभाग द्वारा समय पर सूचना प्रेषित नहीं की जाती है तो स्मरण पत्र भिजवाया जाता है। प्रकरणों का समय सीमा में निस्तारण नहीं होने अथवा अधिक संख्या में लम्बित रहने की स्थिति में यह समिति संबंधित विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, विभागाध्यक्ष को अपनी बैठक में आमंत्रित कर सकती है। संबंधित विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत पर की गई कार्यवाही के बारे में समिति व प्रार्थी को भी सूचित किया जाता है, इससे परिवादी को उसकी शिकायत कब, कहां और किसे दी गई है, की समयबद्ध जानकारी प्राप्त होती है। परिवेदनाओं के अब तक किये गये निस्तारण की व्यवस्था से आमजन को स्थानीय स्तर पर ही राहत प्राप्त हो रही है।

परिवादी की संतुष्टि एवं उसकी शिकायत का मात्र निस्तारण नहीं, बल्कि पूर्णत: निराकरण करना ही हमारा लक्ष्य है। हमारा प्रयास है कि आमजन को दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता को विभिन्न भौतिक एवं डिजिटल माध्यमों से जांचा एवं परखा जाए और यदि दी जाने वाली सेवाओं में किसी भी प्रकार की कमी है तो इस संबंध में बिना विलंब किए समस्या को हल किया जाए।

जिलों में आयोजित जन अभियोग शिविरों का पर्यवेक्षण किस प्रकार किया जाता है?

समिति अध्यक्ष के रूप में मैं समय- समय पर जिलों में जाकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मॉनिटरिंग करता हूं तथा जिलों में चल रही त्रिस्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रमों में भाग लेता हूं। साथ ही, समिति के सदस्य भी जनसुनवाई कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सभी सदस्य पूर्ण संवेदनशील होकर मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हर व्यक्ति तक सरकारी मदद की पहुंच सुनिश्चित कर रहे हैं।

राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति के सदस्य के रूप में किन्हें सम्मिलित किया गया है?

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुसार प्रबुद्ध, अपने विषय

में पारंगत एवं जन हितैषी व्यक्तियों को राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति में सम्मिलित किया गया है। इस समिति में अध्यक्ष के साथ लोकसभा या राज्यसभा का राज्य सरकार द्वारा मनोनीत एक सदस्य, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 2 विधानसभा सदस्य, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत एक जिला प्रमुख (सदस्य), सदस्य के रूप में अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रमुख शासन सचिव या शासन सचिव जन अभियोग निराकरण विभाग, सदस्य सचिव के रूप में निदेशक, लोक सेवाएं एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव जन अभियोग निराकरण विभाग, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत प्रतिष्ठित सामाजिक व्यक्ति 07 (प्रत्येक संभाग से एक व्यक्ति), अनुसूचित जाति का एक व्यक्ति, अनुसूचित जनजाति का एक व्यक्ति, एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता, अल्पसंख्यक श्रेणी का एक व्यक्ति, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का राज्य सरकार द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति इस समिति के सदस्य हैं। मनोनीत सदस्यों को समिति से संबंधित कार्यों के संपादन के लिए संभाग का आवंटन किया गया है।

14 अक्टूबर 2022 को राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति की प्रथम बैठक आयोजित की गई। बैठक में समिति द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्यों का विवरण एवं त्रिस्तरीय जनसुनवाई व समाधान व्यवस्था पर विस्तार से सदस्यों को जानकारी प्रदान की गई।

प्रस्तावित राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी एवं जवाबदेही विधेयक-2022 की क्या विशेषताएं हैं?

राज्य के निवासियों को सेवाओं की गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए तथा संवेदनशील, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार द्वारा ''राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी एवं जवाबदेही विधेयक-2022'' का प्रारूप सार्वजनिक अवलोकन, मंथन हेतु विभागीय वेबसाइट rpg.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध करवाया गया है। प्रस्तावित विधेयक का हिन्दी संस्करण 31 अक्टूबर 2022 को विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया जा चुका है।

समिति के अध्यक्ष के रूप में मैं समिति के सभी सदस्यों, सभी विभागों, अधिकारियों से अपेक्षा करता हूं कि सभी पूर्ण मनोयोग से जनसमस्या के समाधान के लिए समर्पण भाव से काम करते हुए हर उस व्यक्ति तक मदद पहुंचायें, जहां जिसे आवश्यकता हो एवं राज्य को सुखद और खुशहाल राज्य में बदलने में सभी अपना योगदान दें।

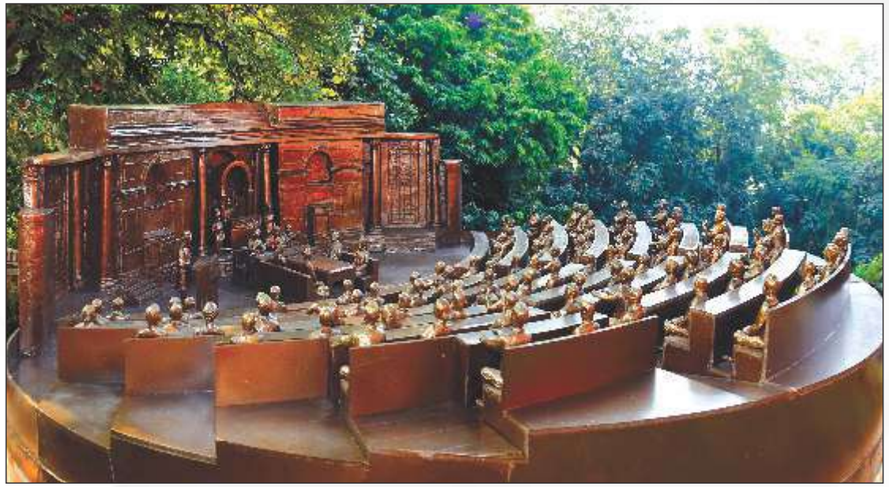

राजभवन में संविधान उद्यान

संविधान और उसकी विशिष्टताओं के बारे में रू–ब–रू करवाने के उद्देश्य से राजभवन, जयपुर में 'संविधान उद्यान' का निर्माण किया गया है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 3 जनवरी को इसका लोकार्पण किया। संविधान के लेखन, इसे निर्मित करने के लिए बनाई गयी संविधान सभा, संविधान सभा की बैठकों, संविधान निर्माण में शामिल रहे महापुरुषों की इसमें भूमिका और इसे लागू किए जाने की यात्रा को संविधान उद्यान में विभिन्न मूर्तिशिल्पों, छाया–छवियों, मॉडल्स और अन्य कलात्मक माध्यमों से जीवंत किया गया है। छाया: सूजस

साकार हुई देश की बहुरंगी संस्कृति, सजे-धजे ऊंटों के साथ थिरके 'पावणे'

बीकानेर में आयोजित हुआ 29वां अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव

ढोल की थाप पर ठुमक-ठुमक नाचते ऊंट, मूंछों को ताव देते सजे-धजे रोबीले और नख-शिख ऋृंगारित युवतियों के साथ विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतिनिधित्व करते लोक कलाकारों ने 29वें अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आगाज किया, तो देशी-विदेशी पर्यटकों को पश्चिमी राजस्थान की समृद्ध जीवनशैली और संस्कति से रूबरू होने का मौका मिला।

पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से तीन दिवसीय ऊंट उत्सव 13 से 15 जनवरी तक आयोजित हुआ। पहली बार इसकी शुरुआत 'बीकानेर कार्निवल' से हुई। संभागीय आयुक्त और जिला कलक्टर ने रंग-बिरंगे गुब्बारे हवा में उड़ाकर और झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। 'बीकानेर कार्निवल' की शुरुआत मश्क वादन से हुई। पारम्परिक वेशभूषा में सजे-घजे रोबीलों ने राजस्थान की बहुरंगी संस्कृति को साकार किया। बीएसएफ के ऊंटों का दस्ता विशेष आकर्षण का केन्द्र रहा। इसका नेतृत्व सीआई ने किया। इस दौरान एक हजार मीटर लम्बे साफे का प्रदर्शन किया गया। कार्निवल में टेबूलो थीम के साथ फेस्टिवल के मस्कट 'फेलिक्स' ने दर्शकों की वाहवाही लूटी। इस दल में विंटेज कारें और रॉयल इनफील्ड बाइक्स को भी सम्मिलित किया गया। इन पर पारम्परिक वेशभूषा में सज-धज बैठे विदेशी पर्यटकों ने सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया।

हरि शंकर आचार्य
सहायक निदेशक, जनसंपर्क

कार्निवल के दस्ते में विद्यार्थियों ने डोरेमोन, छोटा भीम, नोबिता जैसे कार्टून पात्रों का रूप धर बच्चों का भरपूर मनोरंजन किया। इस कार्निवल में कच्छी घोड़ी नृत्य और मयूर नृत्य की प्रस्तुतियां भी शामिल रहीं। बहरूपियों ने विभिन्न देवताओं, चार्ली चैपलिन, मोटू-पतलू, रावण आदि का रूप धरा। चूरू के श्याम मित्र मंडल ने चंग की थाप के साथ लोकगीतों की सुमधुर स्वरलहरियां बिखेरी। सहरिया जनजाति के नृत्य को भी आमजन ने बेहद पसंद किया। इस दौरान पंजाब का

भांगड़ा-गीत, जम्मू का रउफ, गुजरात का राठवा, हरियाणा का घूमर फाग, पुरूलिया का छउ तथा महाराष्ट्र के सौंगी मुखौटा नृत्य के कलाकारों ने देश की विविध संस्कृतियों का प्रदर्शन करते हुए विविधता में एकता का संदेश दिया।

कार्निवल में राजस्थानी वेशभूषा में सजी कॉलेज छात्राएं, ऊंट सवार रोबीले तथा ऊंट गाड़ियों पर राजस्थानी लोक जीवन का दृश्य देखकर आमजन ने राजस्थान की ग्रामीण संस्कृति को जाना। जम्मू कश्मीर के कलाकारों ने रेगिस्तान के जहाज पर सवार होकर लोक गीत प्रस्तुत किए। डांडिया गैर, रासलीला और महिषासुर मर्दन की झांकी भी कार्निवल में शामिल रही। बच्चों ने समोसा, भुजिया और औजार का रूप धारण कर आमजन को आकर्षित किया। कार्निवल के साथ मस्ती में झूमते बच्चों ने आमजन को भी थिरकने के लिए मजबूर कर दिया। शहरवासियों ने पलक पांवडे बिछाकर इसका अभिनंदन किया। ऊंटों का ठुमक-ठुमक नृत्य को देखकर आमजन ने दांतों तले अंगुली दबा ली। एक ऊंट ने संभागीय आयुक्त के गले में फूलों की माला पहनाई तो वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर इसका अभिनंदन किया।

'बीकानेर बाई नाइट' में पहली बार शहरी क्षेत्र में ऊंट उत्सव की रही धूम

बीकानेर शहरी परकोटे की मौज-मस्ती, अपनापन, मिलनसारिता, परम्पराएं, संस्कृति, खान-पान और साल भर मनाए जाने वाले तीज-त्योहारों को देखते हुए इस बार जिला प्रशासन की पहल पर पहली बार यहां 'बीकानेर बाई नाइट' का आयोजन हुआ। इसकी शुरुआत शहर के ऐतिहासिक छतरी के पाटे वाले दम्मानी चौक में वीर रस प्रधान अमर सिंह राठौड़ की रम्मत के साथ हुई। मोहता चौक में पंचांग पढ़ने की पुरातन परम्परा का निर्वहन हुआ। हर्षों के चौक में होली के अवसर पर खेले जाने वाले डोलची खेल को बड़ी स्क्रीन पर देखकर हर किसी ने बीकानेर की सांस्कृतिक विरासत को समझने का प्रयास किया। इस अवसर पर पूरे रूट को रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया। यहां की हवेलियों की कारीगरी देखकर देशी विदेशी सैलानी अभिभूत हुए। आसाणियों के चौके में वेद पाठशाला के विद्यार्थियों ने वेद मंत्र प्रस्तुत किए। स्थानीय कलाकारों द्वारा हवेली संगीत की प्रस्तुति दी गई। ढढ्ढों के चौक में गणगौर घूमर नृत्य प्रस्तुत किया गया। वहीं कोचरों के चौक में संगीत संध्या हुई। यहां फूड जोन बनाया गया। जहां बीकानेरी भुजिया, जलेबी और घेवर बनाया गया तथा आमजन ने इनका स्वाद चखा। इस प्रयास ने बीकानेर शहरी परकोटे में 'नाइट टूरिज्म' की संभावनाओं को बल दिया।

ऊंटों की प्रतियोगिताओं के नाम रहा दूसरा दिन

ऊंट उत्सव का दूसरा दिन ऊंटों की प्रतियोगिताओं के नाम रहा। ऊंट की पीठ पर कैची के माध्यम से की गई आकर्षक फर कटिंग भी विशेष रही। ऊंट पालकों द्वारा ऊंट की कमर पर लोक देवी-देवताओं, परंपराओं और यहां की स्थापत्य कला पर आधारित चित्र उकेरे, जिन्हें देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध रह गए। राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं को देखने के लिए बड़ी संख्या में आमजन पहुंचे। दूसरे दिन के कार्यक्रमों की शुरुआत ऊंट नृत्य प्रतियोगिता से हुई। नृत्य के दौरान ऊंटों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। नृत्य करते ऊंट ने ऊंटपालक की गर्दन को अपने मुंह में ले लिया तो वहां सन्नाटा दिखा। आमजन ने कैमल सफारी का आनंद भी उठाया। ऊंटनी के दूध से बनी आइसक्रीम, लस्सी, छाछ और अन्य उत्पाद विशेष आकर्षण का केंद्र रहे।

कोमल बनी मिस मरवण, जोशी मिस्टर बीकाणा

ऊंट नृत्य प्रतियोगिता में बजरंग ने पहला, जितेंद्र सिंह ने दूसरा तथा करणी सिंह ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। ऊंट फर कटिंग प्रतियोगिता में मोहन सिंह ने पहला, बंशीधर ने दूसरा तथा जापान की मेघूमी ने तीसरा स्थान हासिल किया। ऊंट सज्जा प्रतियोगिता में लक्ष्मण राम सियाग, इमरान खान तथा मगाराम कुमार क्रमश: पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। कोमल सिद्ध ने मिस मरवण का खिताब जीता। रविंद्र जोशी मिस्टर बीकाणा चुने गए। दूसरे दिन डॉ. करणी सिंह स्टेडियम में 'लोक संध्या' आयोजित हुई। इसमें तेजरासर के बिबू खां फ्यूजन फोक म्यूजिक बैंड ने मनमोहक स्वर लहरियां बिखेरी। बीकानेर की नृत्यांगना मानसी सिंह पंवार ने भवई नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी। इस दौरान महाराष्ट्र का सौनगी मुखौटा नृत्य, हरियाणा घूमर फाग, जम्मू कश्मीर का रहूस नृत्य, पंजाब का भांगड़ा, पुरूलिया का कातक, भरतपुर का मयूर नृत्य और गुजरात का राठवा नृत्य प्रस्तुत किया गया।

देशी-विदेशी पर्यटकों ने कुश्ती, रस्सा-कशी और कबड्डी प्रतियोगिताओं में आजमाया हाथ

तीसरे दिन रायसर के रेतीले धोरों में देशी-विदेशी पर्यटकों का हुजूम रहा। यहां भी पहली बार कार्यक्रम हुए, जहां विभिन्न प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों को हजारों की संख्या में पर्यटकों ने देखा। तीसरे दिन के कार्यक्रमों में पहलवानों ने रेत के समंदर के बीच कुश्ती के दाव-पेंच दिखाए। पुरुष वर्ग में राजस्थान पुलिस और रायसर के बीच कबड्डी का मुकाबला हुआ जिसे राजस्थान पुलिस ने जीता। महिला कबड्डी अंबेडकर सर्किल और राजस्थान पुलिस के बीच खेली गई। अंबेडकर सर्किल टीम ने इसमें विजय हासिल की। मटका दौड़ प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस की राजेश्वरी ज्याणी ने पहला स्थान प्राप्त किया। देशी-विदेशी पर्यटकों के बीच रस्सा-कशी प्रतियोगिता भी हुई। वहीं अर्जेंटीना के युगल ने भारतीय पद्धति से विवाह करते हुए, सभी परंपराओं का निर्वहन किया। सैंड आर्टिस्ट द्वारा रोबीलों और ऊंट की नायाब कलाकृति बनाई गई। हॉट एयर बैलून भी दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रहा। पर्यटकों ने धोरों पर दौड़ लगाई।

अनवर खां के गीत सुन मंत्रमुग्ध हुए श्रोता

अंतिम दिन 15 जनवरी को धोरों पर भव्य सांस्कृतिक संध्या हुई। इसकी शुरुआत पद्मश्री अनवर खान ने 'धरती धोरा री' गीत के साथ की तो वहां मौजूद पर्यटक झूम उठे। उन्होंने 'निबूड़ा-निबूड़ा' और 'यार

मेरी....' सहित एक से एक बढ़कर एक बेहतर गीत प्रस्तुत किए। मशहूर लोकगायिका उषा शर्मा ने गीत प्रस्तुत किए। जसनाथ संप्रदाय के कतरियासर धाम के महंत मोहन नाथ सिद्ध के लोगों ने सान्निध्य में धधकते अंगारों पर अग्नि नृत्य किया। दीपावली के अवसर पर शहरी परकोटे के बारहगुवाड़ में होने वाले बन्नाटी खेल की बेहतरीन प्रस्तुति दी गई।

कोरोना संक्रमण के दौर की सभी पाबंदियों के हटने के बाद हुए महोत्सव ने सफलता का नया अध्याय लिखा। बड़ी संख्या में देशी-विदेशी पर्यटकों ने इसमें भागीदारी निभाई और यहां की सांस्कृतिक विरासत को देश-विदेश तक पहुंचाने का प्रयास किया और अगले वर्ष जनवरी के दूसरे शनिवार-रविवार को उत्सव के 30वें संस्करण में फिर से मिलने का वादा किया।

खेती से बढ़ी आमद अन्नदाता खुशहाल

सुमंत कौशिक
स्वतंत्र लेखक

अलग कृषि बजट से आवंटित धन का बेहतर उपयोग हुआ है। नियमित वार्षिक बजट में सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए कई प्रावधान किए। सिस्टम फंड में बाधाओं को दूर कर बजट का सही तरीके से उपयोग किया गया। पहले कृषि क्षेत्र में हर साल बहुत सारा धन और अनुदान के खजाने में वापस आ जाता था।

उत्पादकता में वृद्धि

अलग कृषि बजट ने राजस्थान में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में मदद की है। अलग कृषि बजट योजना, फंड के बेहतर उपयोग और विपणन रणनीतियों आदि के माध्यम से कृषि उत्पादकता में भिन्नता पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश करता है।

किसानों के लिए ऋण सुविधा में सुधार

चालू वर्ष में कृषि वित्त पर ब्याज दर 4 से 6 प्रतिशत है। अलग से कृषि बजट बनता है तो कृषि वित्त पर ब्याज के प्रतिशत को कम करने में मदद मिलती है।

अवसंरचना सुविधा

ग्रामीण क्षेत्र में अपर्याप्त बुनियादी ढांचे का कारण वार्षिक और पंचवर्षीय योजनाओं में धन की उपलब्धता की कमी और ग्रामीण क्षेत्र में धन के उचित उपयोग की कमी है। सरकार हर साल वार्षिक बजट में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए धन आवंटित करती है, लेकिन उपयोग की कमी के कारण यह धन सरकारी खजाने में वापस आ जाता था। अलग कृषि बजट ने निश्चित रूप से उचित योजना के माध्यम से कृषि के लिए अच्छी बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने में मदद की।

तकनीकों को बढ़ावा देना और कृषि अनुसंधान और विस्तार में सुधार

कृषि अनुसंधान और विस्तार प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण कृषि विकास के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण जरूरतों में से एक है। इन सेवाओं में समय के साथ, सर्वप्रथम बुनियादी ढांचे और संचालन, अप्रचलित शोध व अत्याधुनिक तकनीकों की व्यापक पहुंच के कारण सुधार हुआ है। सार्वजनिक विस्तार सेवाएं किसानों को निम्न स्तर पर ही नवाचार प्रदान करती हैं। अनुसंधान और विस्तार, या इन सेवाओं और निजी क्षेत्र के बीच बहुत कम संबंध है। अलग कृषि बजट ने इस जरूरत को पूरा किया।

छाया: सविता चौहान

मोबाइल फोन से प्राप्त कर सकते हैं योजनाओं की जानकारी

सरकार से जुड़ने के लिए करें सुजस ऐप डाउनलोड

डॉ. विरेंद्र कुमार ढुंढ़ाड़ा
स्वतंत्र लेखक

राजस्थान सरकार का प्रयास है कि हर नागरिक के पास सही जानकारी हो। यही वजह है कि राजस्थान सरकार के निर्णयों, कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध करवाने के लिए सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा सुजस ऐप तैयार किया है। यह सुजस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जयपुर में आयोजित हुई राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी के शुभारंभ के मौके पर इस ऐप को लॉन्च किया था।

उपयोगी सामग्री

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रतिदिन जारी किये जाने वाले ई-बुलेटिन, वीडियो बुलेटिन, सुजस आवाज (न्यूज पॉडकास्ट) के साथ-साथ विभाग द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापन, पोस्टर, सुजस मासिक पत्रिका, जिला दर्शन एवं अन्य संदर्भ सामग्री भी इस ऐप पर उपलब्ध है।

सुजस ऐप में सोशल मीडिया के सभी लिंक जैसे डीआईपीआर, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार को भी इस ऐप पर देखा जा सकता है। विभाग द्वारा जारी सजावटी व सभी विज्ञापन, सभी प्रकाशन, जिला दर्शन पुस्तिका, मासिक सुजस मैग्जीन भी इस ऐप पर उपलब्ध हैं।

इतना ही नहीं, इसमें 'यूजर फीडबैक' नामक एक कॉलम है जिस पर आप अपनी बेशकीमती राय यानी सुझाव भी दे सकते हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की मंशा साफ है। वे चाहते हैं कि

सरकार और आमजन के बीच कोई दूरी न रहे। सरकार के कामकाज पर आमजन की नजर रहे। आमजन सरकार को फीडबैक देते रहें, तभी सरकार बेहतर से बेहतर परिणाम दे सकती है।

युवाओं में लोकप्रिय

यह ऐप युवाओं के बीच काफी पसंद किया जा रहा है। इस ऐप आम जनता के लिए ही नहीं बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भी बेहद फायदेमंद है। अमूमन युवाओं को राजस्थान 'सुजस' मैगजीन के लिए सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालयों में जाना पड़ता है, लेकिन अब सिर्फ सुजस ऐप डाउनलोड कर लेने से उन्हें घर बैठे राजस्थान सरकार व अन्य सरकारी गतिविधियों से रूबरू होने का मौका मिल सकता है। आमजन में 'सुजस मोबाइल एप' की जागरूकता का प्रमाण है कि महज महीने भर में लगभग 50 हजार से अधिक लोगों ने 'सुजस मोबाइल एप' को डाउनलोड कर लिया है। 'सुजस मोबाइल ऐप' राज्य सरकार की अनोखी सौगात है। चूंकि राज्य सरकार ने विगत चार वर्षों के दौरान बच्चों, युवा, प्रौढ़, बुजुर्ग आदि हर वर्ग के लिए बेहतरीन योजनाएं लागू की हैं। इन योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए हरसंभव उपाय किए जा रहे हैं लेकिन जब तक जन जागरूकता नहीं होगी, अधिकाधिक पात्र लोगों को लाभान्वित करना मुनासिब नहीं होता। ऐसे में इस ऐप का महत्व बढ़ जाता है। लिहाजा, सरकार से जुड़िए, 'सुजस मोबाइल एप' डाउनलोड कीजिए। राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को इसके लिए प्रेरित कीजिए।

जनजाति क्षेत्र में गरीबों के लिए नई उम्मीद बन रही कल्याणकारी योजनाएं

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनी वरदान

लाइफ-लाइन बनी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

छाया चौबीसा
सहायक निदेशक, जनसंपर्क

राजस्थान के दक्षिण में अवस्थित जनजाति बहुल जिले डूंगरपुर में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना गरीबों के लिए 'लाइफ लाइन' साबित हो रही है।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की मंशानुरूप आमजन को स्वास्थ्य संबल प्रदान करने तथा निरोगी राजस्थान के सपने को साकार करने में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना डूंगरपुर जिले के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। दूरस्थ क्षेत्रों से डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज तथा चिकित्सालय में गंभीर बीमारियों की चिकित्सा हेतु पहुंचने वाले मरीजों को चिरंजीवी योजना न केवल आर्थिक संबल प्रदान कर रही है वरन गरीब लोगों के लिए आर्थिक संपन्नता नहीं होने से सही चिकित्सा के अभाव में होने वाली अकाल मृत्यु से निज़ात देते हुए 'लाइफ लाइन' साबित हो रही है।

हैंडबॉल के राष्ट्रीय खिलाड़ी का पूरा पैर कटने से बचा

हैंडबॉल के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी प्रकाश कटारा को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नि:शुल्क चिकित्सा ने लगभग छह माह से निराशा और अंधकारमय जीवन से मुक्ति प्रदान कर नई उम्मीद दी है।

डूंगरपुर जिले के मांडवा खापरड़ा के 32 वर्षीय प्रकाश कटारा को जांघ के फेमोरल आर्टरी में ब्लॉकेज की बीमारी हो गई । शुरुआत में उनके दाहिने पैर के अंगूठे के पास अचानक घाव होकर सड़ने लगा। निजी मेडिकल स्टोर पर हेल्पर के रूप में कार्य करने वाले प्रकाश ने छोटे से घाव का शहर के कई निजी चिकित्सालयों में उपचार करवाया । लगातार 20 दिन तक उपचार करने पर भी घाव नहीं भरने से धीरे-धीरे गैंगरीन में बदल गया तथा पैर का अंगूठा और अंगुलियां सड़कर काली पड़ने लगीं। प्रकाश के पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है, ऐसे में समस्त पारिवारिक जिम्मेदारियां भी प्रकाश के कंधों पर हैं। प्रकाश ने अपने परिजन के साथ बड़े शहर के एक निजी चिकित्सालय में इलाज करवाया जहां पर दस हजार की जांचे कर फेमोरल आर्टरी डिजीज की जानकारी दी गई। चिकित्सकों ने बताया कि प्रकाश की दाहिनी जांघ में खून की सप्लाई करने वाली नस में ब्लॉक हो जाने से नीचे पैर तक खून नहीं पहुंच पा रहा है तथा ब्लॉकेज को हटाने के लिए लगभग बारह हजार की दवाइयां दी गई। एक माह तक उपचार लेने के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ तथा पुन: चिकित्सक को दिखाने पर पांव की सर्जरी के लिए डेढ़ लाख रुपये का खर्च बताया गया। साथ ही जांघ में ब्लॉकेज होने के कारण उसके पांव को कूल्हे के पास से काटने की जानकारी दी गई। इस पर प्रकाश पड़ोसी राज्य के बड़े शहर में गया जहां पुन: जाचें कर दवाइयां दी गई तथा वहां पर भी पैर को काटने का सुझाव दिया गया। प्रकाश के पास इतना पैसा नहीं होने के कारण वह अपने गांव लौट आये। इस दौरान उनके पड़ोसी को भी प्रकाश की बीमारी की जानकारी मिली, जिस पर उन्होंने सारी रिपोर्ट लेकर मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर के प्राचार्य को दिखाया। प्राचार्य द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की जानकारी देते हुए तत्काल जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। ऐसे में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम के द्वारा नि:शुल्क ऑपरेशन करते हुए मरीज को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना तथा नि:शुल्क दवा एवं जांच योजना का पूरा-पूरा लाभ देते हुए संपूर्ण इलाज नि:शुल्क किया गया तथा समस्त दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भी चिकित्सालय से नि:शुल्क उपलब्ध करवाये गये। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य बताते है कि कुछ विशेष आवश्यक चिकित्सकीय संसाधनों के लिए चिरंजीवी योजना के तहत पंजीकृत होने से उन्हें मंगवा कर लाभ देते हुए जटिल सर्जरी को पूर्णतः नि:शुल्क करते हुए मरीज तथा उसके परिजनों को राहत प्रदान की गई।

प्रकाश के जीवन में मुख्यमंत्री चिंरजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ने प्रकाश की नई किरण देकर आशा की लौ जगा दी।

नि:शुल्क हुआ कुल्हे का जोड़ प्रत्यारोपण

ऐसे ही एक प्रकरण में डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज से संबंद्ध हरिदेव जोशी जिला चिकित्सालय में अस्थि एवं जोड़ रोग विभाग के प्रोफेसर चिकित्सकों की टीम ने सुदूर प्रतापगढ़ जिले से चिकित्सा के लिए पहुंची 65 वर्षीय वृद्धा के कूल्हों के ज्वॉइंट का अनसीमेंटेड पूर्ण जोड़ प्रत्यारोपण का सफल ऑपरेशन कर नया जीवन दिया है। परिजनों ने राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि ऑपरेशन राज्य सरकार की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पूरी तरह से नि:शुल्क किया गया जबकि निजी चिकित्सालयों में इस हेतु लगभग दो लाख से अधिक खर्च बताया गया था।

चिकित्सालय अधीक्षक ने बताया कि वृद्धा गंगा पत्नी हरीश डामोर निवासी हवाला पारसोला जिला प्रतापगढ़ की कुछ दिन पूर्व घर में ही गिर जाने से कूल्हे की हड्डी टूट गई थी, जिससे वृद्धा चलने-फिरने में असमर्थ हो गई थी। परिजन उसे इलाज के लिए निजी चिकित्सालय में लेकर पहुंचे लेकिन महंगा इलाज होने के कारण दूसरे दिन ही वापस घर आ गए। इसी दौरान डूंगरपुर में निवास करने वाले वृद्धा के रिश्तेदारों ने उन्हें मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के तहत डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में नि:शुल्क उपचार करवाने की सलाह दी। वृद्धा को एंबुलेंस से डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के श्री हरिदेव जोशी सामान्य चिकित्सालय लाया गया जहां पर मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना के तहत नि:शुल्क जांचे कर वृद्धा का केस तत्काल ही अस्थि रोग विभाग के प्रोफेसर को सौंपा और चिरंजीवी योजना में नि:शुल्क ऑपरेशन कर संपूर्ण कुल्हे का जोड़ प्रत्यारोपण किया गया। वृद्धा के परिजनों ने मुख्यमंत्री चिंरजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की सराहना करते हुए कहा कि इस योजना ने उनकी बुजुर्ग मां को नया जीवन दिया है।

तिल्ली के दो टुकड़े, लीवर में चोट : चिरंजीवी योजना ने दिया जीवनदान

ऐसे ही एक अन्य प्रकरण में मेडिकल कॉलेज के श्री हरिदेव जोशी सामान्य अस्पताल में कार्यरत चिरंजीवी मार्गदर्शक पराग चौबीसा सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां उन्हें मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में लाया गया तथा गंभीर हालत को देखते हुए आईसीयू में शिफ्ट किया गया। शरीर से लगातार रक्त स्त्राव की स्थिति बनी हुई थी, जांच करने पर पता चला कि तिल्ली और लीवर में गहरी चोटें आई है । विशेषज्ञों की टीम द्वारा तत्काल ही ऑपरेशन किया गया तो तिल्ली दो टुकड़ों में विभक्त मिली और लीवर में गंभीर चोट होना पाया गया।

मरीज का मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत संपूर्ण इलाज नि:शुल्क किया गया। चिरंजीवी योजना में मिले आर्थिक संबंल और जिला मुख्यालय पर ही मेडिकल कॉलेज में तत्काल हुई सर्जरी की बदौलत मिले जीवनदान से अभिभूत लाभार्थी पराग और उसके परिजनों का कहना है कि राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं और मेडिकल कॉलेज की जिला मुख्यालय पर उपलब्धता के कारण तत्काल ही उपचार होने से उसे जीवनदान मिला है। पराग ने इस कल्याणकारी योजना तथा स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के लिए राज्य सरकार का हृदय से आभार व्यक्त किया।

सरकार का मिला साथ, पीले हुए बेटियों के हाथ

डूंगरपुर जिले में सर्वाधिक बेटियां हुई लाभान्वित

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 15 करोड़ 13 लाख 78 हजार का आर्थिक संबल मिला

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा गरीब एवं असहाय परिवारों की बेटियों को दुल्हन बनाकर विदा करने के स्वप्न को साकार करने तथा उनके परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ने जनजाति बहुल्य जिले डूंगरपुर की चार हजार 973 बेटियों के हाथ पीले कर उन्हें दुल्हन बनाकर विदा करने के परिवारजन के सपनों को साकार किया है।

जिला कलक्टर ने बताया कि आयोजना विभाग द्वारा माह जून 2022 में जारी सूची के अनुसार मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अन्तर्गत प्रदेश में डूंगरपुर जिले में सर्वाधिक बेटियां लाभान्वित हुई है, बावजूद इसके हमारा प्रयास है कि जिले में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए विवाह पंजीयन के समय ही इस योजना हेतु आवेदन करवाया जा सकें, जिससे इस योजना से अधिक से अधिक पात्र लोगों को लाभान्वित किया जा सकें। उन्होंने बताया कि जिन ब्लॉक में न्यून प्रगति है वहां ब्लॉक अधिकारियों को व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए शत-प्रतिशत पात्र को लाभान्वित करने के प्रयास किये जा रहें है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक ने बताया कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा विभाग के माध्यम से बी.पी.एल., अन्त्योदय, विधवा माता की प्रथम दो पुत्रियों के विवाह पर राज्य सरकार द्वारा उनकी शैक्षिक अर्हता एवं नियम अनुसार पात्रता के आधार पर 21 हजार से लेकर 51 हजार तक की राशि देय होती है।

उन्होंने बताया कि आयोजना विभाग की ओर से अप्रैल से जून 2022 तक जारी सूची के अनुसार प्रदेश भर में डूंगरपुर जिले में सर्वाधिक बेटियां योजनान्तर्गत लाभान्वित हुई तथा वर्तमान में डूंगरपुर जिले में अब तक कुल 5827 आवेदनों में से 4973 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान करते हुए कुल 15 करोड़ तेरह लाख 78 हजार का आर्थिक संबल प्रदान किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इसमें से 557 आवेदन नियमानुसार अपात्र होने से अस्वीत किये गये है तथा 257 आवेदन ऑब्जेक्शन में है तथा शेष आवेदन प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि जिले में सर्वाधिक सागवाड़ा ब्लॉक में 807 बेटियों को लाभान्वित किया गया है वहीं बिछीवाडा ब्लॉक में 696, दोवडा ब्लॉक में 691, डूंगरपुर ब्लॉक में 626, गलियोकोट ब्लॉक में 614, चिखली ब्लॉक में 566, सीमलवाडा ब्लॉक में 357, झौंथरी ब्लॉक में 397, आसपुर ब्लॉक में 157 तथा साबला ब्लॉक में 62 आवेदन स्वीकृत कर कुल चार हजार 973 बेटियों को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत लाभान्वित किया गया है।

सपने जैसा था बेटी का विवाह करवाना

डूंगरपुर जिले के नगरीय क्षेत्र गरीब नवाज कॉलोनी निवासी एजाज हुसैन कंधारी पिता इनायत हुसैन कंधारी ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आर्थिक संबल से लाभान्वित होने पर राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हुए संबंधित ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी क्रमश: पिंकी मीणा को बताया कि पुत्री का विवाह करवाना उनके लिए एक सपने जैसा था। आर्थिक तंगी के चलते पुत्री का विवाह करवाना बहुत कठिन लग रहा था। कही से कोई आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद भी नहीं थी। वे बताते है कि तब उन्हें राज्य सरकार की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत संचालित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की जानकारी मिली। उन्होंने विभाग में जाकर आवेदन कर समस्त दस्तावेजों प्रस्तुत किए जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन किया गया।

विभाग को आवेदन प्राप्त होते ही स्वीकृत कर योजनान्तर्गत राशि रुपये 51 हजार रुपये लाभार्थी को पे-मेनेजर के माध्यम से खाते में डीबीटी कर दिये गये। इस राशि के प्राप्त होने से लाभार्थी का मायूस चेहरा खिल उठा। लाभार्थी ने बेटी के विवाह के आर्थिक व्यय के पुनर्भरण में सहायता मिलने से परिवार को मिली बड़ी राहत हेतु मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

गरीब के लिए वरदान है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

ऐसे ही एक अन्य प्रकरण में ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को पंचायत साबला निवासी श्री रामचन्द्र कटारा एवं उनकी पत्नी भुल देवी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में मिली आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहती हैं कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से उन्हें अपनी बेटी के विवाह में बहुत बड़ा सहारा मिल गया। उन्होंने बताया कि एक गरीब पिता अपनी बेटी ब्याहने के लिए प्राय: कर्ज में उलझता है पर अब इस योजना से मिलने वाले आर्थिक सहयोग से गरीब व्यक्ति को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने बताया कि इस योजना में बेटी की शिक्षा के आधार पर 51 हजार का आर्थिक सहयोग मिलने से शिक्षा का महत्व भी समझ आया है। बेटी के शिक्षित होने से उन्हें नियमानुसार अधिक आर्थिक सहयोग मिल सका। उन्होंने इस योजना को गरीब के लिए वरदान बताया।

4 साल के राजपाल की हुई हायपोस्पेडियस सर्जरी

नौनिहाल के साथ नियति ने कहर ढाया चिरंजीवी योजना ने स्वस्थ कर दिखाया

कल्पना डिंडोर
सहायक निदेशक जनसंपर्क

आमजन को सेहत की सुरक्षा और स्वास्थ्य रक्षा को लेकर जीवन भर के लिए चिन्ताओं से मुक्त करा देने वाली मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना आदिवासी बहुल बांसवाड़ा जिले के मरीजों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। इसे स्वास्थ्य लाभ पाने वाला मरीज ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार हमेशा याद रखेगा।

बांसवाड़ा जिले की छोटी सरवन पंचायत समिति अन्तर्गत कोटड़ा गांव के आदिवासी परिवार के नौनिहाल राजपाल के साथ नियति ने कहर ढाया मगर राजस्थान सरकार की इस योजना ने उसे स्वस्थ कर दिखाया और आज राजपाल सामान्य जीवन जीता हुआ आगे बढ़ रहा है।

चार वर्षीय राजपाल को पेशाब में दिक्कत आ रही थी। इससे वह परेशान था। मेहनत-मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करने वाले पिता श्री गौतमलाल और पूरे परिवार को इस चिन्ता ने घेर लिया। बीमारी दिखाने राजपाल को उसके पिता छोटी सरवन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले गए, जहां आरंभिक चिकित्सकीय जांच के बाद सामने आया कि उसकी पेशाब नली अंदर की तरफ थी। इस कारण पेशाब में काफी दिक्कत हो रही थी। चिकित्सक ने ऑपरेशन की राय दी। इस पर गरीबी के कारण इलाज के खर्च की सोच कर पिता और अधिक चिन्तित हो उठे। जब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सारा ऑपरेशन और इलाज फ्री होगा। तब जाकर उन्हें राहत मिली। जनाधार कार्ड, आधार कार्ड आदि दस्तावेज मंगवाए जिनसे स्पष्ट हो गया कि राजपाल का परिवार मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकृत है। इसके बाद छोटी सरवन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के डॉक्टरों ने उदयपुर के एक अस्पताल के डॉक्टरों से बात की और राजपाल को उदयपुर रेफर किया गया।

छोटी सरवन बीसीएमओ ने बताया कि उदयपुर के एक निजी अस्पताल में राजपाल की हायपोस्पेडियस सर्जरी हुई। सारा इलाज नि:शुल्क हो गया। राजपाल अब पूर्ण रूप से स्वस्थ है। राजपाल के पिता गौतमलाल ने इसके लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत और सरकार का आभार जताते हुए कहा कि सरकार ने उसके बेटे के लिए जो कुछ किया है उसे कभी भुला नहीं पाएगा। राजपाल को नई जिन्दगी दिलाने में मददगार बने को भी धन्यवाद देने से नहीं चूकते, जिनकी बदौलत उनके लाल को शारीरिक समस्या से मुक्ति प्राप्त हुई।

जिला कलक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को सख्त निर्देश दे रखें हैं कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जानकारी के अभाव में कोई भी पात्र एवं जरूरतमन्द व्यक्ति लाभ लेने से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए सभी चिकित्सक अपने - अपने क्षेत्र में रुचि लें और परिवार को सहयोग करें। इसके बाद जिले में अस्पतालों में आने वाले लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजना की जानकारी दी जा रही है और स्थानीय डॉक्टर मेडिकल कॉलेज और अन्य निजी अस्पतालों में भी बातचीत कर इस योजना का लाभ दिलवा रहे हैं।

हायपोस्पेडियस सर्जरी

चिकित्सकों के अनुसार लड़कों में जन्म से ही होने वाली एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या है जिसमें उनका पीनस असामान्य होता है। पीनस के टिप पर होल (छेद) नहीं होता, बल्कि यह पीनस के अंत में या मीडिल में हो सकता है, या अंडकोष में भी हो सकता है। यह एक सामान्य जन्मजात समस्या है जो 200 में से एक बच्चे में पाई जाती है। इस समस्या को ठीक करने के लिए हायपोस्पेडियस सर्जरी की जरूरत पड़ती है।

हस्तशिल्प और औद्योगिक विकास के सुनहरे आयाम

पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव

डॉ. दीपक आचार्य
उपनिदेशक जनसंपर्क

आकांक्षा पालावत
जनसंपर्क अधिकारी

जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान में जिला प्रशासन, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र, रीको तथा नोडल एजेंसी मरुधरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, जोधपुर के संयुक्त तत्वावधान में 6 से 15 जनवरी तक आयोजित 33वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव आशातीत सफलता एवं उल्लेखनीय उपलब्धियों की दृष्टि से यादगार छाप छोड़ गया। 'विकासशील राजस्थान-उद्यमशील राजस्थान' की मुख्य थीम पर केन्द्रित यह उत्सव हस्तशिल्प और औद्योगिक विकास की दिशा में कई नवीन और सुनहरे आयाम दर्शाने वाला रहा। जोधपुर में 33 साल पहले सूचना केंद्र में शुरू हुआ हस्तशिल्प उत्सव आज विशाल स्वरूप ले चुका है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने किया।

जोधपुर में हुए विकास कार्यों, नवाचारों की झलक भी प्रदर्शनी में देखने को मिली। जोधपुर में देश की सभी बड़ी आईआईटी, निफ्ट, आयुर्वेद विश्विद्यालय सहित तमाम संस्थाएं एक साथ हैं। उत्सव के अन्तर्गत सी-वर्ल्ड, भगवान शिव की विशालकाय प्रतिमा, जोधपुर के मेहरानगढ़ किले एवं घंटाघर, सदर मार्केट की प्रकृतियों सहित जोधपुर के उद्योगों में निर्मित एवं जोधपुर से निर्यात होने वाले बेहतरीन हस्तशिल्प व केंद्रीय पंडाल में सुसज्जित विभिन्न उत्पाद दर्शकों एवं जोधपुर वासियों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बने।

राजस्थान में औद्योगिक विकास से लेकर हर तरह का विकास हुआ है। इससे विकास का सुनहरा स्वरूप सामने आया है। लघु कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़े कार्यों में जोधपुर ने देश-दुनिया में नाम कमाया है। कम संसाधनों के बावजूद प्रदेश में हस्तशिल्प क्षेत्र ने प्रगति की है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से राजस्थान का सुनहरा भविष्य है।

लगभग 750 स्टॉल्स के माध्यम से देश के 18 राज्यों से 700 से अधिक हस्तशिल्पियों और उद्यमियों ने हिस्सा लेकर उद्योग और हस्तशिल्प से जुड़े तमाम आयामों का दिग्दर्शन कराया। इस उत्सव के माध्यम से उद्योगों के विकास, नए व आधुनिक अपडेट, नवाचार, जोधपुर के पुराने हाट बाजार की तर्ज पर थार के रेगिस्थान में समुद्र का अहसास कराने के लिए सी-वर्ल्ड, देवाधिदेव महादेव का मुग्धकारी आभामंडल आदि आकर्षण के केंद्र रहे।

बहुआयामी गतिविधियां

उत्सव बहुआयामी औद्योगिक, सांस्कृतिक गतिविधियों और स्पर्धाओं से भरा रहा। इस दौरान औद्योगिक विकास, हस्तशिल्प और इनसे जुड़े विषयों पर विभिन्न प्रतिष्ठानों के प्रतिष्ठित उद्यमियों, विशेषज्ञों, विभागों एवं संस्थाओं से संबंधित अधिकारियों आदि की वार्ताओं, सेमीनारों, परिचर्चाओं के साथ ही रोजाना नई-नई विधाओं में सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने लोकानुरंजन करते हुए उत्सव में आए लोगों को आनंदित किया।

उत्सव के दौरान पश्चिमी राजस्थान में निवेश, मुख्यमंत्री लघु उद्यम, जोधपुर में मेडिकल डिवाइस उद्योग संभावनाओं, स्टार्टअप, सवस इंडस्ट्री सहित तमाम प्रकार की इंडस्ट्रीज के उपयोग, उद्योग रत्न पुरस्कार, औद्योगिक विकास की दृष्टि से प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं, रियायतों, प्रोत्साहन गतिविधियों, राज्य की पर्यावरण नीति व पर्यावरणीय मानकों, जल संरक्षण तथा जल के पुनर्उपयोग, टेक्सटाइल उद्योगों के दूषित जल उपचार संयंत्र, प्रारंभिक परीक्षण, पायलट कुशल प्रदर्शन संयंत्र, संयंत्र के परिचालन अनुभव, संयंत्र संचालन में आने वाली चुनौतियों, उपलब्धियों, प्रमुख लाभ, सीवरेज अपशिष्ट के शोधन, सीवरेज कीचड़ स्रोत, रेडियेशन/विकिरण शोधन संयंत्र, जोधपुर में सस्टेनेबल वाटर पर आईआईटी द्वारा किये जा रहे प्रयासों, औद्योगिक दूषित जल के उपचार संयंत्र, पानी के दबाव संचालित मार्ग, प्रयोगात्मक अध्ययन, औद्योगिक दूषित पानी के उपचार हेतु अभिनव प्रबंधन पर विस्तार से जानकारी दी।

उत्सव में प्रदूषण नियंत्रण प्रबंधन के लिए मजबूत कदम, स्मार्ट सप्लाई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हस्तशिल्प निर्यात के लिए डिजाइन एवं प्रलेखन, मिशन निर्यातक बनो, श्रम एवं रोजगार, इमिटेशन ज्वैलरी किट मेकर, इमिटेशन विनिर्माण, युवाओं के लिए स्टार्टअप, प्रदेश की कृषि नीति, कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन, कृषि क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाएं एवं कृषक मेला, पूंजी बाजार में निवेश, निर्यात संवर्द्धन

योजनाओं, हस्तशिल्प प्रोत्साहन के लिए सरकार की योजनाओं आदि कई विषयों पर कार्यक्रम हुए। इन कार्यक्रमों में सफल उद्यमियों ने अपने जीवन, हुनर और उद्यम की उत्तरोत्तर प्रगति से जुड़े अनुभव साझा करने के साथ ही उद्यम की तरक्की से समृद्धि का सफर तय करने से संबंधित टिप्स भी दिए।

उत्साही जनभागीदारी, सभी का भरपूर योगदान

उत्सव आयोजन की विभिन्न गतिविधियों में नेशनल जूट बोर्ड, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), भारत संचार निगम लि., हस्तशिल्प निर्यात संवर्द्धन परिषद, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर नगर निगम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, एजी एंड पी, प्रथम गैस, नाबार्ड, जोधपुर आर्टिजंस वेलफेयर प्रोडयूसर कंपनी लि. एवं मीडियागढ़, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, जोधपुर शेयर हॉल्डर्स एसोसिएशन आदि की साझा मेजबानी उल्लेखनीय रही।

वीरों का सम्मान

स्वामी विवेकानंद जयंती पर वीर योद्धा सम्मान समारोह में वर्ष 1965 एवं वर्ष 1971 के युद्ध के दौरान शहीद हुए वीरों के परिवारजनों एवं वर्ष 1965 एवं 1971 के युद्ध में भाग लेने वाले वीर सैनिकों का सम्मान किया गया। इसमें 104 वर्षीय सेवानिवृत्त सूबेदार सी.पी. जोशी, आजादी से पूर्व शहीद हुए हाईफा हीरो मेजर दलपत सिंह देवली के पुत्र गंगासिंह सहित वर्ष 1965 एवं 1971 के युद्ध में परमवीर चक्र एवं अन्य वीरता सम्मान प्राप्त सहित अन्य पूर्व सेनाधिकारियों और सैनिकों व उनके परिजनों सहित 66 व्यक्तियों का सम्मान किया गया।

महिलाओं और बच्चों के लिए कार्यक्रम

महिला दिवस मनाते हुए महिलाओं के लिए ब्लू सिटी दिवा ब्यूटी कॉन्टेस्ट, मेहंदी एवं कुकिंग विदाउट फ्लेम प्रतियोगिता, विद्यार्थियों के लिए क्ले मोल्डिंग प्रतियोगिता-स्कूडल, महिलाओं के लिए योगा प्रशिक्षण एवं आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम, क्लाउड किचन व फूड इंडस्ट्रीज में अपार संभावनाओं, घर से स्व-रोजगार, महिला उत्थान, स्वावलंबन आदि पर कार्यक्रमों में उत्साही भागीदारी देखी गई।

मूक बधिर विद्यालय के बच्चों ने लिया लुत्फ

जोधपुर के माता का थान, बासनी तंबोलिया स्थित गांधी बधिर सीनियर सैकंडरी स्कूल और गांधी बधिर महाविद्यालय के लगभग 225 से अधिक बच्चों ने मेले का अवलोकन किया।

साहित्य का वितरण

उत्सव में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रचार साहित्य वितरण के लिए अलग से स्थापित स्टॉल से राज्य सरकार के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा जारी बहुआयामी बुकलैट्स, फोल्डर्स, पुस्तिकाएं आदि प्रचार साहित्य का वितरण किया गया।

प्रदेश के विकास को रफ्तार देगी नई एमएसएमई नीति

नीतिगत बदलावों से एमएसएमई क्षेत्र में मॉडल स्टेट बन रहा राजस्थान

सुनील सिंह शेखावत
सहायक जनसंपर्क अधिकारी

राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले (एमएसएमई) क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार प्रदेश में एमएसएमई के लिए अनुकूल माहौल बनाने में जुटी है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में करीब 24 फीसदी योगदान देने वाले इस क्षेत्र की वृद्धि के लिए प्रदेश सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नीति, 2022 लेकर आई है। इस नीति से प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र का कायापलट होने की उम्मीद है।

सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग (एमएसएमई) न केवल बड़े उद्योगों के मुकाबले कम पूंजी लागत में ज्यादा रोजगार के मौके मुहैया कराते हैं बल्कि वे ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण में भी सहयोग देते हैं। इस तरह वे क्षेत्रीय अंसतुलन को कम करते हैं। रोजगार देने के मामले में कृषि के बाद एमएसएमई क्षेत्र की दूसरी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है। राजस्थान क्षेत्रफल के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की 40 फीसदी भूमि दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे (डीएमआईसी) के दायरे में आती है। राजस्थान शांत और राजनीतिक रूप से स्थिर राज्य है, जो बहुत से क्षेत्रों में लाभप्रद निवेश के मौके मुहैया करा रहा है। राज्य के कुल उद्यमों में से करीब 98 फीसदी एमएसएमई श्रेणी में आते हैं। ये एमएसएमई कारपेट विनिर्माण, कपड़ा, खनन, कृषि, धातु शिल्प, फुटवियर आदि से संबंधित हैं। राजस्थान में पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन और कुशल प्रतिभाएं हैं, जो औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए बहुत अहम हैं। राज्य अपने आर्थिक गलियारों (कॉरिडोर) जैसे भारतमाला आर्थिक कॉरिडोर और ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के जरिये औद्योगिक वृद्धि के लिए शानदार मौके मुहैया करा रहा है। राजस्थान पेट्रोलियम, केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्र (राजस्थान पीसीपीआईआर) बाड़मेर, जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (जेपीएमआईए) और खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराणा (केबीएन) निवेश क्षेत्र उन कुछ अहम बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में शामिल हैं, जो एमएसएमई तथा मोटे निवेश को लुभा सकती हैं और स्थानीय आबादी के लिए रोजगार के मौके पैदा कर सकती हैं। राज्य सरकार एमएसएमई नीति के जरिये अपने एमएसएमई के लिए वृद्धि का एक नया दौर शुरू करना चाहती है।

एमएसएमई नीति का उद्देश्य

इस एमएसएमई नीति का मकसद सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता तथा सुविधाजनक नियामकीय माहौल उपलब्ध कराकर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात में उनके योगदान को बढ़ाना है। नीति का लक्ष्य कुल 10,000 करोड़ रुपये के निवेश से 20,000 नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना और एक लाख लोगों के लिए रोजगार पैदा करना है। इस नीति के तहत 9,000 एमएसएमई को जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (जेड) प्रमाणपत्र दिए जाएंगे।

नियामकीय सरलता, वित्तीय सहायता, तकनीक अपग्रेडेशन, उद्यमिता विकास, निर्यात में मदद और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को सहायता जैसी रणनीतिक पहलों से नीति के विजन और उद्देश्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। इस पॉलिसी की अवधि पांच साल होगी। राजस्थान सरकार ने सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम और ए-वन स्टॉप ऐप फैसिलिटी- राजनिवेश विकसित की है, जो एमएसएमई निवेशकों को नियामकीय मंजूरी और राजकोषीय प्रोत्साहन हासिल करने में मदद देगी। औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (आरआईएसएफ) की स्थापना का प्रस्ताव रखा है।

इज ऑफ डूइंग बिजनेस

राज्य सरकार ने नियामकीय सुधारों और पंजीकरण की प्रक्रियाओं को आसान बनाकर राज्य में कारोबारी माहौल को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। राजस्थान सरकार राज्य में कारोबार करने के लिए एमएसएमई को मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं को सुधारने की खातिर आगे भी नए कदम उठाती रहेगी।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने राज्य में एमएसएमई के लिए माहौल को सुधारने के लिए निम्न कदम उठाए हैं :

- प्रोत्साहन एवं सब्सिडी हासिल करने की प्रक्रिया को पूर्णतया डिजिटल बना दिया गया है।
- रीको ने एमएसएमई के लिए भूमि की उपलब्धता और आवंटन

की प्रक्रिया को ऑनलाइन बना दिया है।

- पॉलिसी में एमएसएमई को अपने सुचारू परिचालन के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन और सहायता उपलब्ध कराने की बात कही गई है।
- राजस्थान सरकार ने राज्य में सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों की स्थापना और रोजगार के नए मौके पैदा करने के लिए एक ब्याज सब्सिडी योजना- मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 10 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 5 से 8 फीसदी तक की ब्याज सब्सिडी मुहैया कराई जाती है।
- पॉलिसी के अंतर्गत लघु एवं मझोले उद्योगों (एसएमई) को एसएमई प्लेटफॉर्म के जरिये पूंजी जुटाने में मदद दी जाएगी।
- राज्य सरकार औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष एमएसएमई शाखाएं खोलने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ गठजोड़ करेगी, जिससे एमएसएमई को फायदा मिलेगा।

एमएसएमई को भूमि

राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में 147 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे राज्य में एमएसएमई की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा। तकनीक आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने सलारपुर, ग्रेटर भिवाड़ी और बोरानाड़ा (जोधपुर) में बहुमंजिला औद्योगिक कॉम्पलेक्स स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है।

स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र

तकनीकी प्रगति का लाभ लेने और औद्योगिक बुनियादी ढांचे की बदलती जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना बनाई है। इन स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्रों में वे उन्नत बुनियादी ढांचा सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिनकी एमएसएमई को जरूरत होती है।

क्षमता निर्माण- कौशल एवं प्रशिक्षण

राज्य सरकार शैक्षणिक संस्थानों, शोध एवं विकास संगठनों और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मदद से मौजूदा औद्योगिक कामगारों के प्रशिक्षण के जरिये कौशल संवर्धन करेगी।

वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल करने में बढ़ोतरी

सभी क्षेत्रों में तकनीक बदल रही है, जिससे उद्यमों के लिए नए उन्नत तकनीक समाधानों का इस्तेमाल कर मौजूदा बाजार जरूरतों से कदम-ताल मिलाना और अपने परिचालन में सुधार करना जरूरी हो गया है। एमएसएमई में मौजूदा तकनीक को अपग्रेड करने और नई तकनीकों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार अपनी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति (रिप्स) 2019 के तहत इंडियन

इंस्टीटूट अफ साइंस और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे प्रीमियर संस्थानों से एडवांस तकनीक हासिल करने पर आने वाली लागत का 50 फीसदी रीइंबर्स कर रही है। हालांकि किसी एक इकाई को अधिकतम 10 लाख रुपये तक की राशि ही दी जा सकती है।

एमएसएमई का वर्गीकरण

प्लांट एवं मशीनरी पर एक करोड़ रुपये तक के निवेश एवं 5 करोड़ रुपये तक के सालाना कारोबार (Turn over) वाली इकाइयों को सूक्ष्म इकाई माना जाता है। प्लांट एवं मशीनरी पर 10 करोड़ रुपये तक के निवेश और 50 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाली इकाइयां लघु इकाई की श्रेणी में आती हैं। वहीं प्लांट एवं मशीनरी पर 50 करोड़ रुपये तक के निवेश और 250 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाली इकाइयां मझोली इकाइयों की श्रेणी में आती हैं।

प्रोत्साहन एवं पुरस्कार

इस नीति में उद्यमों से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं जैसे एमएसएमई कलस्टर्स का विकास, गुणवत्ता सुधार, विपणन एवं व्यवसाय विकास के लिए सहायता, निर्यात प्रोत्साहन सहायता, व्यवसाय एवं सेवाओं को बढ़ावा, महिला उद्यमियों का सशक्तीकरण एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और नि:शक्तजन श्रेणियों के लिए विशेष प्रावधान, पर्यावरण संरक्षण में सहायता करने के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले उद्यमों को प्रोत्साहन और पुरस्कार प्रदान करने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान समाहित किए गए हैं।

4 साल में 37 लाख 33 हजार को मिला रोजगार

गौरतलब है कि राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम-2019 अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य राजस्थान की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का योगदान बढ़ाना था। इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले और राजस्थान में एमएसएमई क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ा है। इस क्षेत्र से प्रदेश में विगत चार वर्ष में 37 लाख 33 हजार 628 लोगों को रोजगार मिला है और जीडीपी में इसका योगदान 24.50 प्रतिशत आंका गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में एमएसएमई उद्योगों का कुल निर्यात 72 हजार करोड़ रुपये का रहा है, जो एक बड़ी उपलब्धि है।

राजस्थान हस्तशिल्प नीति –2022

प्रदेश के अनूठे शिल्प–सौंदर्य को मिली परवाज

राजस्थान विश्व भर में अपने कला कौशल और सांस्कृतिक वैविध्य के लिए प्रसिद्ध है। मेवाड़ हो या मारवाड़, हाड़ौती हो या ढूंढाड़ यहां के शिल्प–सौंदर्य की विशिष्टता और अनूठापन देशी–विदेशी पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करता है। राजस्थान के सभी भौगोलिक अंचलों में हस्तशिल्प का कार्य वृहद स्तर पर किया जाता है। इसमें जयपुर का सांगानेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट, लाख की चूड़ियां, जोधपुर का बंधेज एवं बादला, बाड़मेर का अजरक और मलीर प्रिंट, दाबू प्रिंट, आकोला प्रिंट, कोटा डोरिया, बीकानेर की मथैरण कला, उस्ता कला और मुनव्वत कला, प्रतापगढ़ की थेवा कला, सालावास में दरी निर्माण, मोलेला की टेराकोटा कला, गलियाकोट की रमकड़ा कला, ब्लू पॉटरी, नाथद्वारा की पिछवाई पेंटिंग, टोंक का नमदा, मूर्तिकला, कांच कशीदाकारी, मीनाकारी, कुंदन कला, काष्ठ कला, कठपुतली कला, कावड़, दरी एवं कालीन, पट्टू बुनाई कला, जाजम, भित्ती–चित्र, फड़ चित्रण, सांझी कला, मांडणा कला, तोरण निर्माण और पातरे तिरपणी आदि हस्तशिल्प कलाएं उल्लेखनीय हैं।

हस्तशिल्प से रोजगार के साथ विदेशी मुद्रा भी राज्य को प्राप्त होती है। राज्य में लगभग 6 लाख हस्तशिल्पी हैं। राज्य से वर्ष 2020–21 में 6205.32 करोड़ रुपये के हस्तशिल्प का निर्यात हुआ है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउन्सिल द्वारा हस्तशिल्प कार्यों के लिए जयपुर शहर को 'वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी' घोषित किया गया है।

राज्य सरकार ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2019 में हैण्डीक्राफ्ट सेक्टर को थ्रस्ट सेक्टर में शामिल किया है।

इन तथ्यों से दृष्टिगत होता है कि हस्तशिल्प के संवर्धन, रोजगार सृजन और निर्यात प्रोत्साहन के लिए हस्तशिल्प नीति आवश्यक थी। राज्य सरकार ने 17 सितंबर, 2022 को प्रदेश की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की। यह नीति 31 मार्च, 2026 तक प्रभावी रहेगी।

अभय सिंह
सहायक जनसंपर्क अधिकारी

हस्तशिल्प नीति का प्रमुख उद्देश्य

राज्य के हस्तशिल्पियों का आर्थिक उत्थान एवं विकास, उनके उत्पादों के लिए बेहतर मार्केटिंग की व्यवस्था करना और उन्हें सशक्त बनाते हुए उनकी राज्य के विकास में भागीदारी सुनिश्चित करना।

राज्य के हस्तशिल्पियों के उत्पादों को निर्यात योग्य बनाना एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना व निर्यात में राज्य की भागीदारी बढ़ाना। विलुप्त होती परम्परागत हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना। हस्तशिल्प के क्षेत्र में आगामी 5 वर्षों में 50,000 नये रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

हस्तशिल्प नीति के प्रमुख प्रावधान

ब्रांडिंग : वन डिस्ट्रिक्ट–वन प्रोडक्ट : राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला–एक उत्पाद (One District One Product) योजना के अन्तर्गत कम–से–कम एक हस्तशिल्प उत्पाद को चिह्नित कर प्रोत्साहित किया जायेगा। राज्य के शिल्पकारों के उत्पादों की गुणवत्ता के लिए बार कोड, टेगिंग, भारतीय मानक संस्थान (ISI) मार्क, भौगोलिक संकेतक (GI), हॉलमार्क आदि को प्रोत्साहन दिया जाएगा। राज्य स्तर पर ई–पोर्टल व मोबाइल ऐप का विकास किया जाएगा। राज्य की हस्तकलाओं एवं हैण्डलूम के उत्पादों का प्रचार–प्रसार एवं राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए सेलिब्रिटी या इस क्षेत्र के प्रख्यात व्यक्तित्व की सेवाएं ब्रांड ऐम्बेसेडर के रूप में ली जाएंगी।

संस्थागत विकास से हस्तशिल्प की वैश्विक पहुंच सुगम : उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधीन हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय की स्थापना की जाएगी। निदेशालय विपणन, विक्रय प्रोत्साहन, ई–

कॉमर्स, विभागीय समन्वय और निर्यात प्रोत्साहन संबंधी कार्य संपादित करेगा। राज्य में हस्तशिल्प उत्पादों के निर्यात में और वृद्धि करने एवं इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित करने, विश्व में बदलती हुई परिस्थितियों एवं मांग के अनुरूप हस्तशिल्प डिजाइन विकास, कौशल विकास एवं तकनीकी उन्नयन के उद्देश्य से जोधपुर में हैण्डीक्राफ्ट डिजाइन सेन्टर स्थापित किया जाएगा। इस सेन्टर को हस्तशिल्पियों के लिए उत्कृष्टता केन्द्र (Centre of Excellence) के रूप में भी विकसित किया जायेगा। परम्परागत हस्तकलाओं के विकास, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करने एवं उत्पादों के विपणन की व्यवस्था के लिए रीको द्वारा हैण्डीक्राफ्ट पार्क विकसित किये जाएंगे।

उद्यम प्रोत्साहन संस्थान के राजस्थान हाट, जलमहल, जयपुर में राज्यस्तरीय हस्तशिल्प म्यूजियम स्थापित कराने की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त राज्य के अन्य 13 जिलों में स्थित शहरी एवं ग्रामीण हाटों यथा अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, नाथद्वारा (राजसमन्द), चित्तौड़गढ़, कोटा, सीकर, दौसा, भरतपुर एवं झुन्झुनूं में लघु हस्तशिल्प म्यूजियम स्थापित किये जाएंगे।

आधारभूत संरचना का विकास : राज्य के क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हस्तशिल्प एवं हथकरघा कलस्टर चिन्हित कर आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा। पर्याप्त संख्या में शिल्पियों के परिवार उपलब्ध होने पर क्षेत्र विशेष को क्राफ्ट विलेज के रूप में विकसित किया जायेगा। क्राफ्ट विलेज का पर्यटन विभाग के साथ समन्वय कर पर्यटन, लोक कला एवं संस्कृति के साथ-साथ हस्तकलाओं को प्रोत्साहित किया जायेगा। राज्य के दस्तकारों एवं बुनकरों के क्लस्टर्स के लिए कॉमन फैसिलिटी सेन्टर्स स्थापित करने के लिए रीको औद्योगिक क्षेत्रों में 5,000 वर्ग मीटर तक के भूखंड 31 वर्ष की लीज पर रियायती दर पर उपलब्ध करवाये जायेंगे।

वित्तीय प्रोत्साहन से उद्यमशीलता को बढ़ावा : दस्तकारों को तीन लाख रुपये तक के ऋण पर शत-प्रतिशत ब्याज राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। स्थायी विक्रय केन्द्र स्थापित करने पर कुल लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम एक लाख रुपये जो भी कम हो, तक की सहायता राशि प्रदान कराई जायेगी।

राजस्थान हस्तशिल्प सप्ताह : राज्य के हस्तशिल्पियों के उत्पादों की विपणन व्यवस्था, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने एवं अन्य राज्यों में तैयार शिल्प से गुणवत्ता में सुधार एवं उत्पादों को मार्केटेबल बनाने की दृष्टि से प्रत्येक वर्ष दिसम्बर माह में राष्ट्रीय स्तर के हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन राजस्थान हाट, जयपुर में किया जायेगा। आयोजन में देश की शिल्पकलाओं का प्रदर्शन, राज्य की प्रमुख लोक कलाओं के सांस्कृतिक कार्यक्रम और राज्य के प्रमुख व्यंजनों का प्रदर्शन किया जाएगा।

हस्तकलाएं प्रलेखित और पुनर्जीवित की जाएंगी : राज्य की प्रमुख हस्तकलाओं, हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पाद, चित्रकारी, छपाई कला, रंगाई कला, कढ़ाई कला, शिल्प कला के सिद्धांतों एवं विधियों को विषय विशेषज्ञों के सहयोग से प्रलेखित किया जाएगा। हस्तशिल्प कलाओं को आम व्यक्ति से परिचय कराने, विलुप्त होती शिल्प कलाओं को पुनर्जीवित करने तथा रोजगार के नये अवसर सृजित करने के उद्देश्य से प्रत्येक माह राज्य स्तर, क्षेत्रीय स्तर तथा जिला स्तर पर राज्य के शिल्प पर आधारित सेमिनार एवं वर्कशॉप आयोजित होंगे।

प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तैयार होगा डाटाबेस : राज्य की हस्तकलाओं को चिन्हित कर शिल्पकलाओं एवं हस्तशिल्पियों का सर्वे कर डाटा बेस तैयार किया जायेगा जिससे हस्तशिल्प नीति के प्रावधानों को राज्य में बेहतर रूप से क्रियान्वित किया जा सकेगा।

हस्तशिल्प स्मृति चिन्ह : सरकारी कार्यक्रमों, पुरस्कारों, सम्मान समारोह में राजस्थान में बने हस्तशिल्प को स्मृति चिन्ह के रूप में दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

सम्मान से बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा : हस्तशिल्प सप्ताह के अवसर पर राज्य स्तरीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला हस्तशिल्पी, सर्वश्रेष्ठ युवा हस्तशिल्पी (35 वर्ष की आयु तक), विलुप्त होती परम्परागत हस्तकलाओं में विशेष योगदान देने वाले दस्तकार और हस्तशिल्प निर्यात क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले निर्यातक श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे।

सामाजिक सुरक्षा से सशक्तीकरण: 18 से 50 वर्ष की आयु के दस्तकारों एवं बुनकरों, हस्तशिल्प एवं हथकरघा क्लस्टर्स के लिए समूह बीमा की सुविधा प्रदान कराई जायेगी। हथकरघा बुनकरों के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना संचालित है। बुनकर प्रीमियम राशि के अंश में राज्य सरकार द्वारा योगदान दिया जायेगा। राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार प्राप्त दस्तकारों एवं बुनकरों के बच्चों को मान्यता प्राप्त हस्तशिल्प एवं हथकरघा संस्थान से हस्तशिल्प एवं टेक्सटाइल विषयों में डिग्री, डिप्लोमा में प्रवेश पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

हर क्षेत्र में आ रहा व्यापक निवेश

उद्योग, अक्षय ऊर्जा और पर्यटन क्षेत्र में 1.36 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं के एमओयू

अमन दीप विश्नोई
जनसंपर्क अधिकारी

अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और प्रदेश के सर्वांगीण विकास में उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकार की नीतियों से प्रदेश में उद्योग लगाने की प्रक्रिया सुगम हुई है और प्रदेश में श्रेष्ठ निवेश वातावरण तैयार हुआ है, जिससे बड़े स्तर पर निवेशक राजस्थान की ओर आकर्षित हो रहे हैं। राज्य में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए एमएसएमई एक्ट-2019, निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स) 2019 एवं 2022, वन स्टॉप शॉप प्रणाली जैसे कदम उठाए गए हैं। पर्यटन के क्षेत्र में निवेश के लिए पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। राज्य में कानून व्यवस्था, सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर, बिजली आदि की स्थिति काफी अच्छी है।

अक्टूबर 2022 में आयोजित इन्वेस्ट राजस्थान समिट में लगभग 11 लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन हुए, जिनमें से 49 प्रतिशत एमओयू का क्रियान्वयन हो रहा है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट की सफलता और इसके तहत हस्ताक्षरित एमओयू की संख्या एवं निवेश राज्य में उद्योग जगत के विश्वास को दर्शाता है। भारत सरकार द्वारा हाल में जारी आंकड़ों के अनुसार 11.04 जीडीपी विकास दर के साथ राजस्थान पूरे देश में दूसरे स्थान पर रहा है। कोरोना महामारी के कारण उपजी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सभी आर्थिक मापदण्डों पर राजस्थान उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। इन्वेस्ट राजस्थान के अंतर्गत राज्य में 1.36 लाख करोड़ रुपये के निवेश के लिए 23 जनवरी को जयपुर में एमओयू साइनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उद्योग, ऊर्जा एवं पर्यटन से संबंधित 26 परियोजनाओं के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। राज्य के विभिन्न जिलों में लगने जा रही इन परियोजनाओं से लगभग 17 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।

ये हुए एमओयू:

- ओएनजीसी, 25 हजार करोड़ रुपये का 5 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट
- टेपसोल सन स्पार्कल प्रा.लि., 25 हजार करोड़ रुपये का 5.2 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट
- ग्रीनको एनर्जीज प्रा. लि., 13,500 करोड़ रुपये का 2,650 मेगावाट ऑफ -स्ट्रीम क्लोज्ड लूप पम्पड स्टोरेज प्रोजेक्ट
- रिन्यू पावर, 10 हजार करोड़ रुपये का पम्पड स्टोरेज प्रोजेक्ट
- सेमालिया एनर्जी प्रा.लि., 9,700 करोड़ रुपये का 1,200 मेगावाट ऑफ स्ट्रीम क्लोज्ड लूप पम्पड स्टोरेज प्रोजेक्ट
- गेल (इण्डिया) लि., 7,250 करोड़ रुपये का सोलर पार्क
- एक्मे क्लीनटेक सॉल्यूशन्स प्रा. लि., 7,150 करोड़ रुपये का 1,500 मेगावाट ऑफ स्ट्रीम क्लोज्ड हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज
- आदित्य बिरला रिन्यूएबल्स लि., 6 हजार करोड़ रुपये के 1,500 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स एवं ग्रीन हाइड्रोजन
- मलूर रिन्यूएबल्स, 5,090 करोड़ रुपये के 1,800 मेगावाट का सोलर पार्क प्रोजक्ट
- बीपीसीएल लि., 5,000 करोड़ रुपये का 1,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट
- भांकरोटा सोलर पार्क, 4,050 करोड़ रुपये का 900 मेगावाट सोलर पार्क प्रोजेक्ट
- किरी ग्रुप, 2,892 करोड़ रुपये का एनीलिन कॉम्पलेक्स
- एक्मे क्लीनटेक सॉल्यूशन्स प्रा. लि., 2800 करोड़ रुपये का 600 मेगावाट ऑफ स्ट्रीम क्लोज्ड हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज प्रोजक्ट
- रिन्यू पावर, 2 हजार करोड़ रुपये का कार्बन प्रोजेक्ट
- चिरीपाल ग्रुप, 700 करोड़ रुपये के सोलर मॉडयूल्स
- केराकोल, 200 करोड़ रुपये के बिल्डग मैटेरियल कार्य
- एस्प्रिट वेंचर्स प्रा. लि., 150 करोड़ रुपये का रिसॉर्ट
- ग्रेस कॉलोनाइजर्स, 122 करोड़ रुपये के होटल एवं रिसॉर्ट
- उदयपुर एंटरप्राइजेज प्रा. लि., 105 करोड़ रुपये का रिसार्ट
- संप्रेति स्ट्रक्चर्स एलएलपी, 101 करोड़ रुपये का रिसॉर्ट
- रूपम सोवर होटल्स प्रा. लि., 51 करोड़ रुपये का होटल
- दयाराम, 10 करोड़ रुपये का मोटल
- आनंद बाग रिसोर्ट एण्ड स्पा, 8.5 करोड़ रुपये का होटल
- लक्ष्मणगढ़ फोर्ट प्रा. लि., 5 करोड़ रुपये का हेरिटेज होटल
- नरेन्द्र पाल सिंह, 4.64 करोड़ रुपये का होटल

RAJIV GANDHI SCHOLARSHIP FOR ACADEMIC EXCELLENCE

TO HELP STUDENTS WITH EXCEPTIONAL CAPACITIES OF LEARNING AND CREATIVE MINDS TO REACH THEIR GOALS

With the aim to provide quality education in various branches of knowledge, boost employment opportunities, enhance skills of youth, and acquaint the students with global prospect to study, the Rajasthan government under the diligent leadership of Chief Minister Shri Ashok Gehlot announced Rajiv Gandhi scholarship for academic excellence.

The scholarship is provided through the department of higher education wherein every year 200 meritorious students belonging to Rajasthan domicile will be get financial assistance for pursuing undergraduate, post graduate, doctoral and post doctoral courses in any the 150 selected foreign universities including Oxford, Harvard, Stanford University, Yale University, Imperial University of London Along with this 15 seats of QR rated top 25 universities have been reserved for students selected for B.Tech., MBBS, BDS.

Widening the scope of subjects for the students and further the development of state, subjects ranging from humanities, social sciences, agriculture and forest science, nature and environmental science, law, management and business administration, economics and finance, pure science and public health to engineering and related sciences are kept under the backing of scholarship. The scheme will open new avenues for students in numerous fields and advance learning. The state government will bear the cost of tuition fees, travel fare together with some other expenses. The talented students who were not able to get into foreign studies because of their poor financial conditions have benefitted to a great extend from this scheme as it aids the financial requirements of students who have family income less than 8,00,000 per annum to study abroad. The prime focus of this scheme is to provide financial help to the student who are not able to pursue higher education

Rakshita Yadav
Assistant PRO

in world's top universities because of financial constrains. In a bid to encourage education for building their future 30 percent seats have been reserved for girls.

It is noteworthy that the announcement about the scheme was made on the auspicious day of birth anniversary of former Prime Minister late Shri Rajiv Gandhi. The scheme has helped students with exceptional capacities of learning and creative minds to reach their goals. Students from small villages of State by this scheme have been able to get to the top global universities. A total of 238 students have been served with letters out of which fees of 95 students has been reimbursed. An outlay of around 15-crore rupees has been used to facilitate the requirements of students to meet their ambitions.

Many students like Abhishek from Jalore who was not able to follow his dream of pursuing higher education in global universities have turned their dreams into reality by this scheme. Abhishek is now studying English Literature in Lancashire University in UK. The government of Rajasthan is bearing the cost of travel, food, visa, health insurance, laptop and many more expenses. Equally Pradyuman Singh Ranawat coming from a small village of Gordiyan in Bhilwara is studying M.Sc. in York University UK under this scheme. The state government is not only providing the opportunity but also supporting Pradyuman in achieving his career goals by bearing the cost of 23 thousand 950 pounds which is around 23 lakhs 95 thousand in Indian rupees. Along with these educational expenses, other expenses of around 12 lakhs rupees will be borne by the state government. The scheme has brought many dreams of many students like Pradyuman to reality.

जनजाति क्षेत्र की बदल रही तस्वीर

जनजाति क्षेत्र के समुचित विकास को लेकर करवाए गए कार्यों का धरातल पर दिखने लगा असर

किसी भी क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए कुछ मूलभूत सुविधाओं का होना अत्यंत आवश्यक है। जनजातीय क्षेत्रों को सामान्यत: आधारभूत संरचनाओं व सुविधाओं की कमी के कारण पिछड़े क्षेत्रों में गिना जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार के प्रयासों से अब जनजाति क्षेत्र की तस्वीर बदल रही है।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। राज्य सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्र के समुचित विकास को लेकर लगातार करवाए गए कार्यों का धरातल पर असर भी दिखाई देने लगा है। जनजातियों के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण उनका आर्थिक रूप से पिछड़ापन है जो उन्हें बाकी सुविधाओं से वंचित करता है। इसी वजह से वे शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का लाभ भी प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे में जनजाति बहुल जिले प्रतापगढ़ में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा बुनियादी जरूरतें उपलब्ध करवाने के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं जिनसे व्यापक परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है।

स्कूल, छात्रावास, स्टेडियम खुलने से आया बदलाव

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा प्रतापगढ़ जिले में करोड़ों की राशि से अनेकों विकास कार्य सम्पन्न किए गए हैं। इसके अंतर्गत पीपलखूंट में 17 करोड़ 98 लाख रुपये के एकलव्य मॉडल डे-बोर्डिंग विद्यालय, 6 करोड़ 30 लाख का इंडोर स्टेडियम, प्रतापगढ़ में 5 करोड़ 32 लाख की राशि का बहुउद्देशीय बालिका छात्रावास, 2 करोड़ रुपये

नवधा परदेशी
सहायक जनसंपर्क अधिकारी

की राशि से कौशल विकास केंद्र भवन, भंवर माता छोटी सादड़ी में 90 लाख रुपये का नवीन सामुदायिक भवन, 3 करोड़ 58 लाख रुपये की राशि से सुहागपुरा से वीरपुर एराव नदी पर सबमर्सिबल पुलिया और 8 लाख रुपये की राशि से आवासीय विद्यालय प्रतापगढ़ के लिए नवीन सोलर पनघट का कार्य स्वीकृत कर पूर्ण किया गया है।

ऐसे ही 1 करोड़ 44 लाख रुपये की राशि से गोविन्द गुरु सामुदायिक भवन आवासीय स्कूल परिसर, पंचायत समिति परिसर छोटी सादड़ी, सामुदायिक भवन धरियावद, 1 करोड़ 50 लाख रुपये की राशि से खेल स्टेडियम की चारदीवारी, 57.18 लाख रुपये की राशि से जिला चिकित्सालय में लिफ्ट स्थापना कार्य, 3 करोड़ 82 लाख रुपये की राशि से एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल (ईएमआरएस), बालिका टिमरवा में 24 डोरमेट्री, चौकीदार क्वॉर्टर पार्किंग शेड, खेल मैदान विकास, 49 लाख के वादी एवं परिवादी परिवारों के परामर्श एवं जनसुनवाई हेतु कक्ष का कार्य स्वीकृत कर पूर्ण हुआ है।

2 करोड़ 37 लाख की राशि से 21 छात्रावासों में सोलर पनघट, 1 करोड़ 14 लाख रुपये की राशि से गोपालपुरा वाया नाडाफला पंचायत समीति बी.टी. सड़क, 91.21 लाख रुपये जगलावाद मुंगाणा रोड तक वाया नायक टांडा डामरीकरण मय इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य स्वीकृत कर पूरा किया गया है।

अनेक कार्य शीघ्र पूर्ण होने की राह में

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा धरियावद में 3 करोड़ 34 लाख रुपये के जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास, धोलापानी में 3 करोड़ 34 लाख की राशि से जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास, अवलेश्वर में 2 करोड़ 62 लाख की राशि से जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास, 3 करोड़ 23 लाख रुपये की राशि से पंचायत समिति पीपलखूंट में बाईं मुख्य नहर लाइनिंग कार्य, आर.डी. 0 से 6450 मी. भंवर सेमला सिंचाई परियोजना में नहर निर्माण, धरियावाद पंचायत समिति में खूंता, वजपुरा, कुपडा, सिहाड़, खुराजी खेडा में प्रत्येक में 10 लाख रुपये के सीसी रोड व अन्य कई निर्माण कार्य प्रगतिरत हैं।

जनजाति वर्ग के शैक्षणिक उत्थान के लिए दिल खोल कर खर्च कर रही सरकार

प्रतापगढ़ में 334.62 लाख रुपये की राशि से जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास, धरियावद में पुनर्निर्माण कार्य से 70 छात्राओं को फायदा पहुंचा। इसी तरह 334.62 लाख रुपये की राशि से जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास, धोलापानी के पुनर्निर्माण से 50 छात्राएं लाभान्वित हुईं। 335.08 लाख रुपये की राशि से एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ई.एम.आर.एस. टिमरवा में 24 डोरमेंट्री गार्ड रूम, पार्किंग रोड, खेल मैदान विकास, इंटरनल पाथ-वे, रनिंग ट्रैक, सीसीटीवी, सोलर लाइट इन्वर्टर आदि कार्य करके 144 विद्यार्थियों को फायदा पहुंचाया गया। 329.12 लाख की राशि से जर्जर छात्रावासों का पुनर्निर्माण कार्य करके जनजाति बालक आश्रम छात्रावास नागदी, अरनोद में 50 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।

शैक्षणिक प्रोत्साहन को लेकर संचालित योजनाएं

उच्च शिक्षा आर्थिक सहायता योजना कॉलेज (छात्रा) के तहत 5,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं ताकि विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के अवसर प्राप्त हो सकें व उनके लिए प्रगति के द्वार खुलें। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2019 में 3,237 विद्यार्थियों, 2020 में 2,846 विद्यार्थियों, 2021 में 93 विद्यार्थियों और 2022 में 1,697 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। इसके लिए वर्ष 2019 में 1 करोड़ 61 लाख 85 हजार, वर्ष 2020 में 1 करोड़ 42 लाख 30 हजार, वर्ष 2021 में 4 लाख 65 हजार और 2022 में 84 लाख 85 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई।

कक्षा 11वीं व 12वीं आर्थिक सहायता योजना (छात्रा) के अन्तर्गत 3,500 रु. प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2019 में 2357, 2020 में 1479 ,2021 में 221 ,2022 में 988 लाभार्थी रहे। इसके लिए 2019 में 82 लाख 49 हजार 500 रुपये, वर्ष 2020 में 51 लाख 76 हजार 500 रुपये, वर्ष 2021 में 7 लाख 73 हजार 500 रुपये, वर्ष 2022 में 34 लाख 58 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई। प्रतिभावान छात्रवृति योजना (छात्र) के अन्तर्गत 3,500 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। योजना के अंतर्गत वर्ष 2019 में 350, 2020 में 261, 2021 में 106, 2022 में 263 लाभार्थी रहे। योजनान्तर्गत वर्ष 2019 में 12 लाख 25 हजार, वर्ष 2020 में 9 लाख 13 हजार 500, वर्ष 2021 में 3 लाख 71 हजार, वर्ष 2022 में 9 लाख 20 हजार 500 रुपये की राशि प्रदान की गई ।

डीबीटी से बढ़ रहा वित्तीय समावेशन

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के तहत छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को इस योजना के अंतर्गत यूनिफॉर्म सिलाई, स्टेशनरी, अंडर गारमेंटस क्रय करने हेतु विभाग द्वारा राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2019 में 4,319 छात्र-छात्राओं को 850 रुपये, वर्ष 2020 में 3,786 छात्र-छात्राओं को 2,500 रुपये, वर्ष 2021 में 4,117 छात्र-छात्राओं को 3,300 रुपये, वर्ष 2022 में 4,302 छात्र-छात्राओं को 3,300 रुपये की राशि प्रत्येक को खाते में हस्तांतरित की गई।

मां-बाड़ी केन्द्रों का हो रहा सफल संचालन

शिक्षा से वंचित जनजाति परिवारों के बच्चों को उनके निवास स्थान के पास ही शिक्षा सहित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतापगढ़ जिले में गत चार वर्षों में 15 नवीन मां-बाड़ी केन्द्र स्वीकृत किये गये। इनमें से छह कार्य पूर्ण किये गए हैं एवं 9 कार्य प्रगतिरत हैं। वर्तमान में जिले में कुल 380 मां बाड़ी केन्द्रों का संचालन स्वच्छ परियोजना के माध्यम से किया जा रहा है। यहां 6-12 वर्ष के छात्र-छात्राओं को शिक्षा के साथ-साथ अल्पाहार, पाठ्यपुस्तकें एवं अन्य सुविधाएं नि:शुल्क दी जाती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए आवासीय छात्रावासों, यूनिफॉर्म सिलाई, स्टेशनरी, अंडर गारमेंटस क्रय करने के लिए डीबीटी योजना जैसी योजनाओं की शुरुआत की है।

सूचना के अधिकार से एक कदम आगे जन सूचना पोर्टल

आम जन तक सूचना पहुंचाने में मॉडल स्टेट बना राजस्थान

आपकी सूचना, आपका अधिकार को परिभाषित करते हुए जन सूचना पोर्टल के माध्यम से तमाम जरूरी सूचनाएं जन-जन तक पहुंचाने जैसी अभिनव पहल करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले से आमजन को राहत मिली है। अब सूचना लेने के लिए जनता को ना तो सरकारी दफ्तरों में आने की आवश्यकता और न ही बुनियादी सूचनाएं हासिल करने के लिए आरटीआई के तहत आवेदन करना पड़ता है जिससे आमजन के समय, धन और ऊर्जा की बचत हो रही है।

सूचना समाज की शक्ति, विकास का मूल और सुशासन का आधार है। सूचना क्रांति के युग में राजस्थान सूचना के अधिकार के क्षेत्र में मिसाल कायम कर रहा है। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की मंशा को साकार करने के लिए राजस्थान सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया और 13 सितम्बर, 2019 को जन सूचना पोर्टल का आगाज किया।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सूचना के अधिकार की मूल भावना को पोषित करते हुए शासन और प्रशासन को जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए जन सूचना पोर्टल के रूप में जो बीजारोपण किया था, वह विशाल और मजबूत वटवृक्ष बनकर राजस्थान की जनता को महज एक क्लिक पर सरकार के हर लोक कल्याणकारी फैसले, विकास की दिशा में उठाए गए सरकार के हर कदम और सुशासन की राह में जारी हर आदेश की जानकारी दे रहा है। सूचना चाहे किसी कल्याणकारी योजना से जुड़ी हो या प्रशासनिक कार्य-प्रणाली की, हर नागरिक को जन सूचना पोर्टल पर आवश्यक सूचनाएं मिल रही हैं।

नरेन्द्र सिंह शेखावत
सहायक जनसंपर्क अधिकारी

जन सूचना पोर्टल की सफलता की कहानी

जन सूचना पोर्टल का उद्देश्य सोशल ऑडिट के साथ-साथ आम-जन को आसानी से सुविधा उपलब्ध करवाना है। ''जवाबदेही कानून'' बजट पत्र-2019 में प्रस्तावित किया गया, जिसके अनुसार विभागों के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की बात की गई जिससे विभिन्न विभाग एवं अधिकारी पाबंद हों। जन सूचना पोर्टल के द्वारा भी उसी कानून के तहत एक निष्पक्ष सूचना आम जन को उपलब्ध करवाई जा रही है।

साल 2019 में योजना के आगाज के समय जन सूचना पोर्टल पर 13 विभागों की 23 योजनाओं की जानकारियां मुहैया करवाई जा रही थीं। वहीं, आमजन सूचना पोर्टल पर 115 विभागों की 332 योजनाओं की 691 तरह की जानकारियां सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। इस योजना की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज 3 साल में प्रदेश की जनता ने सूचना हासिल करने के लिए 12 करोड़ से ज्यादा बार इस पोर्टल का इस्तेमाल किया और सरकारी योजनाओं और फैसलों की 18 करोड़ से ज्यादा जानकारियां जुटाईं। जनसूचना पोर्टल-2019 अपनी तरह का पहला ऐसा प्रयास है जिसमें सरकार द्वारा वार्ड/पंचायत में क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध करवाई जा रही है। यह सूचना के अधिकार, 2005 की धारा 4(2) को क्रियान्वित करता है जिसमें उल्लेखित है कि ''प्रत्येक लोक अधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि वह उपधारा

आंकड़ों की जुबानी
• 115 विभागों की सूचना
• 332 योजनाओं की जानकारी
• 691 तरह की सूचनाएं उपलब्ध
• 12.35 करोड़ से ज्यादा विजिटर्स
• 18.54 करोड़ से ज्यादा सूचनाएं दी जा चुकी हैं

(1) के खंड (ख) की अपेक्षाओं के अनुसार, स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अन्तरालों पर सूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनके अन्तर्गत इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करें जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिये इस अधिनियम का कम से कम अविलंब लेना पडे.''।

राजस्थान में जनता को सूचना प्राप्ति के लिए न तो आवेदन करना पड़े और न ही 30 दिन का इंतजार। इसके लिए राजस्थान सरकार ने सूचना के अधिकार से भी एक कदम आगे जाकर जनसूचना पोर्टल के माध्यम से जन-जन तक सूचनाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। जनसूचना पोर्टल के माध्यम से आमजन को घर बैठे एक क्लिक पर सूचना सुविधा उपलब्ध है। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा सरकार के 115 महकमों की एपीआई को एकीकृत करके संबंधित विभागों की विभिन्न सूचनाएं, जन सूचना पोर्टल के माध्यम से आमजन को उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

सूचना के अधिकार से जनसूचना पोर्टल तक का सफर

पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने सूचना क्रांति की नींव रखी तो तत्कालीन राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम बनाकर सुशासन की दिशा में एक नई इबारत लिख दी। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत और नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम को लागू करने जैसा ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाया। इस अधिनियम को पारित करने की मंशा थी कि देश के आम नागरिकों को सूचना का अधिकार देकर सशक्त बनाया जाए और

सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के साथ-साथ प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाई जाए। इतिहास गवाह है कि सूचना के अधिकार की बुनियाद भी मरुधरा में ही रखी गई थी। राजस्थान देश के उन अग्रणी राज्यों में शुमार है जिन्होंने बाकायदा कानून बनाकर जनता को सूचना का अधिकार के रूप में एक बड़ा संसाधन मुहैया करवाया। राज्य सरकार ने सितम्बर, 2019 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की 75वीं जयंती पर राजस्थान इनोवेशन विजन (राजीव) की शुरुआत की। स्व. राजीव गांधी ने सूचना क्रांति की मदद से आधुनिक भारत के निर्माण का सपना देखा था। इसी सपने को साकार करने के लिए राजस्थान सरकार ने प्रदेश में आईटी आधारित एक ऐसा सुदृढ़ तंत्र विकसित किया है जिसके माध्यम से प्रदेश के करोड़ों नागरिकों के पास घर बैठे सेवाएं और सूचनाएं पहुंच रही हैं। राजीव इनोवेशन विजन के तहत जन सूचना पोर्टल-2019 के रूप में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई और आम जनता को सरकारी योजनाओं से जुड़ी सभी जानकारियां आसान भाषा में ऑनलाइन प्राप्त हो रही हैं।

तकनीक से बदल रही तकदीर

राजस्थान सरकार की इस सकारात्मक पहल से प्रदेशवासियों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है। यह पोर्टल न केवल सरकार, सिविल सोसायटी और आमजन के डिजिटल संवाद का महत्त्वपूर्ण मंच साबित हो रहा है बल्कि जनसूचना पोर्टल की सफलता दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बन गई है। जनसूचना पोर्टल-2019 का उद्देश्य सोशल ऑडिट के साथ-साथ आम-जन को सरकारी विभागों, प्राधिकरणों, निगमों आदि में संधारित सूचनाएं क्षेत्रवार और निजी जानकारी के अनुसार सरल भाषा और आसान तरीके से उपलब्ध करवाया जाना है। बजट 2019-2020 के बिन्दु संख्या 180 के अनुसार 'लोक सेवकों की जवाबदेही के लिए 'सार्वजनिक जवाबदेही कानून' लाया जायेगा, जो समस्त विभागों, प्राधिकरणों व निगमों पर लागू होगा। ''जन-सूचना पोर्टल-2019'' के द्वारा भी उसी कानून के तहत निष्पक्ष सूचनाएं आम-जन को चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

आपकी सूचना, आपका अधिकार को परिभाषित करते हुए जन सूचना पोर्टल के माध्यम से तमाम जरूरी सूचनाएं जन-जन तक पहुंचाने जैसी अभिनव पहल करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले से आमजन को राहत मिली है। अब सूचना लेने के लिए जनता को ना तो सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाने पड़ते हैं और न ही बुनियादी सूचनाएं हासिल करने के लिए आरटीआई के तहत आवेदन करना पड़ता है जिससे आम जन के समय, धन और ऊर्जा की बचत हो रही है। घर बैठे एक क्लिक पर जनता को बुनियादी सूचनाएं मिलने से सरकारी दफ्तरों में सूचना के अधिकार के आवेदनों के अंबार में भी कमी आई है और इस तरह राजस्थान में सुशासन का सपना साकार हो रहा है।

आजादी के अमृत महोत्सव पर भारत की स्वतंत्रता के लिए राजस्थान में क्रांति की अग्नि प्रज्ज्वलित करने वाले स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर केसरी सिंह बारहठ की 150 वीं जयंती पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने भीलवाड़ा के शाहपुरा में पेनोरमा निर्माण के लिए 4 करोड रुपये के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की हैं । मुख्यमंत्री के इस निर्णय से मुख्य पेनोरमा भवन, चारदीवारी, पाथ-वे, सभागार, पुस्तकालय, ऑडियो - वीडियो सिस्टम, विभिन्न आर्ट वर्क, स्टेच्यू एवं छतरी, प्रवेश द्वार, शिलालेख सहित विभिन्न निर्माण कार्य होंगे। पेनोरमा से आमजन को वीर क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहठ के कृतित्व एवं व्यक्तित्व की जानकारी मिलेगी। युवा पीढ़ी अपने अधिकारों के प्रति शिक्षित और जागृत होगी।

ठाकुर केसरी सिंह बारहठ ने राजस्थान में देश की आजादी के लिए सशस्त्र क्रांति का बेड़ा उठाने में महान क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा, लोकमान्य तिलक एवं अरविंद घोष से प्रेरित होकर ही क्रांति के लिए सहयोग शुरू किया था। इस पेनोरमा के लिए भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के बाहरठ समाज , केसरी सिंह बाहरठ स्मारक समिति एवं अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह बारहठ सेवा संस्थान सहित कई संस्थाओं द्वारा मांग की गई थी। इनकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने यह स्वीकृति प्रदान की हैं।

भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे में क्रांतिकारी ठाकुर केसरी सिंह बारहठ की 150वीं जयन्ती महोत्सव पर 'बारहठ सप्ताह' मनाया गया। जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ।इन कार्यक्रमों में देश और प्रदेश से समाजसेवी, शिक्षाविद, राजनेता, कवि, लेखकों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और महापुरुषों की स्मृतियों को यादगार बनाया। सरकार महापुरुषों के योगदान को इतिहास के पन्नों से बाहर निकाल कर आम जनता तक पहुंचाने का भरसक प्रयास कर रही हैं परंतु आमजन का भी कर्तव्य है कि महापुरुषों की स्मृतियों को सहजने के लिए सभी साथ मिलकर प्रयास करे।

स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारहठ पेनोरमा

राजस्थान में क्रांति की अग्नि प्रज्वलित करने वाले स्वतंत्रता सेनानी के कृतित्व एवं व्यक्तित्व की मिलेगी जानकारी

डॉ. राकेश वर्मा
स्वतंत्र लेखक

क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहठ का जीवन परिचय

ठाकुर केसरी सिंह बारहठ का जन्म 21 नवंबर 1872 को शाहपुरा रियासत के देवखेड़ा नामक गांव में एक चारण समाज के परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम कृष्ण सिंह बारहठ था। माता बख्तावर का निधन उनके बचपन में ही हो गया था।

शिक्षा

शाहपुरा में महंत सीताराम की देखरेख में 6 वर्ष की आयु में शिक्षा प्रारंभ हो गई थी। इनके पिताजी ने 2 वर्ष बाद उदयपुर में काशी से एक

विद्वान पंडित गोपीनाथ शास्त्री को बुलाकर केसरीजी की औपचारिक शिक्षा - दीक्षा संस्कृत परिपाटी में शुरू कराई। केसरीजी प्रतिभा के धनी थे उन्होंने पूरा अमरकोश कंठस्थ कर लिया। केसरी जी ने संस्कृत एवं हिंदी भाषा के साथ-साथ बंगला, गुजराती, मराठी भाषाओं का भी अध्ययन किया। इनकी ज्योतिष गणित, खगोलशास्त्र में थी अच्छी पकड़ थी।

स्वतंत्रता में अमूल्य योगदान

केसरी सिंह ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ राजस्थान के क्षत्रियों सहित सभी वर्गों को एकजुट करने, शिक्षित करने और उनमें जागृति लाने का कार्य किया। सन 1930 में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को वायसराय लार्ड कर्जन द्वारा दिल्ली दरबार में बुलाई गई बैठक में भाग लेने से रोकने के उद्देश्य से उन्होंने 'चेतावनी रा चुंगटा' नामक 13 सोरठों की रचना कर अपनी काव्य प्रतिभा का परिचय दिया। स्वतंत्रता सेनानियों को हथियार उपलब्ध कराना, ब्रिटिश सूचनाएं क्रान्तिकारियों

को भेजना आदि सहयोग करते थे। वर्ष 1910 में उन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की। केसरी सिंह का देश के मुख्य क्रांतिकारियों श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, अर्जुन लाल सेठी, शचीन्द्रनाथ सान्याल, मास्टर अमीरचंद आदि के साथ घनिष्ठ दोस्ती था। सन 1912 में राजपूताना में ब्रिटिश सरकार द्वारा जिन क्रांतिकारियों की निगरानी रखी जानी थी उनमें केसरी सिंह का नाम राष्ट्रीय-अभिलेखागार की सूची में सबसे ऊपर था।

कारावास जीवन

केसरी सिंह को 2 मार्च 1924 को शाहपुरा के राजा नाहर सिंह के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया गया और प्यारेलाल नामक एक साधु की हत्या और दिल्ली-लाहौर षड्यंत्र केस में राजद्रोह, षड्यंत्र व कत्ल आदि के आरोप लगाए गए। केसरी जी को 20 वर्ष के कारावास की सजा दी गई और बिहार के हजारीबाग जेल में डाल दिया गया। जेल जाते ही केसरी ने अन्न-त्याग दिया था उन्हें डर था कि क्रांतिकारियों की गुप्त बातें उगलवाने के लिए ब्रिटिश पुलिस ऐसी कोई चीज न खिला दें जिससे उनका मस्तिष्क विकृत हो जाए। ऐसा 5 वर्ष तक किया। उन्हें कई बार यातनाएं भी दी गई। सरकार किसी प्रकार से केसरी सिंह के विरुद्ध राजनीतिक उद्देश्य से की गई हत्या का जुर्म साबित कर उन्हें फांसी देना चाहती थी। ब्रिटिश सरकार ने उनके गांव की पैतृक जागीर, बड़ी हवेली एवं चल- अचल संपत्ति भी जब्त कर ली। घर के बर्तन तक नीलाम कर दिए थे। उनके भाई जोरावर सिंह और पुत्र कुंवर प्रताप सिंह बारहठ ने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थें। पूरे परिवार को

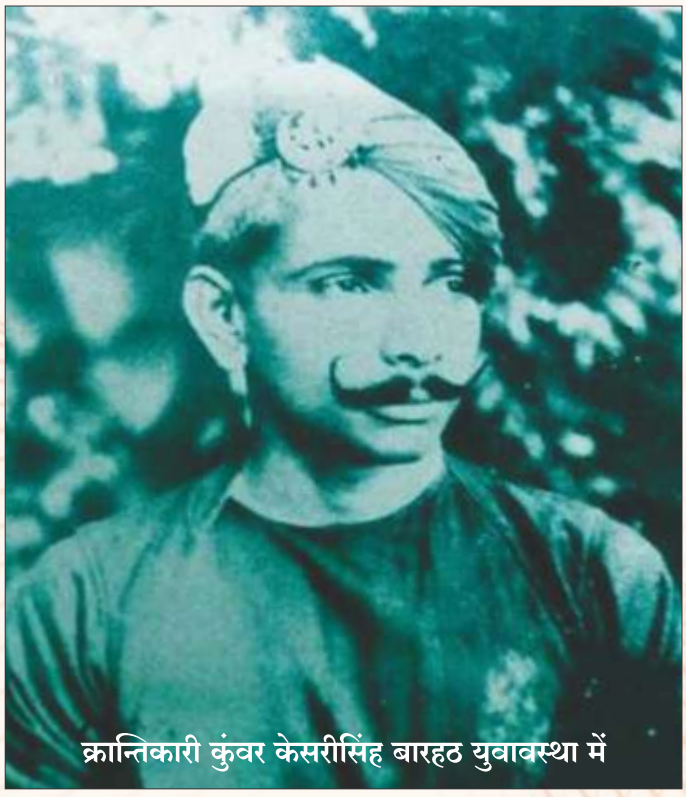

क्रान्तिकारी कुंवर केसरीसिंह बारहठ युवावस्था में

आजादी के आंदोलन में झोंक दिया। शक्ति, भक्ति और कुर्बानी की कण- कण में महान क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहठ और उनके परिवार की शौर्य गाथा देश भर में आज भी गूंजती है। कारावास के समय उन्होंने अपनी एक नई मिश्रित सैन्य कला विकसित कर ली थी, जिसे 'चमवाई' कहते हैं। यह सैन्य कला इटली की स्वाट टीमें धुंए से भरे घरों में घुसने के लिए किया करती हैं। जेल से रिहा के बाद भी उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखा।

जेल से रिहा होने के बाद

केसरी सिंह ने 1920 में आबू के गवर्नर जनरल को एक विस्तृत पत्र भी लिखा जिसमें उन्होंने भारत की रियासतों एवं राजस्थान के लिए एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की एक 'योजना' प्रस्तुत की थी। क्रांतिकारी कवि केसरी सिंह बारहठ ने 'हरि ओम तत्सत' के उच्चारण के साथ 14 अगस्त 1941 को नेत्र सदा के लिए निमीलित हो गए।

केसरी सिंह बारहठ की जन्मस्थली देवखेड़ा में उनके पूर्वजों ने गांव के लोगों के लिए तीन तालाब करनी सागर, ओनाड़ सागर और कृष्ण सागर बनाए। गांव में पुरातत्व विभाग का एक शिलालेख है उसके अनुसार सन 1872 से पूर्व शाहपुरा दरबार भी उनके मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मेहमान बने थे। हाल में सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार ने देश के 80 गांवों को 'मेरा गांव मेरी धरोहर' घोषित किया जिसमें राजस्थान के 6 गांवों में देवखेड़ा को शामिल किया है जो एकमात्र क्रांतिकारियों का गांव है।

युवा पीढ़ी को मिलेगी प्रेरणा

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारहठ पेनोरमा निर्माण का निर्णय लिया है। इसके लिए गहलोत ने 4 करोड़ की स्वीकृति जारी की हैं। बारहठ के पेनोरमा का निर्माण भीलवाड़ा के शाहपुरा में होगा। मुख्यमंत्री के अनुसार पेनोरमा से जनसामान्य को वीर क्रांतिकारी कवि केसरी सिंह बारहठ के कार्यों और व्यक्तित्व की जानकारी युवा पीढ़ी को मिलेगी। युवा पीढ़ी अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति शिक्षित और जागृत होगी। शाहपुरा कस्बे में केसरी सिंह बारहठ की हवेली हैं। जिसमें पुरातत्व संग्रहालय भी बना हुआ हैं।

राज्य सरकार की देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में एक सार्थक पहल है। इस योजना के सफल क्रियान्वयन द्वारा राजस्थान बालिका शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। यदि हमें राष्ट्र की उन्नति देखनी है तो सबसे पहले महिला शिक्षा को समृद्ध करना होगा। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर महिला शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों और नवाचारों का क्रियान्वयन किया गया है। देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना इसी क्रम में एक प्रमुख योजना है।

प्रदेश में अति पिछड़ा वर्ग (MBC) की बालिकाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा वर्ष इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना द्वारा प्रदेश के वंचित वर्ग की छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।

इस योजना का उद्देश्य अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं (सीनियर सेकंडरी) कक्षा की परीक्षा तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक, स्नातकोत्तर की परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक लाने के लिए प्रोत्साहित करना, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना, उच्च अध्ययन हेतु आकर्षित करना और उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। योजना का लाभ प्राप्त के लिए आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है। साथ ही माता-पिता अथवा अभिभावक की सभी स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय 2,50,000 रुपये से कम होनी चाहिए।

इस योजना का लाभ अति पिछड़ा वर्ग की सभी अविवाहित, विवाहित, विधवा तथा परित्यक्ता छात्राओं को देय होगा। इस योजना के अन्तर्गत अति पिछड़े वर्ग की वे छात्राएं जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित

देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना

शिक्षित महिला, उन्नत राष्ट्र

सविता सिंह
सहायक जनसम्पर्क अधिकारी

12वीं (सीनियर सेकंडरी) परीक्षा में 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं और वे राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हैं, उन्हें 1,500 स्कूटी वरीयता के आधार पर नि:शुल्क वितरित की जाती हैं। शेष छात्राओं को प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जाएगी।

प्रतिवर्ष 1,500 के निर्धारित लक्ष्य के अलावा 1,500वीं छात्रा के प्राप्तांक के समान कटऑफ प्राप्तांक वाली छात्राओं को भी स्कूटी स्वीकृत कर नि:शुल्क वितरित की जाती है। स्कूटी वितरण के साथ 1 वर्ष का बीमा, 2 लीटर पेट्रोल तथा छात्रा को सुपुर्द करने तक का परिवहन व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। अति पिछड़ा वर्ग की वे छात्राएं जो राज्य के राजकीय विद्यालयों, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में नियमित अध्ययनरत हैं, उनके द्वारा 12वीं या स्नातक में पूर्णतया 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर 10,000 रुपये वार्षिक, स्नातकोत्तर प्रथम में 20,000 रुपये वार्षिक तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में पूर्णतया 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में 20,000 रुपये वार्षिक प्रोत्साहन राशि के तौर पर दिये जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत अब तक 2,484 स्कूटी का वितरण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा वर्ष 2022 तक इसके अनुसार देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना के अन्तर्गत 1,500 स्कूटी से बढ़ाकर 2,463 स्कूटी प्रतिवर्ष वितरण की जाएंगी।

ऐसे करें आवेदन

योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र या स्वयं राज्य सरकार की वेबसाइट https://hte-rajasthan.gov.in/scholarship.php पर नि:शुल्क आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची में मूल निवास प्रमाण पत्र, शुल्क की रसीद, जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता की अंकतालिका और प्रमाण-पत्र, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, जनाधार या भामाशाह कार्ड की प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।

पालनहार योजना

अनाथ बच्चों के लिए बनी सम्बल

मोहित जैन
सहायक जनसम्पर्क अधिकारी

पालनहार योजना राजस्थान सरकार की एक अभिनव व विशिष्ट योजना है। इसमें अनाथ बच्चों के पालन- पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही निकटतम रिश्तेदार या परिचित व्यक्तियों के द्वारा की जाती है। इसके लिए राज्य सरकार उन्हें मासिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है।

पालनहार योजना राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के 18 वर्ष तक के अनाथ बालक, बालिकाओं के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास को सुनिश्चित करवाने के लिए चलाई जा रही है। इस योजना का नोडल विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है। इसके अन्तर्गत अनाथ बालक और बालिकाओं की देखभाल करने वाले को पालनहार कहा गया है। इसमें पात्र पालनहार परिवार उनको माना गया है जिनकी वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक न हो तथा वे आवेदन की तिथि से कम से कम 3 वर्षों की अवधि से राजस्थान में रह रहे हों। इच्छुक व्यक्ति को पालनहार बनाकर राज्य सरकार की ओर से इस प्रकार की आर्थिक सहायता देना संपूर्ण भारत वर्ष में अनूठा व अनुकरणीय है।

पालनहार योजना में आर्थिक सहायता राशि अनाथ श्रेणी व अन्य श्रेणी के उन बच्चों को दी जाती है जिनकी अधिकतम आयु 18 वर्ष से कम हो। राज्य सरकार ने पालनहार योजना में 6 वर्ष तक की आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को मिलने वाली सहायता राशि 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1,500 रुपये एवं 6-18 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों के लिए 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रतिमाह कर दी है। इसके साथ अन्य श्रेणी के 0- 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे को 500 रुपये प्रतिमाह व 6- 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे को 1,000 रुपये प्रतिमाह देय है। इसके अलावा वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि खर्च के लिए 2,000 रुपये वार्षिक अतिरिक्त एकमुश्त सहायता भी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 1,813.29 करोड़ रुपये व्यय कर 6.51 लाख बच्चों को योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया है एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए लगातार प्रयासरत है।

पात्रता श्रेणी

योजना के अन्तर्गत अनाथ बच्चे, न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के बच्चे, निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के बच्चे, पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे, एचआईवी

या एड्स पीड़ित माता-पिता के बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चे, नाते जाने वाली माता के बच्चे, विशेष योग्यजन माता-पिता के बच्चे, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला के बच्चे, सिलिकोसिस पीड़ित माता-पिता के बच्चों को सहायता प्रदान की जाती है।

जमा करवाए जाने वाले दस्तावेज

आवेदन करने के लिए पालनहार द्वारा विभिन्न दस्तावेज जैसे पालनहार का आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, बच्चे का आधार कार्ड, पालन पोषण करने का प्रमाण-पत्र, बच्चे का आंगनबाड़ी में पंजीकरण का प्रमाण-पत्र, बच्चे का विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण-पत्र, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड जमा करवाए जाते हैं। यह आवेदन पत्र शहरी क्षेत्र में विभागीय जिला अधिकारी को तथा ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित विकास अधिकारी को या ई-मित्र केंद्र में जाकर जमा करवाए जाते हैं।

राजस्थान जन आधार योजना

एक नम्बर, एक कार्ड, एक पहचान

सुरेन्द्र कुमार मीणा
सहायक जनसम्पर्क अधिकारी

गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, वंचित और अल्प आय वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए राज्य सरकार की ओर से विभिन्न प्रकार की योजनाएं शुरू की गई हैं। कई बार पात्र नागरिक भी योजना से संबंधित जानकारी न होने के कारण या किसी अन्य कारण से योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर पाते हैं। अपनी इन तमाम योजनाओं को समावेशी बनाने के लिए और सभी पात्र लोगों तक उनके फायदे पहुंचाने के एक खास व्यवस्था राजस्थान जन आधार योजना है।

श्री अशोक गहलोत द्वारा बजट 2019-20 में की गई बजट घोषणा की अनुपालना में विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से विभिन्न सेवा प्रदायगी माध्यमों को कम कर 'एक नम्बर, एक कार्ड, एक पहचान' की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तथा राज्य की संपूर्ण सेवा प्रदायगी तंत्र को एकीकृत कर केवल एक माध्यम से निवासियों तक पहुंचाने हेतु ''राजस्थान जन-आधार योजना, 2019'' का आयोजना विभाग द्वारा 18 दिसंबर, 2019 से शुभारम्भ किया गया। इसके तहत राजस्थान जन आधार कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की गई थी। इस योजना में भामाशाह कार्ड के सभी लाभ समाहित कर लिए गए हैं।

राजस्थान जन आधार योजना विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करती है

- राज्य के निवासी परिवारों की जन-सांख्यिकीय एवं सामाजिक-आर्थिक सूचनाओं का डेटा बेस तैयार कर प्रत्येक परिवार को ''एक नम्बर, एक कार्ड, एक पहचान'' प्रदान किया जाना।
- इसे परिवार एवं उसके सदस्यों की पहचान तथा पते के दस्तावेज के रूप में मान्यता प्रदान कराना। पात्र लाभार्थियों के नकद लाभ, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से उनके बैंक खातों में तथा गैर-नकद लाभ आधार, जन-आधार अधिप्रमाणन उपरान्त घर के समीप उपलब्ध कराने हेतु बैंक खाते को जन आधार कार्ड से लिंक किया जाता है।
- जनकल्याण की योजनाओं के लाभों के अतिरिक्त ई-कॉमर्स और बीमा सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार कराना।
- राज्य के ई-मित्र तंत्र को राजस्थान जन-आधार प्राधिकरण के अधीन लाकर उसके विनियमन द्वारा प्रभावी नियंत्रण व संचालन।
- राज्य में जन-सांख्यिकीय सम्बन्धी समस्त पंजीयनों को यथा-जन्म, मृत्यु, विवाह, आधार आदि को जन-आधार प्राधिकरण के अधीन लाकर राज्य की रियल टाइम जनगणना अद्यतन रखना। विभिन्न योजनाओं के लाभ प्राप्ति के समय आधार अधिप्रमाणन को लाभार्थी के जीवित प्रमाण-पत्र के रूप में मान्यता देना।

जन-आधार पंजीयन

राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में लाभ लेने हेतु आवेदन करने के लिए, एक जन आधार संख्या अनिवार्य है। जो निवासी राजस्थान जन आधार कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे जनाधार पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान जन आधार कार्ड आवेदन केवल वे ही लोग जमा कर सकते हैं जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं। राज्य के सभी निवासी परिवार पंजीयन कराने व जन-आधार कार्ड प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। नामांकित प्रत्येक परिवार को एक 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या एवं मुखिया सहित प्रत्येक सदस्य को 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या युक्त एक बारीय जन आधार कार्ड नि:शुल्क प्रदान किया जा रहा है। परिवार द्वारा निर्धारित 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को परिवार की मुखिया बनाया जाएगा। यदि परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला नहीं है तो 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरुष मुखिया हो सकता है। यदि परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला और 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरुष भी नहीं हो तो परिवार में अधिकतम आयु का कोई भी सदस्य, परिवार का मुखिया होगा। भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 9 मई, 2020 के द्वारा जन आधार कार्ड को परिवार एवं उसके सदस्यों की पहचान, पते तथा संबंध के दस्तावेज के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए सूचीबद्ध किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आयुष्मान भारत महात्मा गाँधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना आदि 171 योजनाओं, सेवाओं के लाभ जन-आधार के माध्यम से हस्तान्तरित किए जा रहे हैं तथा 1 मई, 2022 से राज्य में जन आधार कार्ड को ही राशन कार्ड घोषित कर दिया गया है। भविष्य में सभी जन-कल्याण की योजनाओं के लाभ, सेवाओं को इस कार्ड के आधार पर हस्तान्तरित किया जाएगा।

शेरगढ़ का किला, बारां

बारां जिले में कोषवर्धन पर्वत शिखर पर स्थित जलदुर्ग परवन नदी से घिरे होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से अद्भुत है। यह किला दो भागों में विभक्त है। पहले भाग में शहर पनाह, देवालय, देव प्रतिमाएं, अभिलेख और हवेलियां हैं। दूसरे भाग में दुर्ग की ऊंची प्राचीर, राजपूत शैली के दुमंजिले महल, बारूदघर, तोपखाना, घुड़साल, बावड़ी आदि हैं। शेरगढ़ किले में सोमनाथ महादेव, लक्ष्मीनारायण मंदिर, दुर्गा मंदिर और चारभुजा मंदिर हैं। भव्य राजप्रासाद, हवेली, अमीर खान का महल, सैनिकों के घर, अन्न भंडार आदि शेरगढ़ की भव्यता को बयां करते हैं। किले के पास ही रानी पोखरा नाम का एक तालाब है।

आलेख व छाया: राहुल आसीवाल, सहा. जनसम्पर्क अधिकारी

Postal Regd. No. Jaipur City/413/2023-25
Registered with Registrar of Newspapers of India under R. No. 56175/1991

तस्वीर बदलाव की

राजस्थान सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम और अन्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी
https://jankalyan.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

#DIPRRajasthan

प्रकाशक व मुद्रक – सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशक, पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के लिए, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित
सम्पादक – श्रीमती अलका सक्सेना, मै. कृष्णा प्रिन्टर्स, डी–14, सुदर्शनपुरा, जयपुर से मुद्रित, 'राजस्थान सुजस'–पृष्ठ संख्या 60, लागत मूल्य 30.56 रुपये ● 1,00,000 प्रतियां